हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 फरवरी, 2004

(द्वितीय बैठक)

खण्ड–1, अंक–3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 10 फरवरी, 2004

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)1
वाक आऊट	(3)14
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)14
वाक आऊट	(3)50
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)51

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 10 फरवरी, 2004

द्वितीय बैठक

विधान समा की बैठक, हरियाणा विधान समा हाल, विधान भवन, सेक्टर– 1, चण्डीगढ में बाद दोपहर 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Rao Narender Singh was on his legs when the House was adjorned at 1.30 P.M. He may continue his speech.

राव नरेन्द्र सिंह (अटेली): स्पीकर सर, मैं बिजली के बारे में बता रहा था। खासतौर से इस फरवरी के महीने को देखते हुए जो छात्रों के एग्जाम सिर पर हैं इस विषय पर सरकार को चाहिए कि विशेष रूप से बिजली का इंतजाम अवश्य करे ताकि पढ़ने वाले बच्चो को शाम और सुबह के वक्त पूरी बिजली मिलने की व्यवस्था हो सके। स्पीकर सर, मैं निवेदन करूंगा कि देहात के अन्दर जो माताएं और बहनें रात को और सुबह चक्की चूल्हे का काम करती हैं उस समय भी बिजली होनी बहुत ही आवश्यक है। चाहे उस समय थी फेस की बिजली न देकर सिंगल फेस या दो फेस में दे दी जाए। इससे निश्चित रूप से सब लोगो को फायदा मिलेगा।

स्पीकर सर, किसानों को मैं तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूं। अगर किसान के घर में एक बेटा या बेटी को सरकारी नौकरी में हिस्सा मिलता है तो में समझता हूं कि किसानों के चेहरे पर रौनक आ सकती है और किसान तरक्की कर सकता है। अभिभाषण में जिक्र किया गया है कि 39 हजार नौकरियां सृजित करके दी जायेंगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार इस विषय पर एक श्वेत पत्र जारी करे कि जिलेवार या कांस्टीच्यूशी–वाइज इस सरकार ने कितनी नौकरियां अपने समय में दी हैं। बेरोजगार भाइयों को पुलिस में भर्ती होने के लिए जहां सरकार ने पुलिस के फार्म की कीमत 500 रुपये प्रति फार्म की है यह मैं समझता हूं कि बेरोजगार लोगों के लिए उचित नहीं है। इससे पहले दूसरी सरकारों के समय में यानि 1996 में हमारी कांग्रेस पार्टी के समय इन फार्मों की कोई फीस नहीं होती थी। फिर भी अगर सरकार चाहे तो कोई नोमिनल फीस रख सकती है उसमें चाहे दस रुपये तक सरकार इस फार्म की कीमत रख सकती है। बेरोजगार भाईयो के लिए कम कीमत पर फार्मो की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे पुलिस भर्ती में खडे हो सकें। इसके साथ ही साथ एस०एस० बोर्ड और एच०पी०एस०सी० के जो फार्म हैं उनकी कीमत भी अधिक है। पिछले दिनों मालूम हुआ कि एच.सी.एस. के फार्म की फीस एक हजार रुपये थी। एस०एस०बोर्ड के फार्म भी 250/300 रुपये फीस देने पर मिलते हैं। बेरोजगारों के लिए यह फीस मिनिमन रखनी चाहिये। खासतौर से एस.एस.बोर्ड की जो परीक्षा ली जाती है वह चण्डीगढ़ में ही ली जाती है इसको

भी जिला मुख्यालय पर लिया जाना चाहिये ताकि बेरोजगारों को आने–जाने के समय में बचत हो और उनका पैसा भी बचे।

अभिभाषण में बाजरे की बात कही गई। मै इतना जरूर कहूंगा कि सरकार की कुछ गलत नीतियों की वजह से जो भाव बाजरे का रखा गया वह देरी से रखा गया जिसकी वजह से जो गरीब आदमी थे उन्होंने शादी विवाह के लिए खरीददारी के लिए पैसा चाहिए था इसलिए अपना बाजरा शुरू में ही बेच दिया और बाद मे इसके लिए अफरा तफरी मच गई। राजस्थान का इलाका हरियाणा के महेन्द्रगढ़ु जिले से बोर्डर पर तीन साईड से लगता है।

जब वहां राजस्थान के किसान अपना बाजरा लेकर आ गये तो हमारे वहां के किसानों का बाजरा 20–20 दिन और महीने तक मण्डियों में पड़ा रहा। वहां के किसानों ने रोड भी जाम किया था कि उनका बाजरा नहीं बिक रहा। इस तरह मैं कहना चाहता हूं कि बाजरा खरीदने के लिए सरकार ने कोई उचित व्यवस्था नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कन्यादान की स्कीम लागू की थी। 26 जनवरी से इस स्कीम में बीपीएल. के आधार पर दूसरी जातियों को शामिल किया गया है। यह सरकार का बहुत ही उचित निर्णय है और हमारी भी यह मांग थी कि हरिजनों के अलावा दूसरी जातियो को भी इसमे शामिल किएया जाये जो

बीपीएल. के नीचे है। इस बारे में मैं सरकार से इतना अनुरोध करूंगा कि बीपीएल. का जो सर्वे किया जाये वह ठीक से किया जाये। जिन गरीबों का नाम मौजूदा लिस्ट में नहीं है उसका दोबारा से सर्वे किया जाये। इसके अतिरिक्त मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हरिजन विडोज की लड़कियों को जो 10 हजार रूपये की स्कीम दी जा रही है इस स्कीम में बीपीएल. से नीचे जीवन यापन करने वाले दूसरी जातियों के लोगों को भी शामिल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, बुढापा पैंशन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगस्त, 2002 के बाद कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसका भी सर्वेक्षण होना चाहिए क्योंकि पिछले दो–तीन सालों मे और भी कई लोग 60 वर्ष के हो गये होंगे ताकि उनको भी बुढापा पैंशन का लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, खेल एवं युवा कल्याण के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया है। मैं समझता हूं कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनके लिए सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए जायें। हरियाणा में 30 वाईसीओज को सरप्लस घोषित किया गया है। उनकों दूसरे विभागों में शिफ्ट करके कंट्रैक्ट के आधार पर नये सिरे से रखे जायेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करके इसका सोल्युशन निकाले तो बहुत अच्छा होगा। स्पीकर सर, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है ....

श्री अध्यक्षः नरेन्द्र जी, आप वाईन्ड अप करें।

राव नरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले अखबारों में एक आर्टीकल आया था कि वर्ष 2003 कानून व्यवस्था के लिहाज से हरियाणा के लिए अच्छा नहीं रहा। इस वर्ष प्रतिदिन दो व्यक्तियों की हत्या हुई है। अखबार वाले प्रजातंत्र मे बहुत उल्लेखनीय माने जाते हें। उनमे से भाई प्रमानंद गोयल की हत्या हो गई और इसी तरह से सिरसा मे भी हत्या हो गई थी। सरकार को कानून व्यवस्था ठीक बनाये रखने के लिए उचित कदम उठाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार की घोषणाओं का प्रश्न है, इस बारे में सत्ता पक्ष के भाईयों ने कहा है कि सरकार ने 44 हजार विकास कार्य किए हैं और सरकार का नाम गिनिज बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए। इस बारे में मैं सरकार का ध्यान मेरे हल्के अटेली की दो सड्कों की तरफ दिलाना चाहूगा। गूवानी से सलूनी ब्लोक अटेली में और भुवारखां से डहानी खातियान ब्लोक नांगल चौधरी तक की सड़को की बहुत बुरी हालत है। इन सडकों पर हमारी सरकार के समय में ही काम हुआ था उसके बाद इन पर कोई कार्य नही हुआ है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि 7—8 वर्ष से इन सड़कों पर कार्य नहीं हुआ है कृपा करके इनको बनवाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, नारनौल जिला हैड क्वार्टर है। वहां की जनता की बड़े लम्बे समय से मांग है कि वहां पर बाईपास बनवाया जाये। वहां पर बाई पास न होने के कारण शहर में बहुत

भीड़ रहती है जिससे बहुत सी दुर्घनाए भी होती रहती हैं और एक्सीडेंट मे बहुत से लोगों की जानें भी गई हें। मैंने पहले भी इस बारे में हाउस मे जिक्र किया है कि नारनौल में बाईपास बनाना बहुत जरूरी है लेकिन इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। नारनौल जिला हेडक्वार्टर है इसलिए वहां पर बाईपास होना चाहिए और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

स्पीकर सर, दक्षिणी हरियाणा में यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपको लिखित में दिया था। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि दक्षिणी हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी बनवाई जाये। क्योंकि जिला महेन्द्रगढ़ पिछड़ा हुआ इलाका हैं इसलिए वहां पर यूनिवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। अन्त मे मैं इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करते हुए तथा आपने बोलने के लिए जो समय मुझे दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

डा० रघुबीर सिंह कादियान (बेरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गर्वनर एड्रैस पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। कल गर्वनर साहब ने जो अभिभाषण पढा उस बारे मे मेरे से पूर्व भी एक दो साथियों ने बताया कि गवर्नर साहब बड़े आधे मन से अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। शायद यही कारण है कि अभिभाषण का जो थी फोरथ हिस्सा था उन्होंने यह कह कर नहीं पढ़ा कि यह पढ़ा हुआ समझा जाना चाहिए क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जो सरकार ने पुलिन्दा उनके

हाथों में दिया है और जो सत्य से परे था, पढ़ना ठीक नहीं समझा उनके लिए इस अभिभाषण को पढना एक कन्हीच्यूशनल आब्लीगेशन्ज थी और एक संवैधानिक जिम्मेवारी के तहत वे अपना अभिभाषण यहां पर पढ़ रहे थे। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मै साल पहले यह सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने जो अपना मैनीफैस्टो हरियाणा प्रदेश को दिया था तो उस समय कहा था कि चश्मा लगा कर देखोगे तो बिजली के बिल माफ पाओगे, पानी की उगाही माफ पाओगे और साथ ही साथ सारे प्रदेश में विकास होता हुआ दिखाई देगा।' इस तरह की बातें इस सरकार ने आने से पहले कही थी। अब चश्मा लगा कर देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि देश की आजादी के बाद इस प्रदेश के समाज के सभी वर्ग दुः खी हैं। चाहे वह किसान वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है या और कोई वर्ग है यानि हर वर्ग ने इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ अपना मन बनाया हुआ है। इन्होंने जिस ढग से अपनी बात लिख करके गवर्नर एड्रैस में कही है कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत बहुत काम हुए हैं यह सही नहीं हे। इन्होने उपलब्धियों के नारे पूरे हरियाणा मे सरकारी खर्च से लिखवाए हैं या पार्टी के खर्च से लिखवाए हैं वह ये जानते होंगे। जहां पर सूर्य की किरणें भी नहीं जाती वहां पर भी इन्होंने नारे लिखवा रखे हैं। (विध्न) सरकार या तो दीवारों पर है या अखबारों में है। इस अभिभाषण में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का बड़ा भारी नाम लिया गया है। वैसे तो 'सरकार

आपके द्वार' कार्यक्रम एक औफिशियल दूर हो जाता है क्योकि इसमें बड़े भारी अफसर जाते हैं, एस०पी० और डी०सी० तक वहां पर जाते हैं। न जाने कितना टी०ए०डी०ए० इस कार्यक्रम पर खर्च होता है। इस बारे मे यदि एक व्हाईट पेपर जारी कर दिया जाये तो पता चलेगा कि इस पर कितना पैसा खर्च हो रहा हे। यह सारा खर्च सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम पंचायत, बी०डी०ओ० या एम०एल०ए० ने करने चाहिएं वे सारे के सारे काम मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करके करते हैं कि इस गांव में विकास के लिए इतने पैसे आये। इस पर लोग कहते हैं कि इतने पैसे नहीं आये। इस बारे में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 43 हजार कामों की इन्क्वायरी करवाऊंगा कि उन कामों पर पैसा खर्च हुआ है या नहीं। यह एक बहुत ही चिन्ता का विषय है कि 43 हजार कामों के लिए पैसे आये ओर व खर्च न हो। आखिर वह पैसा किसी की जेब मे चला गया। अब मुख्यमंत्री जी कहते घूम रहे हैं कि बिजली के बिल भर देना। बेरी हल्के में कहते हैं कि वोट नहीं दिया तो विकास कैसा। फिर कहते हैं कि फलां पंचायत ने वोट नही दिया। इन्होंने संविधान की शपथ ली हुई हे और गीता की शपथ ली हुई है कि मैं सारे प्रदेश का विकास बराबरी के आधार पर करूंगा। अब ये कहें कि तुमने वोट नही दी तो यह ठीक नहीं है। सरकार को सभी को एक नजर से देखना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहां पर बेरी में भेदभाव के साथ काम करें तो फिर यह डैमोक्रेसी के अन्दर एक चिन्ता का विषय है।

मुख्यमंत्री जी कहते हैं चश्में पर मुहर लगा देना मैं थारे बच्चों की शादी भी करवाउगा। (विघन) स्पीकर साहब, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, सारी प्रैस मे और हर जगह पर यह बात आई है। इसमें ऑन ऑफिशियल दूर सरकारी पैसा खर्च हो रहा है और सरकारी पैसा खत्म हो रहा है। सरकारी पैसे के दम पर पार्टी का प्रचार किया जा रहा हे और चश्में पर मुहर लगाने की बात कही जाती है। प्रदेश हित में यह एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है और इससे लोकतन्त्र खतरे मे पड़ जाएगा। इस तरह की बातों को हमने सुना था कि कई बार सैंट्रेलाईजेशन ऑफ पावर हो जाता है। .... शराब के ठेकों की नीलामी होती है। (विघन)

श्री अध्यक्षः इनकी भ्रष्टाचार वाली बात रिकार्ड न की जाए।

डा० रघुवीर सिह कादियानः 1800 या दो हजार करोड़ का रैवैन्यू प्रदेश के डिवेल्पमैट के लिए आना चाहिए। जो पैसा डिवैल्पमैंट पर खर्च होना चाहिए वह खर्च नहीं हो पा रहा है। इस ढंग से ऑक्शन करवाई जाती है कि दिखावटी तरीके से ऑडियो और वीडियों फिल्में बनाई जाती हैं ओर दो–दो हजार करोड़ रुपये के ठेके 600–700 करोड़ में दे दिए जाते हैं। स्पीकर सर, इस तरह से हरियाणा प्रदेश की गरीब जनता का जो पैसा है वह सरकार के चहेते लोगों की जेब में जा रहा है यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, किस चीज का ठेका दो हजार करोड़ रुपये का दिया जा सकता है? (विघन)

डा० रघुबीर सिंह कदियानः दारू के ठेको की खुली नीलामी करवाएं। (विघन)

श्री अध्यक्षः क्या आप दो हजार करोड़ रुपये का ठेका लेंगे? (विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियानः मैं नही लूंगा लेकिन लेने वाले और बहुत लोग हैं। (विघन)

श्री अध्यक्षः वैसे ही आपने ऐसा कह दिया। (विघन) नो–नो यह कोई बात नहीं है।

डा० रघुबीर सिह कादियानः स्पीकर साहब, एक–एक ठेके की नीलामी रखते व एक एक जिले की नीलामी रखते लेकिन चार–चार जिलों को एक साथ क्लब क्र दिया गया। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप भी दो–दो हजार करोड़ रुपये के ठेके ले लें। (विघ्न)

डा० रघुबीर सिह कादियानः माईन्ज की ओमान में करप्शन का सैंट्रेलाईजेशन हुआ है। हरियाणा प्रदेश दिल्ली के चारों तरफ है। खानें–जिस ढंग से औने–पौने दामों में अपने चहेतों ओर रिश्तेदारो को दी गई हैं मैं यह कहता हूं कि यदि इसकी सी०बी०आई० इन्क्वायरी हो जाए तो माईन्ज की ऐलोकेशन

में बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। इसमें कम से कम तीन हजार करोड़ का स्कैंडल आपको नजर आएगा (विघ्न) अगर मुख्य मंत्री जी साफ हैं, ट्रांसपेरैंट हैं तो इसके बारे में व्हाईट पेपर जारी करें। यह जो ऑकशन्ज हुई हैं इनके बारे में सी०बी०आई० इन्क्वायरी करवा लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं यह बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार और करप्शन का सैंट्रेलाईजेशन कैसे हो रहा है। यमुना सैंड का ठेका है। ....

श्री अध्यक्षः इनकी यह बात रिकार्ड न की जाए।

डा० रघुबीर सिंह कादियानः मैं प्रभावशाली लोग कह लेता हूं। प्रभावशाली लोग डीसी. के पास गए तो डी०सी० ने कहा कि यह नीलामी तो हो चुकी है इसके अलावा अगर आपने कोई और बात करनी हो तो करें। स्पीकर सर, यह स्टेट एक्सचेकर का मामला है और यह स्टेट के रैवेन्यू का मामला है। यह छोटी बात नहीं है। इस तरीके से रेत और बजरी के भाव दोगुने हो गए हैं। खानों से रोजाना कम से कम तीन–चार करोड़ रुपये लोगों की जेबों मे जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। हरियाणा टैक्स फ्री स्टेट हो सकती है लेकिन जिस ढंग से लूट खसोट का मामला सामने आया हे यह सैंट्रेलाईजेशन ऑफ क्रप्शन है और पॉलिटिक्स के अन्दर हम ऐप्रिहैन्शन कर सकते हैं कि यह लोकतन्त्र की हत्या होगी ओर इससे पोलिटिकल मर्डर भी होंगे। (विष्णो

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, अब आप वाईड अप करें। (विघन) आपको बोलते हुए। मिनट हो गए हैं इसलिए अब आप वाईण्ड अप करें (विघन)।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, क्रप्शन की बात मैंने पहले भी उठाई थी कि पानीपत के सातवें और आठवें यूनिट का सीधा सिंगल फाईल आर्डर है जबकि यह टैण्डर गलोबलाईजोन होना चाहिए था क्योंकि यह दो हजार करोड़ रुपए का मामला था। यह मामला कोई छोटा मामला नहीं था। इसके आर्डर सीधे सिंगल फाईल पर बी.एच.इएल. को दिए गए। बी.एच.इ. एल. के बाद बाम्बे सबरवन मैनेजमैंट को दिया गया। इस कम्पनी के जितने भी परपोजल थे उनको सबमिट किए और सिंगल फाईल पर ये आर्डर किए जाते हैं कि इसको यह काम एलोकेट किया जाता हे। जिस ढंग से यह काम बी०एच०इ०एल० को सबलेट किया गया था तो मैं समझता हूं कि इसमें 600 करोड़ रुपए का घोटाला है।

श्री अध्यक्ष: बी०एच०इ०एल० कहां की कम्पनी है ?

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, मैं कम्पीटशन की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि 15 सौ करोड़ रुपए में इनसे भी कोई अच्छी कम्पनी इस काम को करने के लिए आ जाती। (विघ्न) मैं यह कहना चाहता हूं कि गलोबल टैण्डर होते तो

स्पैसिफिकेशन आती और क्वालिटी भी मेनटेन होती तथा कम्पीटीशन होता।

श्री अध्यक्ष: बी०एच०इ०एल० का पूरा नाम क्या है ?

डा० रघुबीर सिंह कादियान: भारत हैवी इलैक्ट्रीकलस लिमिटिड है। (विघन) स्पीकर सर, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। आप जिस दंग से ....। हमने इतने कालिंग अटैंशन मोशन और एडजर्नमैंट मोशन दिए हैं उनमें से आपने एक भी नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष: इनके ये शब्द रिकार्ड न किए जाएं।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के मेम्बर्ज ने 100 सवाल दिए हैं। मैं चाहता हूं कि उन 100 सवालों को सदन की मेज पर रखा जाए।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप गवर्नर एड्रैस पर बोलें।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, जिस ढंग से 12 संस्थाओं में से जिनमें एच०एस०एम०आई०टी०सी०, हरियाणा वीवर्ज हैण्डलूम, स्माल एक्सपोर्ट कारपोरेशंज इत्यादि हैं इनमें से इम्पलाईज की छंटनी की गई है, यइ ठीक नहीं है। ऐसा करके इस सरकार ने 25–30 हजार इम्पलाईज के पेट पर लात मारी है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह जो रिट्रैंचमैंट हुई है उसको वापिस लेने की बात करें। वे लोग जो

उजड़ गए हैं उनको दोबारा से बसाने का काम यह सरकार करे। अब मैं फार्मर्ज की बात कहना चाहता हूं। इस सरकार के वक्त में फार्मर्ज के ऊपर इतने जबरदस्त अन्याय हुए हैं कि व्यान नहीं किए जा सकते हैं। मैं यह रिकार्ड की बात कर रहा हूं। केन्द्र सरकार ने 1998 के अन्दर एक रुपया डीजल के दाम बढ़ाए थे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने केन्द्र की सरकार से स्पोर्ट वापिस ले लिया था लेकिन उसके बाद जो ये उनके साथ रहे उस समय में 6 रुपए से 22 रुपए लीटर डीजल के दाम चले गए, 3 रूपए से 1० रूपए लीटर तक मिट्टी के तेल के दाम चले गए और 90 रुपए से 190 रूपए तथा 200 रुपए खाद के कट्टे के दाम चले गए। यह सब इनकी सरकार के टाईम मे ही बड़े हैं।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं, आप ठीक बात करें। आप गर्वनर एड्रैस पर ही बोलें।

डा० रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, यह किसानों के ऊपर चोट है।

श्री अध्यक्षः आप इस तरह की बात करके सदन को गुमराह करने वाली बात नहीं करें।

डा० रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, आपकी परमिशन के तहत कहना चाहता हूं कि इन्होंने यह दिखाया है कि इनके चार साल में 4 हजार 625 करोड रुपए रैवेन्यू बढ़ा दिया है। 1999–2000 में 77 प्रतिशत तक रैवेन्यू बढ़ गया है। इसके लिए

यहां पर मेजे थपथपाई गई थीं। यहां पर सम्मत सिंह जी बैठे हुए हैं। ये यह बताएं कि यह जो डैट की लायबलिटी है यह कितनी बढ़ी है, कितने प्रतिशत बढ़ी है। यह 400 प्रतिशत बढ़ी है। यह 6 हजार करोड़ से लेकर 36 हजार करोड़ रुपए तक चली गई है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये जनता को गुमराह करने की बात करते हैं कि इन्होंने मै साल में रेवेन्यू बढ़ा दिया हे।

श्री अध्यक्षः कादयान जी, आप वाईन्ड करे। आपको बोलते हुए 16 मिनट हो गए हैं।

डा० रघुबीर सिह कादयानः अभी तो बहुत सारा सौदा है इसलिए मुझे एक बार इस बारे में बोलने दें। (विघन) आप तो खुली छूट देने वाले आदमी हो इसलिए आप तो ऐसा न करे। (विघन) मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यहां पर एस०वाई०एल० के बारे में बात कहीं गयी। एस०वाई०एल० के बारे में तमाम पार्टियों की मीटिंग हुई थी और उस समय सदन मे इस बारे में एक प्रस्ताव भी पास हुआ था। उसमें सरकार को एस०वाई०एल० के बारे में पूरी ताकत दी गयी थी कि वह अपने लेवल पर इस बारे में जो भी बात करेगी, जो भी स्टैप्स लेगी उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन इस बारे में जो हुआ वह देखने वाली बात है। आज हर आदमी कहता है कि एस०वाई०एल० जीवन रेखा है। एस०वाई०एल० इस प्रदेश के लोगों के लिए जीवन ओर मरण का प्रश्न है। जीवन और मरण का प्रश्न

सही मायनों मे इसलिए है क्योंकि यह पानी उस गरीब किसान के हक का है जो उसके खेतों मे चलना चाहिए लेकिन वह चल कहीं और रहा है। इस बारे में एक प्रस्ताव आया था और हमने आन रिकार्ड यह सुझाव दिया था। 90 एम०एल०एज० और 10 एम०पी० यानी 100 आदमी दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलेगे और ये सौ आदमी दिल्ली से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा में नहीं आ जाएगा। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है लेकिन इस मामले के कारण आज हरियाणा प्रदेश की उस बहादुरी के सामने एक क्वैश्चन मार्क लग गया है। लोग कहते हैं कि हरियाणा के कैसे लोग हैं कि 35–36 साल हो गये लेकिन एस०वाई०एल० का पानी आज तक उनके खेतों में नहीं आ पाया। हमारे हिस्से का वह पानी या तो पाकिस्तान जा रहा है या पंजाब मे जा रहा है। इस तरह से यह तो हरियाणा प्रदेश के लोगों की बहादुरी पर एक क्वैश्चन मार्क लगाता है, हरियाणा प्रदेश के लोगों के स्टेटस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। जिस लाईटली ढंग से इस बारे में सारी बातें ली गयीं वह बहुत ही दुखी करने वाली हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गया तो यह काम पूरा होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों में यह आस जगी थी कि अब एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा में आ जाएगा। राजीव लोंगोवाल समझौते के बेसिज पर यह फैसला आया था इसलिए लोगों में यह आस जगी थी कि अब एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। जब एक साल तक पंजाब सरकार ने यह काम

पूरा नहीं किया तो सैंट्रल गवर्नमैंट को इसकी खुदाई करवानी चाहिए थी। फैसले के अनुसार पंजाब सरकार पर बाइंडिंग नहीं थी लेकिन जब केन्द्र की सरकार के सामने यह बात आयी तो केन्द्र सरकर ने अपने बजट में इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, कोई बजट की ऐलोकेशन नहीं की। स्पीकर सर, केन्द्र की सरकार की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार कोई एजेंसी इस काम के लिए सुझाएं लेकिन कोई भी एजेंसी इस बारे में नहीं सुझायी गयी और न ही कोई सर्वे हुआ। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में दो करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं इसलिए यह तो अब उनके स्वाभिमान का सवाल पैदा हो गया है।

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, अब आप वाईड अप करें।

डा० रघुबीर सिह कादयानः स्पीकर सर, यह हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है इसलिए यहां तो मुझे अपनी बात कहने दें। अगर मैं कोई इररैलेवैन्ट बोल रहा हूं तब तो आप मुझे कह सकते हें 1

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, अकेले आप ही बोलने वाले नहीं हैं बल्कि और भी सदस्यों ने अभी बोलना है। इसलिए अब आप वाईड अप करे।

डा० रघुबीर सिंह कादयानः स्पीकर सर, यह सरकार पूरी तरह से फेल रही है। इसमें जिसकी भी गलती रही है उसको

सजा मिलनी चाहिए। जिस ढंग से सरकार के इस बारे में कदम रहे हैं वह गलत हैं।

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, अब आप बैठें।

डा० रघुबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, अभी तो मेरे हल्के की बातें रह गयी हैं जबकि आप कह रहे हैं कि वाईंड अप कर लो। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की सड़कों के नाम बताना चाहूंगा – डीघल से कलावडु, बेरी से काहनौर, बेरी से महाराना, वाया दुजाना, बेरी से पलड़ा, वाया मांगावास, बेरी से बिसान, दुबलधन से छुछकवास वाया अछेज पहाड़पुर, बेरी से शोरिया, गोछी से इशान, बिशान से बाकरा इनमें सड़कों का नाम निशान तक नहीं है कि यहां कभी सड़कें थीं भी या नहीं। इन सड़कों के बारे में मेरी सदन के नेता से रिक्वेस्ट है कि इन सड़कों के बारे मे बताएं। यहां बोलते हुए किसी सदस्य ने बिजली के बारे में बात की। मेरे हल्के बेरी में चार घण्टे बिजली अल्टरनेट डेज में आती हे।

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्याइंट ऑफ ऑर्डर है। मैं इस महान सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इनके अपने हल्के बेरी मे चौधरी भजन लाल जी के राज में 11 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनी थी और चौधरी बंसी लाल के राज मे एक इंच भी सड़क नहीं बनी और हमारे राज में 27.65 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं।

जहां तक रिपेयर की बात है, रिपेयर पर चौधरी भजन लाल और चौधरी बंसी लाल के राज में एक पैसा भी नहीं लगाया गया और हमारे राज में अब तक 108 लाख रूपया मै साल में खर्च हो चुका

डॉ० रघुबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, तकरीबन 90 फीसदी गांवों मै ट्रांसफार्मर जले पडे हैं। 42 दिन में से ओं दिन नहरें चलती हैं। ऐग्जिस्टिंग मोरियों में पाइप फंसा कर बंद कर दी गई हैं। इतना जबरदस्त अन्याय, इतना जबरदस्त डिस्किमनेशन पानी के बंटवारे के मामले में मैंने कभी नहीं देखा। ....

श्री अध्यक्षः अब आप बैठै। डॉ० रघुबीर सिंह काद्यान की अब कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कृष्ण पाल (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बातें बहुत हैं समय कम हैं और अपनी बात यूं शुरू करूं कि चार साल में इतने जुल्म किए हैं।

श्री अध्यक्षः आप गवर्नर ऐड्स पर बोले। जुल्म की बात बाहर करें।

श्री कृष्ण पालः इतने जुल्म किए हें कि हरियाणा में हम बताना चाहें तो महीनों लग जाएंगे। कृप्या बीच में इटरवीन न करे। आज से चार वर्ष पूर्व हरियाणा के किसान ने, मजदूर ने,

व्यापारी ने, छात्र ने इस सोच पर मोहर लगाई थी क्योंकि चुनाव से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहा करते थे कि हरियाणा में ऐसा राज दूंगा कि किसान का राज दूंगा कि किसान का राज होगा, मजदूर का राज होगा, राम राज होगा, कमेरों का राज होगा, लुटेरे जेलों के पीछे होगे। अफसोस जिन कमेरो ने आज राज पर होना चाहिये था आज वे हरियाणा की जेलों में हैं और जिन्होंने जेलों में होना चाहिये था उनको छोड़ दिया है।

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल जी। आप गवर्नर एड्रेस पर ही बोलें और सब्जैक्ट पर ही बोलें।

श्री कृष्णपालः ये किसानों को कहते थे कि अगर हम सत्ता में आये तो आपको 24 घण्टे बिजली दी जायेगी और सस्ती बिजली दी जायेगी। गन्ने के पूरे दाम समय पर मिलेंगे। किसानो का सम्मान किया जायेगा। कर्मचारियों, छात्रो, बेरोजगारों, व्यापारियों का सम्मान किया जायेगा। लेकिन अफसोस, सब वर्गों ने समझौता होने पर मुहर लगाई थी। उन सब वर्गों की भावनाओं पर इन चार सालों मे कुठाराघात हुआ है उसके बारे मे मैं विशेष तौर से चर्चा करना चाहूंगा। स्पीकर सर, इन चार सालों के दौरान प्रदेश के किसानों, मजदूरो, व्यापारियों, दुकानदारों और उद्योगपतियों के घरों में इस सरकार ने आग लगाई है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि अभी समय है आप जन हित में फैसले कीजिए, किसानों, मजदूरो, कर्मचारियों, व्यापारियों के हित में फैसले कीजिए। लेकिन

सत्ता का नशा ऐसा होता है जो सिर चढ़कर बोलता है। जिसमें किसी का दुख दर्द सुनाई नहीं देता। हरियाणा के हर आगन में आग की चिन्गारी लगी हुई थी हमने कहा था मुख्यमंत्री जी चारो और आग लगी हुई है और तुमने आख मूंद ली हैं लेकिन इस बस्ती में घर तेरा भी है लेकिन सत्ता में नजर नहीं आता था।

श्री बलबीर सिंहः आन ए प्यांयट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि जो विकास के काम इस सरकार के समय मे हुए हैं उतने पिछली सरकार में इनकी हिस्सेदारी थी उसमें नहीं हुए। उस समय इन्होंने क्या किया यह भी बता दें। लेकिन असत्य बात कहने की कोई तुलना नहीं है।

श्री कृष्णपालः मैं तो सत्ता के खिलाफ रहा हूं जो ....

श्री अध्यक्षः जो यह बात कर रहे हैं वह रिकार्ड न की जाये। कृष्णपाल जी एथेंटिक बोले, प्रूफ के साथ बोलें या फिर बैठ जायें।

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्षः एथैटिक बोलें यह कोई स्टेज वाला भाषण नहीं है आप विधान सभा में बोल रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: आन ए प्यांयट आफ आर्डर सर। स्पीकर महोदय, सम्मानित साथी ने अभी नाम लेकर कहा कि यह काम किए हैं। इन लोगों की पिछली सरकार ने क्या काम किए थे ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है। चोधरी बंसीलाल जी के राज में इनकी एक बस चला करती थी उसमें बाकायदा शराब की थैलियां पकड़ी गई थीं और इन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अगर हमारे खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो तो बतायें। इनको तकलीफ इस बात की है कि हमारे चार साल के राज में इनको लूट मचाने की छूट नहीं दी गई इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। अगर इन्होंने कोई बात कहनी है तो यह गवर्नर के अभिभाषण पर कहें। अभिभाषण से बाहर जाकर कोई बात न कहें। बाकी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें अच्छी तरह से इनकी औकात का पता चल जायेगा।

श्री कृष्णपाल: ये सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था

श्री अध्यक्ष: कृष्णपाल जी अनपार्लियामैंट्री शब्द कह रहे हैं वे रिकार्ड न किए जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्णपाल: अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: कृष्णपाल जी अनपार्लियामैंट्री शब्द कह रहे हैं वे रिकार्ड न किए जायें।

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने किसानों को कहा था कि ये किसानो को सस्ती और 24 घंटे बिजली देंगे लेकिन आज प्रदेश मे हालात ऐसे हैं कि किसानों को 5 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिलती और नहरों में महीनों–महीनों पानी नही आता। यदि किसान सरकार से बिजली और पानी की मांग करते हैं तो किसान पुत्र किसानों की पुलिस से हत्या करवाता है और दूसरी तरफ गन्ने की पेमैंट की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि ऐसा राज हरियाणा की जनता को दूंगा कि रात 12 बजे माताएं, बहनें और बहुएं गहने पहनकर घर से बाहर जा सकेंगी। लेकिन ये रात 12 बजे की बात करते थे दिन में 12 बजे भी हमारी मां–बहनों और बहुओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। मौजूदा सरकार के समय में दिन–दिहाड़े बहन–बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। फरीदाबाद में पूजा अग्रवाल की 7जनवरी, 2003 को इज्जत लूटी गई और उसकी लाश सैक्टर–30 के पुलिस लाईन के पास पेड पर लटकी हुई मिली। दो महीने से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन हरियाणा पुलिस उसके हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है। पूजा अग्रवाल के हत्यारे आजाद घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर अपराध और अपराधी दोनों ही मौजूदा सरकार के समय में बढे हैं, कम नहीं हुए। मौजूदा सरकार के समय मे अपराधियों के मन से पुलिस का भय समाप्त हो गया है और बेखौफ होकर अपराध करते हैं। जैसा कि चौधरी भजन लाल जी ने अपनी स्पीच में बताया कि मौजूदा सरकार के समय में जिला कोर्ट से, हाई

कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हुए कैदियों को जेल से बाहर निकाल रही है। अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार ऐसा करेगी तो इससे अपराधियों में क्या मैसेज जायेगा। यदि ऐसा होगा तो अपराधी के मन में पुलिस का भय समाप्त हो जायेगा और अपराध बढेंगे। ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने जेल से आने के बाद दोबारा हत्या की है और वे आजाद घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन हरियाणा के अंदर अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त हो गया है और हरियाणा मे जंगल राज शुरू हो गया है। आज हरियाणा अपराध के लिहाज से नम्बर दो पर है। यह सब इस सरकार के आने के बाद हुआ है। कानून का भय अपराधियों के मन से समाप्त हो गया हे और आज हर रोज लूटपाट, हत्याएं, बलात्कार, चोरी, डैकेती और अपहरण आदि की घटनाएं दिन ब दिन अधिक होती जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन जानता है कि मौजूदा सरकार ने बड़े–बड़े होर्डिंग हर जगह लगा रखें है जिन पर लिखा है कि नेक इरादे निभाये वायदे। लेकिन जब हम जनता में जाते हैं तो जनता हमें कहती हे कि इनकी जगह यह लिखा होना चाहिए बुरे इरादे, भूलाए वायदे। स्पीकर सर, बुरे इरादे इसलिए क्योकि जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है उसको जेल का रास्ता ये लोग दिखा देते हैं। स्पीकर साहब, आज हरियाणा में भय का राज है।

श्री अध्यक्षः श्री कृष्णपाल जी। आप वाइन्ड अप करे।

श्री कृष्णपालः स्पीकर साहब, अभी मैं बोला ही कहा हूं।

श्री अध्यक्षः आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गए हैं।

श्री कृष्णपालः स्पीकर साहब, मेरे पास बोलने के लिए मसाला बहुत है। आप मुझे बोलने के लिए पूरा समय दें। यह सरकार एच.एस. आईडीसी, हैफेड व दूसरी कारपोरेशनों का सरकारी पैसा अपने विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। आज सरकार दीवारों पर अपने नारे लिखवा रही है। अब तो हरेक विद्यालय को 5–5 हजार रुपये इस बात के लिए दिए गए हैं कि उन की दीवारों पर सरकार की उपलब्धियों के नारे लिखे जाएं। इस काम के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है। मैं अब सरकार की नीति और जो नियत है उसके बारे में भी बात कहना चाहूंगा।

प्रो० राम भक्तः आन ए प्यांयट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे सम्मानित साथी ने बहुत ही लच्छेदार भाषा में सदन को गुमराह करने की कोशिश की हे। इन्होंने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार अपनी उपलब्धियों के लिए इन बोर्डज और कारपोरेशन का पैसा खर्च कर रही है। मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की विज्ञापन से संबंधित एक टिप्पणी पर भारत वर्ष के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा है कि सरकार का यह दायित्व है कि वह अपनी उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। ये बेबुनियाद बाते यहां पर कह कर सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें।

श्री अभय सिंह चौटाला: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अभी मेरे साथी ने विज्ञापन की बात की है। कल की रात इलैक्शन कमीशन ने भारत सरकार को यह कहा है कि लोक सभा भंग हो जाने के बाद इस तरह के विज्ञापन नहीं दिये जा सकते तो इस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विज्ञापन तब तक दिए जा सकते हैं जब तक चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तिथि निश्चित नहीं कर दी जाती यानि जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की तिथि निश्चित कर देगा उसके बाद ऐसे सरकारी विज्ञापन नहीं दिए जा सकते। ये उन विज्ञापनों को क्यों भूल रहे हैं जो करोड़ों रुपये के लिए जा रहे हैं। हमने तो वह बोर्ड लगवाये हैं जो काम हमने किए हैं। वाजपेयी जी तो वो बोर्ड लगवा रहें हैं जो काम राज्य सरकारों द्वारा किए गए हैं। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि वहां पर एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या करके कहीं पर सरे आम फैंक दिया गया। मैं कहना चहूंगा कि अभी अटल जी के रिश्ते के पोते को यू०पी० में चलती ट्रेन से फेक दिया। वहां पर ट्रेन भी केन्द्र सरकार की है। यह क्राईम यू०पी० में हुआ है। क्राईम करने वाला क्राईम कर ले अगर सरकार उसके प्रति कोई कौताही करे तो वह ठीक नहीं है। हमारे हरियाणा प्रदेश में इस सरकार के बनने के बाद यदि किसी ने कोई क्राईम किया है तो उसको यहां की पुलिस ने पकड़ने का काम किया है।

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महादेय, अब मैं कर्मचारियो की बात करना चाहता हूं। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद 30 हजार कर्मचारियो को नौकरी से बाहर कर दिया है जिस कारण आज उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। नौकरियों में भी बड़ा भेदभाव बरता जा रहा है। सभी को पता है कि जे०बी०टी० की भर्ती में क्या हुआ, वह केस सी०बी०आई० में चल रहा है। एस०आई० ओर ए०एस०आई० की भी पीछे भर्ती हुई। उस भर्ती में न कद की पैमाईश की गई और न छाती की पैमाईश की गई। ऐसे तीन आदमियों को जो इन्होंने गलत भर्ती कर दिए थे उनको बाद में टर्मीनेट किया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी भर्ती करना ठीक नहीं है। स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा। वैसे तो मुख्यमंत्री जी की इस बात का जिक्र जय प्रकाश जी ने कर ही दिया है। ....

श्री अध्यक्षः इनके ये शब्द रिकार्ड न किए जाएं। (विघ्न)

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय, आज अगर मुख्य मंत्री जी हाउस मे होते तो मैं उनसे कहता। (विघन) अध्यक्ष महोदय, मैं कहने जा रहा हूं कि इन मन्त्रियों को सोन्नाटा कारों की जरूरत नहीं है इनको अधिकारों की जरूरत है जो इनके पास नहीं हैं। इनको अधिकार चाहिएं। (विघन)

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल जी, अब आप बेठें। (विघन) आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है और आपका समय खत्म

हो गया है इसलिए अब आप बैठें। (विघन) धर्मबीर जी, अब –आप बोलें (विघ्न) कृष्णपाल जी, आपको बोलते हुए 22–23 मिनट का समय हो गया है। (विघन) आप अपनी पार्टी का ऐलोट टाईम के मुताबिक ही बोल सकते हैं (विघ्न)

चौधरी भजन लालः स्पीकर सर, ये बी०जे०पी० पार्टी के लीडर हैं (विघन)

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप इनकी क्या सिफारिश कर रहे हैं (विघ्न) कृष्णपाल जी अब आप बैठें। (विघन)

चौधरी भजन लालः स्पीकर सर, मैं यह कहता हूं कि इनको बोलने दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप इनकी सिफारिश न करें और अपनी जगह पर बैठें। (विघन)

चौधरी भजन लालः ....

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें (विघन) कृष्णपाल जी, आप भी अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) ये चेयर की परमिशन के बगैर बोल रहे हैं इसलिए इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए (विध्न एवं शोर)

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, मेरे माननीय साथी श्री कृष्णपाल जी यह कह रहे थे कि मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, कौन सा तोप का गोला है। इनके पास कहने

के लिए कोई बात हो, कोई इग्जाम्पल हो, कोई कमैंट हो तो ये कहें। इन्होंने एक भी ऐसी बात कही हो जो इनसे पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने न कही हो तो ये बता दें। जिन पूर्व मैम्बर्ज ने बोला है उन बातों को दोहराने के अलावा और कुछ कहा हो तो ये बताएं। मेरे बोलने से क्या होता है क्या इसके अलावा और कोई बात कही। स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि आज इनका प्यार कैसे उमड़ रहा है। आज जिस प्रकार से चौधरी भजन लाल जी आपसे रिक्वैस्ट कर रहे थे कि इनको बोलने दिया जाए, क्या ये अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं या लीडर ऑफ ओपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं जब कि लीडर ऑफ ओपोजिशन तो भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हैं और वे यहां पर बैठे हुए हैं क्या ये लीडर ऑफ ओपोजिशन का काम भी कर रहे हैं या ये अपनी पार्टी के टाईम से बी०जे०पी० पार्टी को टाईम दे रहे हैं अथवा ये लोग एक हो गए हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैजोरटी के बलबूते पर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। (विघन) इस प्रकार की बात ठीक नहीं हे।

प्रो० सम्पत सिंहः भजन लाल जी, क्या आपको बी०जे०पी० अच्छी लगने लगी है? (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। धर्मबीर जी, आप कॉन्टीन्यू करे। अगर आप बोलना नहीं चाहते तो मैं दूसरे मैम्बर को बोलने के लिए कहूं। (विघ्न)

श्री कृष्णपाल: अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए। (विघन) कृष्णपाल जी, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) No-No. Please take your seat. (शोर एवं व्यवधान) आप चौधरी भजन लाल जी को मेरे चौम्बर में बुलाकर यह बात सुना देना। (शोर एवं व्यवधान) धर्मवीर जी आप बोलों। (शोर एवं व्यवधान) कृष्ण पाल जी, आपका समय समाप्त है। गया है आप अपनी सीट पर बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नही हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) ऐसे बोलकर आप हाउस का समय खराब कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) ऐसे बोलकर आप हाउस का समय खराब कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) बैठिए—बैठिए। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) धर्मवीर सिंह जी, आप बोले। (शोर एवं व्यवधान) कृष्णपाल जी, आप बैठ जाएं, आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान) आप क्या चाहते हैं? (शोर एवं व्यवधान) आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है और आपका जब कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है तो आप क्यों बोल रहे हैं। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। धर्मवीर सिंह जी, आप बोलें वर्ना मैं नैक्सट स्पीकर को बोलने के लिए कह दूंगा।

श्री धर्मवीर सिंह (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में कल पढा है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इनको तो चुप करवाएं।

श्री अध्यक्षः धर्मवीर जी, आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंहः सर, ये चुप ही नहीं हो रहे हैं। आप इनको चुप करवाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप चेयर की मानते हो या कृष्णपाल की मानते हो। (शोर एवं व्यवधान) उन्होंने कह दिया कि चुप हो जाओ तो आप चुप हो गए। आप नहीं बोलोगे तो मैं नैक्स्ट स्पीकर का नाम लूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

वाक – आऊट

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और न ही मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट वाक आऊट करता हूं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाक आऊट कर गए।)

श्री अध्यक्षः आपको चौधरी भजल लाल जी ने कह दिया कि वाक आऊट कर जाओ इसलिए आप वाक आऊट कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री धर्मवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह को बिठाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः धर्मवीर जी, आप बोलें।

15—00 बजे

श्री धर्मवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कल सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा और उसके बाद सदन के नेता का भी यही विचार था कि यह इस सदन का आखिरी साल है और आखिरी बजट सैशन है। अध्यक्ष महोदय, पिछले चार सालों से सदन के सभी विधायकों की मांग थी और सुझाव दिया था कि एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा के अढ़ाई जिलों में ही चलता है, उसका सही बंटबारा हो। यह मांग पिछले चार साल से सभी मैम्बर्ज करते रहे हैं। लेकिन पिछले चार सालों में इस बारे में सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है। अब इन्होंने सिरसा और फतेहाबाद में 106 करोड रुपए दिए हैं जहां पर आलरेडी ज्यादा पानी होने की वजह से सेम आ चुकी है। इसके दूसरी तरफ दक्षिणी हरियाणा है जहां पर लोग पानी की वजह से प्यासे हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि भाखड़ा नहर कमान क्षेत्र के विकास कार्य 319.46 करोड रुपए की लागत से शुरू किए जा रहे हैं, इसके अन्तर्गत 8 जिलों से सम्बन्धित 2.39 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र के खालों को

पक्का किया जाएगा। जबकि बाकी प्रदेश मे एम०आई०टी०सी० के खाले टूटे पड़े हैं। (विघन) इस खालों की रिपेयर के लिए पैसा नहीं दिया। यह पैसा इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि अब वह डिपार्टमैंट खत्म किया जा चुका है।

अब में माईनिंग के बारे में कहना चाहूंगा। माईनिंग डिपार्टमैंट का अभिभाषण में उल्लेख है। इस सरकार ने पिछले दो सालो चाहे वह खानक के पहाड़ की बात हो, चाहे वह निगाणी के पहाड़ की बात हो या चाहे वह अटेला के पहाड़ की बात हो, हर रोज नकली रसीद लेकर माईनिंग करवायी है। पहले हरियाणा के निवासी पांच रूपये फुट के हिसाब से बजरी लेकर जाते थे लेकिन अब वहां पर ज्यादा दाम पर बदमाश लोग लूट मचा रहे हैं। इस तरह से कुछ लोगों ने प्रदेश के करोड़ों रुपये लूट लिए इसलिए इस लूट से लोगों को बचाया जाए। इसी प्रकार से सडकों की बात है पिछले कई सालों से कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बना तो दीं लेकिन उनके ऊपर घटिया मैटीरियल लगाया गया इसलिए वे टूट गयीं लेकिन फिर भी वहां पर टोल टैक्स लिया जाता है। वह पैसा कहां जाता है, वह पैसा राजनैतिक लोगों के पास जाता है।

इसी तरह से कृषि के बारे में मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक तरफ तो ये अपने आप को किसान की सरकार मानते हैं वहीं दूसरी तरफ किसान को जो कोपरेटिव बैंक्स की तरफ से लोन मिलता है उसके ऊपर बारह परसैंट से. ज्यादा ब्याज लिया जाता है। इसमें एक परसैंट हरको बैंक खाता है, तीन

परसैंट सैंट्रल बैक को मिलता है और तीन परसैंट सोसायटीज खा जाती हैं। कृपा करके जो पैसा नाबार्ड से पांच परसैंट पर मिलता हे उसी हिसाब से गरीब किसान को भी पैसा उपलब्ध करवाया जाए। एक तरफ तो सरकार कहती हे कि पैसे की खजाने में कमी नहीं है फिर भी पहली बार हम देखते हैं कि मौजूदा सरकार बनने के बाद इन चार सालों में एक भी महीना ऐसा नहीं गया जिसमें रिकवरी बंद हुई हो। किसान फसल के समय तो पैसा दे सकता है लेकिन सूखे के समय, बाढ़ के समय वह अपना कर्ज नहीं दे सकता लेकिन इस सरकार के द्वारा उनसे ऐसे समय में भी रिकवरी जारी रहती है।

इसी तरह से मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। तीस जून को डी०पी०ई०पी० प्रदेश से खत्म हुई और हमें हैरानी इस बात की है कि तीस जून को भी चार करोड़ रूपये से ज्यादा फिजूल पैमेंट की गयी। यानी यह सारी की सारी नहीं तो कम से कम आधे से ज्यादा बोगस थी। जो झूले दिए हुए दिखाये गये वह एक भी स्कूल में नहीं भेजे गये। जहां पर हैड मास्टर्ज ने आपत्ति की तो वहां पर यह दिये गये। सहमति के बाद भी आधे स्कूलों मे झूले नहीं पहुंच पाए। इसी तरह से नौकरी की बात आती है। प्रदेश के अंदर जिन्होंने आई०टी०आई० या जे०बी०टी० कर रखी हे तो उनके बारे में हमने कभी नहीं सुना कि वे ठेके पर लगाए जाएंगे लेकिन मौजूदा सरकार ने दो साल से जिला परिषद् के नाम पर केवल पांच हजार रूपये फिक्स के हिसाब से इनको

लगाने की व्यवस्था की है। इनको पता है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने केवल वोट लेने के लिए जो यह नया अनुभव किया है उसको खत्म किया जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे भिवानी के इलाके के जितने कालेजो के लड़के थे उनकी पहले रोहतक यूनिवर्सिटी थी और उनको केवल चालीस किलोमीटर दूर ही जाना पड़ता था लेकिन इस सरकार के द्वारा उनको सिरसा यूनिवर्सिटी के साथ इसलिए जोडा जाता है कि वे सिरसा के दरबार में अपनी हाजिरी लगा सकें। मेरी मांग है कि वहां के कालजों को दोबारा से रोहतक यूनिवर्सिटी के साथ जोडा जाए।

इसी तरह से शराबबंदी के नाम पर यहां पर काफी कहा गया है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में सैंट्रलाइज शराब का ठेका किया गया है उसके अंदर भी देखेगे कि एक तरफ पुलिस प्रशासन जहां क्राईम रोकने के लिए बनाया गया था लेकिन आज मैं बाई नेम बता सकता हूं कि शराब के ठेकेदार के साथ मिलकर इस हरियाणा प्रदेश की पुलिस के सिपाही, थानेदार असली नकली वर्दी पहनकर शराब बिकवाते हैं। मैं भिवानी के दो आदमियों के बारे मे बताना चाहूंगा। एक वेदपाल जोकि पब्लिक हैल्थ विभाग में फोर्थ क्लास कैटगरी में लगा हुआ है, पाले राम जिनके पास तोशाम पुलिस से चार–चार सिपाही दिए गए है। तनख्वाह सरकार देती है और वे बदमाश चार–चार सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, प्रदेश का खजाना न लूटा जाए। (इस

समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री पूर्ण सिंह डाबडा पदासीन हुए।)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हैल्थ के नाम पर काफी पैसा खर्च किया दिखाया गया है। प्रदेश की सवा दो करोड से ज्यादा जनसंख्या है और उनको तीन रूपये उन्नीस पैसे की दवा प्रति व्यक्ति प्रति साल मिलेगी। एक साल में एक एक दिन का निकाल तो एक नया पैसा भी नहीं आता। केवल मात्र साढ़े पांच करोड की दवाईयां खरीदी जाएंगी। बी०जे०पी० के साथी चले गए, बैठे होते तो बताता कि केन्द्रीय हैल्थ मंत्री ने कहा कि ऐसा घपला पकड़ा गया है कि सारे देश में नकली दवाईयां जाती हैं ऐसे में बीमार लोग कहां जाएंगे। रंगा साहब बैठे हुए हैं। बड़ा प्रचार करते हैं। खासकर था हत्याओं के बारे में बताना चाहता हूं कि सरकार की शह पर भिवानी में प्रभात अन्टर्रासाउंड वाला खुले आम टैस्ट करता है और वहां के लोग भी यही कहते हैं कि केवल प्रभात अन्ट्रासाउंड वाला ही देख सकता है क्योंकि वह खुलेआम कहता है कि मुझे ऊपर पैसे देने पड़ते हैं। (विघन)

श्री सभापतिः आप वाइंडअप कीजिए।

श्री धर्मबीर सिंहः सभापति महोदय, मैं वाईंडअप करता हूं। जिस प्रकार से सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं इस बारे मे मैं केवल भिवानी का उदाहरण देना चाहता हूं। करोडीमल पार्क के साथ 7–8 एकड जमीन जिस पर सी.एम.ओ. का रेजीडेंस,

ज्यूडीशियल आफिसर्स का रैजीडैंस है, उस पर भी कब्जा करके मकान बनाने शुरू कर दिए। अगर यही हालात रहे तो प्रदेश की सारी जमीन चली जाएगी। रोहतक रोड भिवानी में जहां कबाड़ का काम करने वाले और लुहार रहते थे वहां पर कब्जा करके दुकानें बनानी शुरू कर दीं। कृपा करके ऐसी चीजों की इंक्वायरी की जाए।

सभापति महोदय, बिजली के मामले में सरकार का प्रचार है कि 12 घंटे बिजली देते हैं। हकीकत यह है कि गांवो में 6 घंटे बड़ी मुश्किल से बिजली आती है और जो आती है वह भी टिमटिमाती हुई आती है और उसमें बच्चे नहीं पढ़ सकते। 400 रुपये का मीटर लगाकर 1300 रूपये में दे दिया और जब चुनाव नजदीक आने लगे तो कह दिया कि 650 रुपये में देंगे।

श्री सभापतिः आपको यह पता होना चाहिए कि इलैक्ट्रानिक्स की चीजें सस्ती होती जा रही हैं।

श्री धर्मबीर सिंहः सभापति महोदय, मैं वही कहना चाहता हूं जो सिंगल फेस के कनैक्शन हैं उनसे तो आप 750 रुपये ज्यादा लेते हैं और जो फ्लैट रेट के हैं उनका 350–450 रुपये का खर्च आता है इसके बारे में आप सरकार को आदेश दें। आज ही के ट्रिब्यून में खबर छपी है कि चार साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बार भी नहीं बोले, पहली बार मुंह खोला कि इस साल केन्द्र सरकार का बजट किसान विरोधी है। सभापति महोदय,

अब मैं ट्रांसपोर्ट की बात कहना चाहता हूं। इसमें ये नयी पोलिसी लेकर के आए है। मैं रूट बता सकता हूं जिन रूट्स पर बसें चलती है। जिनकी प्राइवेट बसें है उनकी एक बस के बदले में 4–4 बसें चलती हैं। अपने आदमियो को फायदा देने के लिए बगैर टैक्स दिए चलती हैं, उनका भी पता कीजिए। अकेले भिवानी में ही नहीं सब जगह यही हो रहा है। डी०टी०ओ० और ए०टी०ओ० के नाम से नकली अधिकारी लगा दिए। इनकी यह सोच है कि किसी तरह से इस प्रदेश को उजाड़ा जाए।

सभापति महोदय, मैं केवल एक ही किस्म की नौकरी की बात कहना चाहता हूं। पीछे सब इन्सपैक्टर की भर्ती हुई तो पहली बार यह देखते हैं कि सरकार का यह कहना कि एस०सीज०, बी०सीज० के पूरे कंडीडेट पूरी तरह से सही नहीं पाये गये और उनके लिए रिएडवर्टाइज की गई। एडवटाईज केवल इसलिए की जाती है कि राजपूत की जनसंख्या साढ़े आठ प्रतिशत है और हमें शर्म आती हे यह कहते हुए कि राजपूत का एक भी कंडीडेट पुलिस के सब–इन्सपैक्टर की भर्ती के लिए सही नहीं मिला यह कहां का न्याय है।

श्री सभापतिः आप वाईंड अप कीजिए आप दूसरे सदस्यों का टाइम भी यूज कर रहे हें।

श्री धर्मबीर सिंहः सभापति महोदय, अब मैं मण्डियों में बाजरे और गेहू की खरीद के बारे में बताना चाहूंगा। इस पर 76 करोड़ रूपया कहां पर खर्च किया गया।

श्री सभापतिः आप राजपूत वाली बात क्लीयर करें।

श्री धर्मबीर सिंहः यह कहां का न्याय है कि पूरी भर्ती में एक भी राजपूत नहीं मिले।

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह): चेयरपर्सन महोदय, सारी भर्ती कैटेगरीवाइज की गई है। (विघन) चेयरपर्सन महोदय, इनको मालूम होना चाहिए कि भर्ती कैटेगरीवाईज होती है कोई जाति विशेष की नहीं होती। जेसे जनरल कैटेगरी, एससी., एससीबी, बीसी.ए., बीसीबी और एक्स सर्विसमैन लेकिन जाति विशेष की कोई भर्ती नहीं होती। माननीय साथी न जाने क्यों राजनीतिक शोशा छोडना चाहते हैं। ये इस तरह की बात स्टेज पर कहते होंगे। जब किसी विशेष कैटेगरी का कोई कंडीडेट उपलब्ध नहीं होता तो बाकायदा उसके लिए दोबारा से एडवर्टाइजमैंट की जाती है और प्रत्येक कैटेगरी की अपनी एक मेरिट होती है। एक कैटेगरी विशेष की मैरिट होती है अगर उसमे चाहे पांच पोस्टें हैं तो पांचों कंडीडेट एक कैटेगरी विशेष के भी हो सकते हैं और अलग–अलग भी हो सकते हैं। माननीय सदस्य को ऐसी अनर्गल बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री धर्मबीर सिंहः एससी. और बीसी का कोई कंडीडेट नहीं मिले यह कैसे हो सकता है ?

श्री सभापतिः आपका बैक लीग तो इस सरकार ने पूरा किया है।

प्रो० सम्पत सिंहः चेयरपर्सन महोदय, अगर एक केटेगरी का आदमी इलीजिबल नहीं होता है तो उस पोस्ट को दोबारा से एडवर्टाइज किया जाता है माननीय साथी इस बात को साबित करें। उस पोस्टों को दूसरी कैटेगरी में कंवर्ट नहीं किया गया है बाकायदा दोबारा से विज्ञापित किया है। रिजर्वेशन पोलिसी का पीछे से लगभग 600 की नौकरियों का बैकलॉग इस सरकार ने पूरा किया है और जो भी बैकलॉग बकाया है उसको यह सरकार पूरा करेगी।

श्री सभापतिः धर्मबीर जी, वाईड अप कीजिए। (विघन)

श्री धर्मबीर सिंहः चेयरपर्सन महोदय, पिछली बार जब गेंहू की खरीद हुई उस समय एक बोरी को सड़क तक उठाने के दो रूपये दिये जाते थे लेकिन इस सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए 14– 14 रुपये प्रति बोरी सड़क तक पहुंचाने के लिए दिये हैं जिससे 76 करोड़ रुपये का सरकार को नुकसान हुआ है। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि सरकार इन गलत नीतियो पर कंट्रोल करे।

श्री सभापतिः धर्मबीर जी, वाईड अप कीजिए। (विघन)

श्री धर्मबीर सिंह: सभापति महोदय, अब मैं सोशल वैलफेयर के बारे में कहना चाहूंगा कि जब हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से लंगड़े और अंधे व्यक्ति है जिनकी अब तक पैंशन नहीं बनी है। वे लोग अपनी पैंशन बनवाने के लिए दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन उनकी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस बारे में सरकार हिदायतें जारी करे कि जो भी विकलांग है उनकी पैंशन बनाई जाये।

नगर एवं ग्राम आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): सभापति महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। सभापति महोदय, माननीय धर्मबीर जी कांग्रेस पार्टी में ही थे ओर चौधरी भजन लाल जी 1991 से 1996 तक मुख्यमंत्री रहे। हमारी पार्टी की सरकार जाने के बाद उस दौरान इन लोगों ने पैंशन देने के लिए मापदण्ड रख दिए थे। इन्होंने पांच एकड़ वाले किसान की पैंशन काट दी थी, जिस किसी का बेटा सरकारी नौकरी में था उसकी पैंशन काट दी थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि कोई कहीं से दो पैसे कमाता था तो उसकी पैंशन इन लोगो ने काट दी थी। यह रिकार्ड की बात है और अब ये 'खुद मियां फजीहत और को नसीहत' वाली बात कर रहे हैं 1 (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिह: सभापति महोदय, अब हमारी सरकार आने पर 300 रुपये पैंशन देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः धर्मबीर जी, आप वाईड अप करें।

श्री धर्मबीर सिंहः सभापति महोदय, मौजूदा सरकार के समय में जो ठेके सड़कों के और पब्लिक वर्क्स के दिए गए हैं वे इन्होंने अपने चहेतो को दिए हैं। आज के दिन हरियाणा में कानून व्यवस्था जितनी खराब है इतनी खराब पहले कभी नहीं हुई थी यही कारण है कि आज स्कूलों मे अध्यापकों को तनख्वाह न देकर हेंको में उनकी तनख्वाह भेजी जा रही है।

श्री सभापतिः यह तो अच्छी बात है कि बैंको में तनख्वाह दी जा रही है। दूसरे देशों में भी तनख्वाह बैंको में ही दी जाती है। इस बात के लिए तो आपको सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए।

प्रो० सम्पत सिंहः सभापति महोदय, धर्मबीर जी ने बैंको का जिक्र किया। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पिछले सालों मे बहुत सी फाइनैंशियल कम्पनीज खुल गई हैं और उनमें से बहुत सी कम्पनीज लोगो के करोड़ो रुपये लेकर भाग गई तथा जो ब्याज का रेट है वह 3 रुपये सैंकड़ा के हिसाब से है यानि 36 प्रतिशत ब्याज पर लोगों को पैसा उन कम्पनीज से मिलता है। आज के दिन धीरे-धीरे पैसा सर्कुलेशन में आया है। बैंक पालिसीज की वजह से जो पैसा आ रहा है उसी की वजह से आज हम ग्लोबल लैवल पर कंपीट कर रहे हैं। पैसा बैंक्स में आने की वजह से सर्कुलेशन बढ़ा है और ब्याज दर मे कमी आई है। इससे

आम जनता को फायदा हुआ है। इसके अतिरिक्त बैंको मे पैसा सेफ भी है। सभापति महोदय, घटनाएं कभी घट सकती है उस पर किसी का जोर नहीं चलता। अपराध के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, अपराध पर पूरी तरह से न किसी ने कंट्रोल किया है और न ही हो सकता है। हमने तो सेफ्टी के लिहाज से बैंक से सेलरी देने का प्रोविजन किया है और पैसे का सर्कुलेशन बढ़ा है।

श्री धर्मबीर सिंहः सभापति महोदय, अब मैं विधान सभा के बजट के बारे में कहना चाहूंगा। हीरा नंद आर्य जो कि पूर्व विधायक हैं उन्हें ब्रेन ट्युमर की बीमारी है। उन्होंने कई दफा अपने इलाज के लिए विधान सभा में लिखकर दिया है लेकिन उसे पैसे नहीं दिए गए और उसे लिख दिया गया कि अभी पैसे नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह वह मर जायेगा तब उसको पैसे दिए जायेंगे।

प्रो० सम्पत सिंहः सभापति महोदय, यह बिलकुल गलत स्टेटमेंट है।

श्री धर्मबीर सिंहः सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी की चिट्टी उसके पास गई है।

प्रो० सम्पत सिंहः समापति महोदय, पैसे की वजह से किसी का कोई बिल पैंडिंग नहीं रहता। हो सकता है कि उनके केस मे बिल कंपलीट न हो या किसी अथोराइज्ड होस्पिटल से उसने इलाज नहीं करवाया हो। बिल एथेनटीकेट कराने पड़ते हैं,

वैरीफाई कराने पड़ते हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको पैसा नहीं मिला लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी का बिल पैंडिंग रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री धर्मवीर सिंहः सभापति महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि डीजल पर केन्द्र सरकार ने जो 1.50 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया है उस पर हरियाणा सरकार सेल्वटैक्स हटा ले क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ने से किसान पर बहुत भार पड़ा है। अन्त में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़): परम आदरणीय चेयरमैन सर, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया उसके लिए मैं तहेदिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय चेयरमैन सर, महामहिम राज्यपाल ने संवैधानिक परम्पराओ को निभाते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से अभिभाषण के माध्यम से उपलब्धियां गिनाने का प्रयास किया है। चेयरमैन सर, प्रजातंत्र में इस तरह से सरकार द्वारा प्रेषित अभिभाषण आमतौर पर राज्यपाल महोदय पढ़ कर सुनाते हैं और इसके अन्दर जो आकड़े दिए जाते हैं वे जमीनी हकीकत की सच्चाई से दूर होते हैं। आप इस सरकार के बनने के बाद के इनके 3–4 अभिभाषणो को उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शब्दों के हेरफेर के अलावा और कोई कुछ हकीकत

नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर जनस्वास्थ्य के सम्बन्ध में अपनी बात कहना चाहता हूं। जिस प्रदेश का वातावरण स्वच्छ व साफ न हो और जहां पर लोगो को पीने का पानी मिलना संभव न हो तो वहां पर लोगो का रहना दुभर हो जाता है। हमारी सरकार ने अपने अभिभाषण में पीने के पानी का लक्ष्य 40 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति निर्धारित किया है जबकि इन्हीं की सरकार के वर्ष 2002 के अभिभाषण के अन्दर यह मात्रा 55 लीटर से बढ़ा कर 70 लीटर का लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है। 57 साल की आजादी के बाद आज भी लोग ऐसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार इतने वर्षो के बाद भी अपने प्रदेश के लोगों को स्वच्छ हवा और पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही। चेयरमैन सर, इस संदर्भ मे मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक तो हमारा जिला महेन्द्रगढ़ एट नारनौल है। इसकी वजह से भी हमें पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दूसरी तरफ सरकार ने वहां पर ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं जिस वजह से वहां की म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों को पिछले दो महीने से वेतन भी नहीं मिल रहा है। यानि कमेटी के पास अपने कर्मचारियों को पे देने के लिए पैसे भी नहीं है जब कमेटी के पास पैसे ही नहीं हैं तो फिर वहां की कमेटी से दूसरी मांग करना बेमानी है। महेन्द्रगढ़ की सड़कों की बहुत बुरी हालत है। वहां पर नालियों में गन्दा पानी सीवरेज का उगलता हुआ नजर आयेगा और ढेर सारे सुअर और गधे वहां पर

घूमते नजर आएंगे जिस कारण वहां पर गन्दगी का ढेर होता जा रहा है। वहां पर किसी वक्त कोई महामारी हो जाये तो उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरे हल्के में एक कस्बा है, पहले वहां पर तृतीय श्रेणी की नगरपालिका होती थी उसको अब पंचायत में तबदील कर दिया गया जबकि सरकार दूसरी तरफ 6 शहरों में निगम बनाने जा रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो सुविधाएं दे रही है जबकि मेरे क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं को सरकार वापस ले रही है। मेरे क्षेत्र में कनीना एक कस्बा था और आजादी से पहले वह सब तहसील भी थी लेकिन इस सरकार ने जो वहां पर तीसरे दर्जे की कमेटी थी उसको भंग कर दिया और उसे पंचायत का दर्जा दे दिया। अब वहां पर न तो पंचायत की तरफ से काम हो रहा है और न ही सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है। वहां की हालत बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर सरकार तुरन्त कार्यवाही करते हुए लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये।

चेयरमैन सर, अब मैं स्वास्थ्य से संबंधित बात कहना चाहूंगा। यदि किसी प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वहां पर वातावरण भी अच्छा होगा। आज स्वास्थ्य के नाम पर अस्पतालों में सुविधाएं देने की बात की जाती हैं लेकिन असल में वहां पर कुछ हो नहीं पा रहा। मेरे सामने स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, मैंने उनको भी अपने हल्के की समस्याओं के बारे में कई बार कहा है। आज सरकारी अस्पतालों मे या तो दवाइयां नहीं है या

फिर डॉक्टर्ज नहीं हैं। डॉक्टरों द्वारा इतनी महंगी दवाइयां लिख दी जाती हैं जिन्हें खरीदना आम आदमी के बस में नहीं है। जहां तक जांच की बात आती है तो जिनके पास क्लीनिक्स हैं उनके पास मरीजों को जांच के लिए भेजा जाता है और उनसे मोटी और भारी रकम अदा करवा के उनकी जांच करवाई जाती है। यह प्रदेश के नागरिकों का शोषण है। वहां पर किसी का इलाज नहीं होता, ये अस्पताल केवल एम०एल०आर० काटने के केन्द्र साबित हो रहे हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि वक। से पहले इनका इलाज कर ले वरना तो आने वाले समय में इनको भुगतना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं यह बात निश्चित तौर पर सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। सभापति महोदय, ये लोग बात करते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। औद्योगिकीकरण की तीव्रता के बावजूद भी हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर करती है। यहां के लोगों की आजीविका कृषि है और यहां के मुख्य मन्त्री महोदय किसान के बेटे हैं, किसानों के नेता हैं और किसानों को सत्ता की सीढ़ी बना कर सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं लेकिन आज वे सत्ता के मद के अन्दर चकाचौंध हैं जिन्हे किसानों की समस्याएं नजर नहीं आती हें। ये वही व्यक्ति हैं जब मण्डियाली के अन्दर किसान आन्दोलन चल रहा था तो इन्होंने सब के बीच कहा था के ऐ किसानों अगर मैं सत्ता के अन्दर आया तो आपको 24 घण्टे बिजली दूंगा और वे समस्याएं जिनसे आप जूझते रहे हैं उनका समाधान करुंगा। अफसोस इस बात का है कि मुख्य मन्त्री बनने के बाद इनको कुछ भी याद नहीं है। प्रजा को हरा चश्मा उतारकर

देखिए, आज उन सब को भुला दिया गया है और एक ऐसी पार्टी के साथ गठबन्धन करके सत्ता प्राप्त की जिनका किसानो के साथ कोई भी हित जुड़ा हुआ नहीं है। जब उस पार्टी की सरकार ने बिजली, डीजल और खाद के भाव इतने बढ़ा दिए जिससे किसानों की कमर टूटती नजर आई तब भी इस पर ये रहस्यमयी चुप्पी साधे रहे। आज उनसे इनका मन मुटाव हुआ है। दो राहों पर चलने का प्रयास किया जा रहा है और दोनों को ही सरकार का कल्याण नजर आ रहा है। मै आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि एक शायर ने ठीक ही कहा है– 'जब दिया रंज बुतां ने तो खुदा याद आया। ' सभापति महोदय, आज से पहले ये कहां गए थे आज से पहले इन्होंने किसान के हित की बात क्यों नहीं की। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है कि हरा चश्मा उतार दें। आज प्रदेश की जनता शीशे की तरह बिलकुल साफ देख रही है, वरना आने वाले समय में उनकी सब हकीकत को व्यान करके बता देंगे चेयरमैन साहब, जहां तक शिक्षा का सवाल है, में यह कहना चाहता हूं कि इस शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार शिक्षा संस्थान स्थापित कर रही है और एक ही जिले के अन्दर तीन–तीन विश्वविद्यालय केवल घोषित ही नहीं किए गए हैं बल्कि बना दिए गए हैं वहीं पर मैडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज और डेन्टल कॉलेज खोल दिए गए हैं दूसरी तरफ दक्षिणी हरियाणा में पांच छः जिले आज भी एक विश्वविद्यालय की बाट जोह रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह भेदभाव नहीं होना चाहिए हमें

इस सुविधा से क्यों वंचित रखा जा रहा हे। मुझे इस बात का अफसोस है कि सरकार भेदभाव कर रही है। चेयरमैन, सर मैं आपके माध्यम से अपनी भावनाएं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान करे और जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उनका समाधान करने के लिए काम करे। (विघन)

श्री भागी रामः सभापति महोदय, मेरा प्यांयट ऑफ आर्डर है। अफसोस तो हमे इस बात का है कि ये रोज तो इस सरकार से काम लेते हैं और यहां पर आ कर सरकार की मुखालफत करते हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

राव दान सिंहः चेयरमैन सर, सरकार का काम ही काम करना है इसमें कोई अहसान की बात नहीं है। (विघन) हमें जनता ने अपने काम करवाने के लिए ही यहां पर चुन कर भेजा है। हमें चुप रहने के लिए जनता ने नहीं भेजा है।

श्री सभापतिः भागी राम जी, अपनी सीट पर बैठें। दान सिंह जी, आप भी टू दि प्यायंट बात करें।

राव दान सिंहः सभापति महोदय, जहां तक सवाल है सिंचाई का, हमारे दक्षिणी हरियाणा के अन्दर सिंचाई के बहुत बडे साधन नहीं है। हमारे यहां पर मात्र बिजली से चलने वाले टयूबवैल्ज हैं जहां चारों तरफ बिजली की आपूर्ति के लिए देखा जाता है। चौबीस घण्टे हमारी नजर बिजली पर रहती है। जहां 24

घण्टे बिजली मिलनी चाहिए वहां हमें मात्र 5 या 6 घण्टे बिजली मिलती है और उस समय के अन्दर भी बिजली कभी आती है और कभी जाती है। आज छात्रों की पढ़ाई का समय है और रात के समय में बिजली का कट लग जाता है और छात्र अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। चेयरमैन सर, में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी बिजली की आपूर्ति की जाए और खासतौर पर शाम के समय जब छात्रो की पढ़ाई का समय होता है उस समय बिजली का कट न लगाया जाए। सभापति महोदय, एस०वाई०एल० इस प्रदेश की जीवन रेखा है यह कटु सत्य है लेकिन सारी बात सब ज्यूडिस है कह कर हम इस पर जिक्र नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा कि आज भी हमे जो पानी मिल रहा है उसमे हमारा इक्विटेबल शेयर नहीं मिल रहा है। इक्यिटेबल डिस्ट्रिब्यूशन हमें नहीं मिल रहा है। हमारे सब भाईयों ने मांग उठाई है और यह इलाके की भी मांग है कि आज वर्तमान में जो पानी मिल रहा हे उसमें हमें अपना पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। सभापति महोदय, जहां तक विकास की बात आती है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा को चारों तरफ से बोर्डज से बांध रखा है और बोर्डज पर लिख रखा है कि 'सरकार आपके द्वार'। इस विषय मे मैं यह कहना चाहूंगा कि आज मेरा हल्का महेन्द्रगढ 'सरकार आपके द्वार' के तहत जो पैसा मिलना चाहिए था और जो विकास वहां पर होना चाहिए था उससे वंचित रह गया है। वहां पर कोई भी काम नहीं हुआ है और जो पैसा वहां पर मिलना चाहिए था वह नहीं

मिला है। आज दिल्ली हरियाणा के तीन जिलों सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद से धिरा हुआ है और बाहर से आने वाला हर इन्डस्ट्रीलिस्ट यहां पर उद्योग खोलना चाहता हे लेकिन सरकार के रैड टेक्ज्यम की वजह से वह उद्योगपति हैदराबाद और बैंगलोर की तरफ चला जाता है। अगर सरकार रैड टैपिज्म की तरफ से ध्यान हटाकर उनकी तरफ ध्यान देगी तो हरियाणा में काफी उद्योग लग सकते हैं। सभापति महोदय, हरियाणा में जो लेबर काम करती हे उनमें से 70 फीसदी के करीब लेबर बिहार और उत्तर प्रदेश की है। हमारे लोगों को यह कह कर डिस्कवालीफाई कर दिया जाता है कि तुम लोकल हो। सरकार को इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि हमारे लोगों को नौकरियां मिल सकें। सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने सदन में पढ़ा है यह मात्र सरकार के लिखे हुए शब्द हैं जो कि सच्चाई से बहुत दूर हैं। अगर वक्त रहते हुए इन बातों को नही सुधारा गया तो आने वाले समय में सरकार को पता चल जाएगा। धन्यवाद।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह (जुलाना): सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। गवर्नर साहब ने जो .अभिभाषण दिया है मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि न तो मैं किसी के बोलने के वक्त बीच में बोलता

हूं और न ही मुझे बीच में टोका जाए। सभापति महोदय, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और किसानों के हितों को ध्यान में रखने वाला प्रदेश है। हरियाणा के गांवों में मजदूर और किसान रहता है और वह खेतों पर ही अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर करता है। जब से यह सरकार रही है तब से यह सरकार किसानों और मजदूरो के साथ अनेक वायदे करती रही है और कहती रही है कि हम किसानों को सभी फायदे देंगे। अब हम बोर्ड देखते हैं जिनपर यह लिखा रहता है एक व्यक्ति अनेक उपलब्धियां। अगर डैमोक्रेसी सिस्टम में ऐसा होता है तो डैमोक्रेसी लाने की क्या जरूरत थी क्योंकि डैमोक्रेसी में जो भी काम होता है वह कुलैक्टिव काम होता है। आज ये किसान के लिए कहते हैं कि हम सब कुछ किसान के लिए ही कर रहे हैं। आज किसान का लडका नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है क्योंकि उसकी हालत खराब होती जा रही है। बड़े आदमी का बच्चा तो नौकरी नहीं करेगा। आज किसान के बच्चे को कहीं पर नोकरी नहीं मिल रही है और अब तो वह यह सोचने लग गया है कि चलो कोई और नौकरी तो न सही, कहीं पर चपड़ासी की ही नौकरी मिल जाए तो भी बेहतर है। आज हमारे किसान की यह सोच हो गई है और इससे पता चलता है कि हमारा किसान आज कितना दुखी है। अब मैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा। इस बारे में आप मेरे इलाके को ही ले लें। आज चाहे किसी भी पोस्ट की भर्ती हो या चाहे पुलिस की भर्ती हो वहां पर 500—500 रुपए फार्म देने पड़ते हैं। अगर पुलिस

लाईन में छाती और कद नपवाने के लिए 500 रुपए देने पड़ेगें तो गरीब लोगों का क्या होगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि गरीब किसानो से और मजदूरों से इस तरह का इन्डायरैक्ट टैक्स नहीं लेना चाहिए। वे दे नहीं पाते हैं। सरकार कहती है कि चालीस हजार नौकरी दी गयीं हम मानते हैं दी गयी होंगी इनके पास आकड़े होंगे लेकिन हमारे पास भी यह आकड़े हैं कि किन–किन को नौकरी से निकाला गया है। एक तरफ तो सरकार नौकरी देती हे और दूसरी तरफ निकालती है। आज इम्पलाईज डी०ए० या इंक्रीमैन्ट नहीं मांगता बल्कि आज वह इसलिए चिंतित है कि कहीं कल को सरकार उसे नौकरी से निकालकर घर न भेज दें। अगर इसी तरह से चालीस हजार नौकरी दिखानी है तो सरकार जाने। इसी तरह से जो किसान और मजदूर गांवों मे रहते हैं वह केवल खेती पर ही निर्भर होते हैं और खेती को पानी ही अच्छा बनाता है। मेरा हल्का जुलाना है जोकि जीन्द जिले में आर्थिक स्थिति के हिसाब से सबसे कमजोर माना जाता है वह कमजोर इसीलिए माना जाता है क्योकि सभी लोग गांवो मे रहते हैं और गांवों में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है चाहे वह पीने का पानी हो या चाहे वह खेती में प्रयोग होने वाला पानी हो। हमारे यहां पर एक नहर है वह नहर सुन्दर ब्रान्च कहलाती है। इसमें से कई माईनर निकाले गये हैं।

श्री सभापतिः शेर सिंह जी, आर्थिक स्थिति के बारे में शायद आपकी पार्टी के मैम्बर्ज की एक राय नहीं हे।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंहः एज ए हरियाणा निवासी मैं चाहूंगा कि जिस जगह पर भी यह कमी है वहां पर उनको दी जाए। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि जहां पर कमी है तो उनको भी न दी जाए। जिसकी भी न्यायोचित मांग है वह उसको दी जानी चाहिए। यही मेरा एक नारा है। (विघ्न) मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। जिस तरह से नौकरी दी जाती है उसमें देखा जाता है कि वह किसका लड़का है, कहां का रहने वाला है और किस पार्टी का लड़का है। अगर इस आधार पर हम नौकरी देंगे तो यह हमारी डैमोक्रेसी के ऊपर एक लानत है। जब कोई सरकार बन जाती है तो वह किसी एक पार्टी की सरकार न होकर सभी की सरकार बन जाती है लेकिन इस सरकार में भेदभाव किया गया है और हमारे लोगों को नौकारियों के मामले में वंचित रखा गया है। मेरे पास इसके ऐग्जाम्पल हैं। सर, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा। बिजली जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। आज किसान को पानी की जरूरत है। परमात्मा कब बरसेगा कब नहीं यह तो वही जाने लेकिन मैं अपने हल्के की बात बताना चाहूंगा। हमारे एरिया में नीचे के पानी की बहुत कमी है इसलिए हमारे यहां के किसान को पानी के लिए केवल नहर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। नहरों में पूरा पानी नहीं मिलता है। जो रजवाह लगाये गये हैं उनकी सतह ऊपर लगायी गयी है इसलिए अगर आधी नहरें चलें तो रजवाहे बंद रहेंगे। किसान चाहता है कि जो उनके मोगे हैं वह नहर की सतह के ऊपर लगाए जाएं ताकि उनको एरा पानी

मिल सके। नहर मैं जो मोहरिया लगायी गयी हैं वह तो खुली चलती हें शायद किसान को उस की जरूरत नहीं है लेकिन रजवाहो पर जो शटर्ज लगाये गये हैं उसके कारण उनको पूरा पानी नहीं मिलता इसलिए मैं चाहता हूं कि जो यह व्यवस्था की गयी है वह गलत है और इसको दूर किया जाए। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत या जब भी लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो वह अपने सभी कागज लेकर जाते हैं जब उनसे खालो को पक्का करने केलिए कहते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये पक्के कर दिए जाएंगे लेकिन अभी तक जुलाना हल्के में इस बारे में कार्यवाही नहीं हुई है। राजवाहो में जो पानी टेल तक जाना चाहिए वह भी नहीं पहुंच पाता है। हमारे यहां पर किसी भी माईनर में टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। हो सकता है कि यह मेरे हल्के में ही नहीं बल्कि सभी जगहों पर न पहुंचा हो।

अब मैं शिक्षा के बारे मे भी कहना चाहूंगा। शिक्षा एक आधार है सभी समाज के उत्थान करने का लेकिन जिस तरह से टीचर्ज की सिलैमान की जाती है वह ठीक नहीं है। गार्बेज इन गार्बज आउट एक कहावत है। अगर टीचर थर्ड क्लास बनाया जाएगा तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। भाईबंदी से टीचर बनाए गए जिसके बारे में केस चल भी रहा है। ज्यादातर जो मैरिट होल्डर लड़के हैं वे बाहर रहते हैं नकल मारकर के लड़के सलैक्ट हो जाते हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

प्रो० सम्पत सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होने टीचर्ज के केस का जिक्र किया। पहली बात तो यह है कि वह केस अंडर इन्वैस्टीगेशन है, सब–जूडिस है दूसरी बात उसमें है कि जो ऐलीगेशन हैं आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं आपको पता होना चाहिए रिकुटमैंट आपने भी काफी की है। यह जितनी भी रिकुटमेंट हुई है यह इलाकेवाइज नहीं है, हल्केवाइज नहीं है, कोई जातपात वाली बात इसमें नहीं है। यह हन्ड्रेड परसैंट ऑन मेरिट की गई है। जे०बी०टी० टीचर्ज के केस में कोई मेरिट का ऐलीगेशन नहीं है वह तो साफ कहता है कि भर्ती जो हुई है उसमें हन्ड्रेड परसैंट ऑन मेरिट वाली लिस्ट उसमें जारी की है फिर ये कैसे कह रहे हैं कि मेरिट पर सलैक्ट नहीं किए गए हें थर्ड क्लास भर्ती किए गए हैं। वह तो पता लग जाएगा, आज मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने इस बात को माना है कि भर्ती हन्ड्रेड परसैंट ऑन मेरिट हुई है। इन्वैस्टीगेशन की बात जो कह रहा है तो जैसे किसी के खिलाफ ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐक्शन होता हे तो उसमें वह पौलिटिकल बातें डालकर अपना निजी फायदा उठाने के लिए उस आदमी ने जो कुछ कहा है उसकी प्रीपर इन्वेस्टीगेशन के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, टीचर्ज के तबादले किए गए हैं तबादले होने चाहिए इसमें कोई बात नहीं है लेकिन जिस तरीके से तबादले किए गए है वह गलत है। बच्चों

के पढ़ने का समय होता है ऐसे में ट्रांसफर नहीं होने चाहिएं। स्कूल सैशन शुदा होने से पहले–पहले ट्रांसफर हो जानी चाहिएं। मेरा निवेदन यह भी है कि जुलाना में लडकियों और लड़कों के लिए कालेज खोला जाए। वहां हम जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। जब तक कालेज नहीं खुलता है तब तक मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि जुलाना से एक बस रोहतक के लिए व एक बस जीन्द के लिए चलाई जाए जो कालेज के बच्चों को सुबह कालेज के समय पर ले जाए और शाम को वापस छोड़ दे। उस बस का प्रयोग सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होना चाहिए। वोकेशनल स्कूल खोले गए हैं लेकिन उनमें टीचर्ज नहीं हैं और बच्चे दो साल से पास हो रहे हैं बच्चे पास तो हो जाते हें लेकिन जब कभी कहीं ग्रेस्टिकली कंपीटीशन होता तो वे बच्चे उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं।

श्री अध्यक्ष: कौन से सब्जैक्ट के टीचर नहीं हैं ?

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह: सिलाई मशीन और टाइपिंग के टीचर्ज नहीं हैं। मैं लिखकर दे दूंगा। इसी प्रकार से मैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहना चाहूंगा। जुलाना में एक? ही कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर है उसकी जो बिल्डिंग है वह बाबा आदम के जमाने की बनी हुई है। जब वहां कोई पेशेंट बैठता है तो बैठते हुए डरता हे कि कहीं वह बिल्डिंग की छत गिर न जाए। मेरा अनुरोध है कि उसकी जल्दी से जल्दी नयी बिल्डिंग बनाई जाए

इसके अलावा वहां दवाई होती है तो डॉक्टर नहीं होता है डॉक्टर होता है तो दवाई नहीं होती है।

श्री अध्यक्षः आप वाईड अप करें। (विघन)

श्री बलवंत सिंह मायनाः स्पीकर सर, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। हम भी 1991 में विधान सभा में चुनकर आये थे और आज तक एक भी रिकार्ड दिखा दें कि माननीय ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार में जब मुख्यमंत्री जी खुद जनता के पास जाते हैं और जनता हम लोगों को चुनकर भेजती है उस वक्त गांव में जाते हैं तो उस समय माननीय सदस्य अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने क्यों नहीं रखते अगर उस समय रखें तो आज विधानसभा में इन्हें यह बात कहनी नहीं पड़े।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंहः स्पीकर महोदय, मेरे साथी ने ठीक फरमाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में गये थे ओर सिर्फ एक मिनट के लिए उनसे बात करने का समय मिला था। जनता ने उनसे पूछा कि बिजली के बिल हम कैसे भरेगे तो उन्होंने कहा कि अपनी जमीन बेचकर भरो। मुख्यमंत्री जी कितनी देर तक जनता की बात सुनते हैं। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कितनी देर तक गांव में रहते हैं और कितनी बात सुनते हैं यह आप सभी को मालूम है। (विघ्न) जहां तक पीने के पानी का जिक्र है। भीं–। की व्यवस्था ठीक नहीं है। कई जगह नहरों का वहीं पानी पीने के लिए टंकी में जाता है

जहां पर खुले खाले में औरते कपड़े धोती हैं और आदमी उस पानी में नहाते हैं उस पानी की सफाई का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी तब्बजो देने की जरूरत है। फसल बीमा का जिक्र आया कि फसलों का बीमा करने जा रहे हैं कब होगा लेकिन हमारे यहां सबसे ज्यादा फसल गेहूं और चावल की होती हैं लेकिन उनका जिक्र इसमें नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्षः आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं वह बताये।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंहः मेरा कहना है कि इन फसलों के बीमा के बारे में भी फसल बीमा योजना में इंक्लूड किया जाये। बाकी तो फसल कम ही बोई जाती हैं गेहूं, चावल और गन्ने को भी इस योजना में इंक्लूड किया जाये।

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए और माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि केन्द्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता मे सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग मे इस बारे में डिस्कशन किया गया था। केन्द्र की सरकार ने स्टेट का प्रीमियम 50 प्रतिशत रखा और 50 प्रतिशत प्रीमियम केन्द्र सरकार का था। हरियाणा सरकार और पंजाब की सरकार ने इस बात का विरोध किया और कहा कि हमें भी दूसरे राज्यों की कैटेगरी में मत डालिये जहां हर समय बाढ़ या सूखा या काल की समस्या

होती है हमारे यहां तो कभी कभी ऐसा होता है इसलिए हमारे प्रीमियम का हिस्सा आप 70 और 30 का रखिये। क्योंकि यह तो हमारे किसानों के लिए वायबल नहीं है। जिन फसलों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जैसे चना, तोरिया उनको इस पोलिसी में लाने के लिए मामला विचाराधीन है।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून और व्यवस्था के बारे में जिक्र आया। आकड़े दिये जाते हैं कि सरकार के पास हर साल के आकड़े होते हैं कि कितनी एफ०आई०आर० दर्ज की गई, कितना क्या घटता है यह तो पुलिस वालों के हाथ में होता है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के के इगराज गांव में वर्ष 2000 मे एक बी०एस०एफ० का जवान गायब हुआ था उसका आज तक कोई पता नहीं लगा। दूसरे इगराज गांव की लड़की जीन्द में शादी हुई थी उस लड़की के बारे में थाने में पिछले महीने एफ०आई०आर० दर्ज हुई थी लेकिन उसका आज तक कोई पता नहीं है। इसी तरह से मेरे हल्के के बीसन पुरा गांव जो शहर से काफी नजदीक है में 12 नवम्बर को एक नौजवान सुबह एक्सरसाईज करने के लिए घर से जाता है लेकिन आज तक उस लडके का पता नहीं चला कि वह कहां गया? उस लड़के के घरवाले मुख्यमंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं लेकिन उस लड़के का अब तक भी पता नहीं चला है। इसी तरह बीगपुर गांव का लड़का जो बीएससी पार्ट–1 में पढ़ता था वह कालुवा से चलता है और रात को जीन्द पहुंचता है लकिन घर पर

उसकी लाश जाती है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था इस तरह की हे। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सड़कों का जिक्र किया गया। सड़कों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि रोहतक से जीन्द वाली सडक की बहुत बुरी हालत है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस वर्ष बरसात बहुत हुई है जिसके कारण सड़क टूट गई। अध्यक्ष महोदय, इस बारे मेँ मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अच्छी बनी हुई सड़कें बरसात से नहीं टूटती। हमारे से ज्यादा तो दूसरी जगहों पर बरसात होती है। सड़कें बरसात में इसलिए टूटती हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ मैटीरियल सड़क बनाने में ठेकेदार जो यूज करते हैं वह बहुत घटिया होती है और मौजूदा सरकार के समय में यही हो रहा है। कारखानों के बारे में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार के समय में बहुत से कारखाने हमारे यहां से पलायन कर रहे हैं लेकिन इन्होंने बताया कि दो लाख लोगों को कारखाने मे नौकरी मिली है। इस बारे में मैं जानना चाहूंगा कि जिन दो लाख लोगों को नौकरी मिली है उनमें हरियाणा प्रदेश के कितने नौजवान हैं और बाहर के कितने हें। हमारे यहां जो कारखाने लगे हैं उनमें हमारे प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, बाहर के लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इस पर भी सरकार विचार करे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए अवसर दिया

इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्रीमति अनिता यादव (साल्हावास): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करती हूं। यह बडी ही विडम्बना की बात है कि आज हरियाणा सरकार कह रही है कि समय पर चुनाव होंगे और भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है। जब ये ऐसी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका आपस की सीटो का तालमेल नहीं हेता और आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जो बात हम रोज–रोज कहते थे कि सैंटर की सरकार किसान विरोधी है उनको यह बात अब समझ आ रही है। हरियाणा की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है ओर हरियाणा कृषि प्रधान स्टेट है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के किसानों को खतरा नहीं दुश्मन की तलवारों से, आज हरियाणा की जनता को खतरा है हरियाणा सरकार से। मैं कहना तो कुछ और चाहती थी लेकिन वे शब्द अनपार्लियामेंट्री हो जाते लेकिन मेरी बात आप सभी समझ गये हैं। आज चीफ मिनिस्टर को याद आ गया कि बी०जे०पी० एक खतरनाक पार्टी है। सुबह से हम इनकी आपस मे कुत्ते–बिल्ली वाली बात देख रहे थे। वह उसकी तरफ झांक रहा था तो वह उसकी तरफ देख रहा था जबकि हम पिछले

चार सालो से कह रहे थे कि सेन्ट्रल सरकार जो हे यह किसान विरोधी है लेकिन 'हमें तो अपनों ने ही मारा औरो में कहां दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ' हमने मुख्यमत्री को कई बार कहा था कि बी०जे०पी० किसी की भी नहीं है। यह बनियों की पार्टि है। यह हर तरह से राम नाम के नाम से वोट लेने वाली पार्टी है लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी की जो सरकार है उसने उस वक्त हमारी बात नहीं मानी लेकिन आज हमारी बात मान रहे हैं कि बी०जे०पी० व्यापार विरोधी पार्टी है लेकिन हरियाणा सरकार की समझ में हमारी बात आयी नहीं और आज जब सीटों के बंटवारे की बात आई तो कहते हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बनिया शब्द को कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्षः बनिया शब्द कोई गलत नहीं है, बनिया शब्द बढ़िया शब्द है।

श्रीमती अनिता यादवः स्पीकर साहब, मैं यह कह देती हूं कि बी०जे०पी० सेठ–साहूकारों की पार्टी है। अब जब आप लोगों का सीटो का बंटवारा नहीं हो रहा तो इस तरह की बातें कर रहे हें। (विघन) कांग्रेस पार्टी तो सभी वर्गों के लोगों की पार्टी है। यह किसान–मजदूरो की पार्टी है। हमने कई बार आपको बहुत समझाया लेकिन आप नहीं माने और कहने लगे कि बी०जे०पी० के

साथ जाएंगे। अब आप लोगों ने बी०जे०पी० के साथ जाकर स्वाद ले लिया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को गिनाने जा रही हूं। हरियाणा सरकार कहती है ओर समय–समय पर बहुत अच्छे लच्छेदार भाषण भी देती है कि हमने विकास के बहुत काम किए हैं। अब मैं अपने क्षेत्र साल्हावास की बात करने जा रही हूं। मैं कहना चाहती हूं कि लच्छेदार भाषणों से काम नहीं होते बल्कि काम करने से काम होते हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा की सड़कें ऐसी हैं कि उन पर हैलीकाप्टर दौड सकते हैं। मेरे हल्के की बहुत सारी सड़के आज भी टूटी हुई पड़ी हैं, चाहे तो आप इस बात की जांच करवा सकते हैं। मेरे हल्के की जो सड़कें खराब हैं मैं उनकी जानकारी आपको देना चाहती हूं। ये सडकें हैं कोसली से नवादा कोसली से झोरदा, कोसली से थुमाडखुशपुरा, कोसली से मातनहेल, अखेड़ी से मुण्डेहरा, जुडडी से लिलोड धिराय, सुधरना से वाया जसुआ सरसोली चोक, साल्हावास वाया तिलहडी नवादा, कोसली से सुरहेड़ी, कोसली से जुडडी। वहां पर पिछले साल से रोड़े पड़े हैं जबकि आप कह रहे हैं कि ये सड़कें बना दी गईं। पता नहीं लगता कि आपको किसने जानकारी दे दी कि ये सड़के बन गई। नाहड से सिरोली की 3 किलोमीटर की जो सड़क है उस पर रेत तो डाला हुआ लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। मैंने सरकार की ये उपलब्धियां बताई हैं कि कितनी अच्छी रोड यह सरकार बना रही है। मेरे क्षेत्र में ही नहीं सारे हरियाणा में ही ऐसी सड़कें बनायी जा रही हैं। सड़कों की हालत ऐसी है कि मैं

अपने हल्के से छह घण्टे में चण्डीगढ़ पहुंच पाती हूं। जो रोड टूट जाती हें उनकी रिपेयर भी कर देते हैं तो फिर से वे साथ ही साथ टूट जाती हैं। कानून व्यवस्था के बारे में भी यह सरकार कहती है कि हमने कानून व्यवस्था को सुधारा है और बहुत सारे कर्मचारी भर्ती किए हैं लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि आज से छह दिन पहले कोसली मण्डी से 140 चीनी की बोरी चोरी की गई थीं लेकिन उनका आज तक पता नहीं चला जबकि यह चोरी कोई एक मिनट में तो हुई नहीं होगी, उन बोरियों को ट्रक या ट्रैक्टर में भी लादा गया होगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज तक वह चोरी बरामद नहीं हुई। इसी प्रकार से आज से ठीक 15 दिन पहले नाहडु गांव में अढ़ाई लाख रुपये की चोरी हुई जिसमें जेवरात भी गए हें। इस केस में हरियाणा पुलिस ने 15 साल के एक बच्चे को पकड़ लिया। बाद मे पुलिस ने उस बच्चे को इतनी यातनाएं दी कि वह बच्चा अस्पताल में रहा। बच्चे की हालत को देखते हुए बाद में गावों के लोगों ने चोरी की तरफ ध्यान न दे करके सब सन्तोष कर लिया लेकिन आज तक भी वह चोरी बरामद नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, से मेरा तो यह मानना है कि प्रशासन और सरकार एक ही बात होती हे। मैने उनको यह बता दिया है कि किस के पास यह आईटम हैं और क्या मिसाल कह सकती हूं। इसी तरह से श्री एच०एस० सहगल का पिस्टल भी गया था जबकि मैंने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था। आपकी सरकार के रहते हुए इम्पलोईज का कुछ पैसा भी गया था, हीरों की दो–तीन अंगूठियां भी गई थी लेकिन

आज तक वह चोरियां बरामद नहीं हुई हैं, आज भी जीता जागता प्रमाण है और मैं आपको बता रही हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मारूति 800 कार पालावास थाने के अन्तर्गत छीनी गई थी लेकिन आज तक वह बरामद नहीं हुई है और ली एण्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हें। आपकी पुलिस इन सब वारदातों में इन्वाल्वड लोगों को पकड़ने मे नाकामयाब रही है। अध्यक्ष महोदय ....

16.00 बजे

श्री अध्यक्ष: अनीता जी, आप इस प्रकार की बात न करें। जो बात अभी इन्होंने कही है वह रिकार्ड न की जाए। (विघन)

श्रीमती अनीता यादव: स्पीकर साहब, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि चौटाला साहब जब पहले ओपोजीशन में थे तो कहा करते थे कि बिजली के बिल मत भरो (विघ्न) मैं अपने क्षेत्र की बात कह रही हूं बिजली के बिल भरने की जब बात आई तो अब यह कहते हैं कि जमीनें बेच कर पहले बिल भरो जब बिल भरोगे तभी कोई बात होगी। अध्यक्ष महोदय, 24 घण्टे में तदर्थ स्कीम के तहत बिजली के कनैक्शन्ज देने की बात कहते थे कि 24 घण्टे के अन्दर मैं तदर्थ स्कीम के तहत बिजली के कनैक्शन्ज दे दूंगा लेकिन आज वह स्कीम भी फेल हो गई है।

श्री अध्यक्षः 24 घण्टे के लिए तो चौधरी बंसी लाल जी कहा करते थे। 24 घण्टे में कनैकन्ज देने के लिए किसी ने नहीं कहा। यह बात पहले भी आ चुकी है इसलिए आप इसे रिपीट न करे। राव साहब भी इस बारे में बोल चुके हैं। अगर आपने कोई और बात कहनी है तो आप बोले।

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, श्य घण्टे की बात तो कही गई थी और वह आज तक पूरी नहीं हुई हे। 15– 15, 20–20 दिन तक क्यू में लगना पड़ता है। आई०जी० साहब की बात मेरे साथ भी आ गई। क्यू में लग कर और पैसे भर कर भी काम नहीं हो रहा है तो सरकार की यह उपलब्धियां है। (विघन) जब स्कूलों की बात आती है तो सरकार कहती है कि इनफर्मेशन टैक्नोलोजी की बात है और कम्पयूटर का जमाना है इतने स्कूल्ज हमने अपग्रेड कर दिए हैं। बीसला गांव मेरे क्षेत्र साल्हावास मे 5 कक्षा तक तथा रूढ़ियावास में तवी तक का स्कूल हो गया है लेकिन दो टीचर्ज 5वीं तक के स्कूल में है और दो ही टीचर्ज आठवीं तक के स्कूल में हैं। बिरोहड़ मे हमने कन्या महाविद्यालय मांग रखा है वह सारे नॉर्म्स पूरे करता है वह मिलना तो दूर रहा जमा दो का जो स्कूल है उसमे टीचर्ज हैं ही नहीं। सरकार से मेरा यह निवेदन है कि उसकी भी भरपाई करवा दें। इसी प्रकार से नाहड़ की बात है।

श्री अध्यक्षः अनीता जी, आप यह सारे स्कूलों की बात लिख कर दे दें।

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, अपने हल्के की समस्याएं तो उठानी ही पड़ेंगी। लोगों ने हमें चुन कर यहां पर भेजा है तो उनकी समस्याएं तो उठानी ही होंगी।

श्री अध्यक्षः अनीता जी, आप का समय समाप्त हो चुका है इसलिए अब आप आपनी सीट पर बैठें।

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय आप और दे दे। मैं अपने हल्के की कुछ बातों का जिक्र अवश्य करना चाहूंगी। नाहड़ में कन्या स्कूल है जो कि दस जमा दो के सारे नॉर्म्स पूरे करता है। नाहड कॉलेज में एक भी ईट नहीं लगी है। ललाड़ी में डी०ए०वी० कॉलेज हैं जिसका सरकारीकरण किया जाना है वह किया जाए। लिलोड़ में दस जमा दो का स्कूल होना चाहिए यह हमारी डिमाण्ड है। कन्दराली नवादा तथा रोहड़वास में 8वीं कक्षा तक के स्कूल्ज होने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पीने के पानी की समस्या का मैं जिक्र करना चाहती हूं। इन्होंने 40 लिटर पर डे पानी देने की बात कही है लेकिन हमारे लोग कड़वा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। (विघ्न) मातनपुर का रेलवे स्टेशन हे उस पर भी वही स्थिति बनी हुई हे।

श्री अध्यक्षः अनिता जी, आप बैठे, आपका समय समाप्त हो गया है। कैप्टन साहब, आप बोलें।

श्रीमती अनिता यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्यायंट है। पूरे हरियाणा में वैटनरी हास्पिटल्स हैं लेकिन मेरे

नाहड़ में कोई हास्पिटल नहीं है वहां पर डिस्पेंसरी ही है। डाक्टर साहब इस बारे में जवाब दें।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम० एल० रंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्या को बताना चाहूंगा कि मैं लोगों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभाग को देखता हूं और पशु चिकित्सा विभाग को मोहम्मद ईल्यास जी देखते हैं। अगर उनके विभाग से सम्बन्धित ये कुछ जानकारी चाहते हैं तो जब वे आ जाएंगे तो उन्हीं से पूछ ले और जहां तक मुझ से सम्बन्धित बात है तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि नाहड़ के बारे में जो इन्होंने हमसे कहा था उसके निर्माण बारे में काम बहुत तेजी से चल रहा है और जल्दी ही पूरा हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अनिता जी, आप बेठ जाएं, आपका समय समाप्त हो गया हैं अब कैप्टन साहब बोलेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रेवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने कल बोलना था लेकिन आप मुझे आज बोलने के लिए कह रहे हैं। आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। इस अभिभाषण में कृषि और स्वास्थ्य के बारे में छोड़ दिया गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, क्या किसी और सदस्य ने नहीं बोलना है 7 रूलिंग पार्टी की तरफ से क्या किसी

ने नहीं बोलना हे? आप उनको भी बोलने का मौका दें। हम भी उनको सुनना चाहते हैं। आप उनको भी बुलवाएं।

श्री अध्यक्षः हुडा जी, प्रस्ताव की शुरुआत ही सत्ता पक्ष की तरफ से हुई थी। बी०जे०पी० वाले बोलकर चले गए हैं। वे इस बारे में सीरियस ही नहीं हैं ओर जो सीरियस हैं वे यहां पर बैठे हुए हैं और हम उनको ही बुलवा रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बाजरे की खरीद की बात कही गई है। इसमें यह देखा गया है कि राजस्थान से इतना बाजरा आ गया कि हमारे किसानों का बाजरा ही नहीं खरीदा गया। जब यह बाजरा खरीदा गया था तो उस समय उसकी क्वालिटी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया था। मुझे तो लगता है कि यह सब राजस्थान में इलैक्शन की वजह से खरीद की गई थी। आज वह बाजरा आपके गोदामो में पड़ा सड़ रहा है। मुझे तो यह भी लगता हे कि सैन्टर की गवर्नमैंट भी उस बाजरे को नहीं खरीद पाएगी क्योंकि उस बाजरे की क्वालिटी ठीक नहीं है। इसके साथ मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि कहीं आपको अपने खजाने से ही उस बाजरे की पेमैन्ट न करनी पड जाए। दूसरे इन्होंने मन्त्रिमंडल के बारे में कहा है कि बहुत छोटा मंत्री मण्डल है यह सही है लेकिन यहां पर सरकार ए०डी०एफ०सी० की है।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब ने जो यह बात अभी कही है वह रिकार्ड न की जाए। कैप्टन साहब, आप गवर्नर एड्रैस पर ही बोलें। आप इस तरह की बात न करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जहां तक 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का सवाल है तो यहां पर कहा गया है कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में लोकल विधायक शामिल होते हैं और हम बार बार कहते रहे हैं कि जो एम०एल०एज० को ग्रांट देने की स्कीम है वह बाकायदा हर विधायक के पास होनी चाहिए ताकि वह अपने हल्के मे पैसा बांट सके। पिछले चार सालों के दौरान एक बार भी विपक्षी विधायक को .सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। वावैल में या दूसरी जगहों पर यह दरबार लगाया गया लेकिन रिवाडी हल्के में एक बार भी यह दरबार नहीं लगाया गया जबकि वहां की पंचायतें इस बारे में गुहार करती रहीं। इस तरह की जो भेदभाव की सरकार की नीति है वह ठीक नहीं है क्योंकि जब मुख्यमंत्री या मंत्री शपथ लेते हें तो वे कहते हैं कि वे सबके साथ बराबर का व्यवहार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज रिवाड़ी हल्के के साथ जिस तरह का भेदभाव किया जा रहा है वह आपके सामने हें। इसी तरह से जहां पर एस०वाई०एल० के बारे में कहा गया गि यह मामला सब जुडिश है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये चार साल तक एन०डी०ए० सरकार को स्पोर्ट क्यों करते रहे और क्या कारण था कि इराडी ट्रिब्यूनल के मैम्बर को आठ साल बाद

लगाया गया। चार साल निकल गये और अब जाकर वह मेम्बर लगा है। कब जाकर यह रिपोर्ट सबमिट होगी। हमारी सरकार को इस बारे मे प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए कि इराडी ट्रिब्यूनल को एक सीमित समय दिया जाए और उससे कहा जाए आप 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे दें ताकि पानी का बंटवारा जल्दी हो सके। एस०वाई०एल० का मामला तो केन्द्र के हाथ में है जब हमारी सरकार सैंटर में एन०डी०ए० सरकार को स्पोर्ट कर रही है तो इनको उनसे पूछना चाहिए था। आज मुख्यमंत्री जी ने बजट की आलोचना की है इसलिए इसको एस०वाई०एल० के बारे में भी केन्द्र की आलोचना करनी चाहिए थी ये क्यों उनको स्पोर्ट करते रहे?

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, यह सब जुडिश केस है इसलिए इस पर ज्यादा बात आपको नहीं कहनी चाहिए। हुड्डा साहब, आप सोनिया जी से कहकर इनको इस बारे में बताएं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, यह बात कहकर टाल देना कि यह मामला सब जुडिश है, ठीक नहीं है। एस०वाई०एल० दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा दै। पानी का बंटवारा न होने के कारण हमे पानी नहीं मिल पा रहा है। जो मौजूदा पानी हैं उसके सही बंटवारे के बारे में भी हमने कई बार काम रोको प्रस्ताव पेश किये और हमने कहा कि हमारे साथ न्याय किया जाए लेकिन हमारी बात नहीं मानी गयी। हमने देखा कि ढाई जिलों के लोग जहां पर ज्यादा पानी के कारण सेम की

समस्या आ रही हे और जहां पर सरकार करोड़ों रुपये इस समस्या को दूर करने पर खर्च कर रही है, उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। हमारे यहां पर दोहान पच्चीसी जैसे अनेक इलाके हैं जहां पर पानी काफी नीचे चला गया है लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरह से स्टैम्प डयूटी के बारे में कहा गया कि रूरल एरिया में साढ़े बारह प्रतिशत से कम करके 6 प्रतिशत और शहरों के अंदर साढ़े पन्द्रह प्रतिशत से कम करके आठ प्रतिशत कर दी लेकिन साथ ही साथ सरकार ने जमीन की वैल्यूएशन दुगनी कर दी। जिस जमीन की वैन्यू 6 लाख रुपये थी उसको बढ़ाकर आपने दुगना कर दिया। इस तरह से एक तरफ तो आप स्टैम्प डयूटी कम कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ आप जमीन की जो वैन्यू बढ़ा रहे हैं तो इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। इसी तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिएं वह नहीं मिल पा रही हैं खास तौर से कैंसर के बारे में मैने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश किया था लेकिन उसको आपने रिजैक्ट कर दिया। आज जो कैंसर के इतने केसिज हो रहे हैं तो आखिर इसके कारण क्या है। क्या कैमीकल की वजह से ऐसा हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि शहरों का सीवरेज का पानी ऐसे ही छोड दिया जाता है तो कहीं यह कैंसर की बीमारी इस वजह से भी तो नहीं हो रही है या जिस तरह से भैंसों को इंजैक्शन लगाकर दूध निकाला जाता है तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी यह बीमारी हो रही हो तो इस बारें में

बाकायदा रिसर्च की जरूरत है कि आज किन कारणों से कैंसर के केसिज बढ़ रहे हैं।

श्री धीरपाल सिंहः सर, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। कैप्टन साहब कई बार मुद्दे से अलग हटकर बात कह जाते हैं इन्होंने एक बात कहीं अगर ये उस बात का समर्थन करते जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है तब तो बात ठीक थी। शहर की जमीन की या खेती की जमीन की अगर कोई रजिस्ट्री होती है और यदि स्टैम्प डयूटी कम करने से आम आदमी को राहत मिलती है तो इनको इस बात के लिए प्रशंसा करनी चाहिए। सबने इसकी प्रशंसा की है। वे तो ये नहीं कह रहे हैं इन्होंने ये कहा कि एकदम से रेट डबल कर दिए। कैप्टन साहब. आखिर आप चाहते क्या हैं?

राव इन्द्रजीत सिंहः आपका क्या पाइंट ऑफ आर्डर है। अगर आप इस तरह के प्याइंट ऑफ आर्डर एलाऊ करते हैं तो जब चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे तो हम भी प्याइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े होंगे।

श्री धीरपाल सिंहः मैं यह कहना चाहता हूं कि कलैक्टर रेट संशोधित होते रहते हैं।

श्री अध्यक्षः राव साहब, वे मिनिस्टर हैं वे ऐक्सप्लेन कर सकते हैं।

राव इन्द्रजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से देख रहा हूं कि एक पार्टी के लोग बोले जा रहे हैं। ....

श्री अध्यक्षः राव साहब की अब कोई बात रिकार्ड न की जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि रेट कम कर दिए तो अच्छाई नहीं है। हमारा यह कहना है कि वैल्युऐशन तो न बढ़ाइए। अगर वैल्युशन साथ बढ़ा देंगे तो रेट घटाने का क्या लाभ है?

श्री धीरपाल सिंहः मैं यह कहना चाहता हूं कि कलैक्टर रेट संशोधित होते रहते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं उनमें से यदि किसी को कैंसर या टी०बी० हो जाती है तो उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार देती है। मेरा यह निवेदन कि हरियाणा में बी०पी०एल० के लोग हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हरिजन लोग हैं उनके लिए भी सरकार ऐसी कोई योजना बनाए। जिस तरह से देवी रक्षक स्कीम आपने निकाली है उसकी मैं सराहना करता हूं। इसी तरह से बी०पी०एल० के लोगों के लिए भी आप ऐसा कुछ करें तो अच्छा रहेगा। मेरे हल्के के गांवों में सड़कों की बहुत बुरी हालत है एक गांव मानक खुर्द है, एक बीकानेर है, एक गांव तुर्कियावास है इनमें सड़कों की इतनी बुरी हालत हे कि ऐसा लगता ही नहीं है कि सड़क पर खडे हैं

ऐसा लगता है कि गड्ढे में खड़े हैं इन सड्कों की मरम्मत करवाई जानी बहुत जरूरी है।

अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। दक्षिणी हरियाणा के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में एक रीजनल सैन्टर गुड़गांव में बनने वाला था उसका भी पता नहीं किन कारणों से काम रोक दिया गया है। अखबारों में यह भी दिया गया कि स्टे ले रखा है 1 सरकार अगर चाहे तो हमारे इलाके में यूनिवर्सिटी खोल सकती है कोई कन्या महाविद्यालय भी हमारे यहां नहीं हे। सैनिक स्कूल भी मातनहेल में खुल गया है। मैं यह कहता हूं कि मातनहेल में खुल गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। अच्छी बात है लेकिन पाली गोठड़ा में जहां पहले खुलना था वहां भी खुलना चाहिए। रिवाड़ी हल्के में पिछले चार साल में एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। इसके साथ–साथ जो जे०बी०टी० की कार्य प्रणाली है उसके बारे मे सुप्रीम कोर्ट ने सी०बी०आई० को इंक्वायरी दे दी है। वह पता लगाएंगे कि किस प्रकार से सलैक्यान करते हैं। यह जो हमारे ....

श्री अध्यक्षः यह जो मैम्बर्ज के बारे में बात कही गई है यह रिकार्ड न किया जाए।

केप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ जो हमारी एक्लीक्यूशन ऑफ लैंड हैं उसके बारे में मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां रेवाड़ी में कई गांव हैं

जैसे कौनसीवास, ढालियावास, पदियावास और दो तीन ढाणी हैं जिनमें कालोनियां काटने के बारे सैक्शन 4 लागू की जा रही है। जो गांव की फिरनिया थी, टैम्पल थे, गांव के स्कूल के ग्राउंड थे या क्रीमेशन ग्राउंड थे उनमें हुडा ने जमीन को एक्वायर कर लिया है यह कोई तरीका नहीं है जिन्होंने नये घर काफी पैसा लगाकर बनाये थे उनके घरों को भी इस एक्वायर की हुई जमीन में ले लिया। पिछले दिनों श्री अजय चौटाला जी सांसद वहां गये थे और काफी लोग उनसे मिले थे मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग विभाग वहां पर सैक्शन 4 और सैक्शन 6 को ध्यान में रखते हुए उन बने हुए मकानों को जिन पर इतनी भारी पूंजी लगाई है उनको तोड़ने की बात की जाती है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय, एक्सग्रेशिया स्कीम की बात की जाती है। इम्पलाईमैंट के बारे में पहले ऐसा नहीं होता था किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितो को तुरन्त नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब छोटे–छोटे बच्चों को 3 साल का वेट करके अढाई लाख दे दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अढाई लाख में क्या गुजारा चल सकता है। इस बारे में इस पोलिसी में सरकार को परिवर्तन करना चाहिए। इम्पलाई को कम से कम राहत देने के लिए उसके बच्चो को आगे जाकर नौकरी तो मिलनी ही चाहिए। इस बारे मे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो कर्मचारी सरकार ने रिट्रैंचमेंट किए थे जिनको सरकार ने घर भेज दिया कारपोरेशन के अगर उनको कहीं सरकारी कार्यालयों मे एडजस्ट कर सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा।

श्री अध्यक्षः आप वाईड अप कीजिए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, रोजगार के बारे में मेरा एक सुझाव है कि सरकार इम्पलायमेंट एक्सचेंज के माध्यम से जो नई नई औद्योगिक इकाइयां हमारे यहां पर आ रही हैं। उनमें रोजगार दिया जाये ताकि वहां लोकल नौजवानों को जिनकी जमीन एक्वायर हुई है उनको रोजगार दिया जा सके। जब भी कोई इकाई वहां पर लगती हे तो उनसे एन०ओ०सी० लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति की जमीन एक्वायर हुई है उसके बच्चा को उस इकाई मैं रोजगार अवश्य मिलेगा। क्योंकि हमारे यहां मानेसर और गढ़ी हरसरू में मैंने सुना है कि तीन हजार एकड़ जमीन किसानों की सरकार ने एक्वायर की है। इस मामले में खास तौर से दक्षिणी हरियाणा की जमीन कौड़ियों के भाव एक्वायर की है ओर जो पैसा उनको मिलता है उसे वे शादी ब्याह में खर्च कर देते हैं और बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं। आजकल नौकरी कान्ट्रैक्ट बेसिज पर दी जा रही है जिससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय जो फीस प्रोफैशनल कालेजिज और एल०एल०बी० की दुगुनी बढ़ा दी है उसको भी कम करना चाहिए क्योंकि इस तरह से तो गरीब आदमी का बच्चा तो कैसे पढ़ सकेगा। इसके साथ–साथ हमारे रेवाड़ी में म्युनिसिपल कमेटी ने तह बाजारी खत्म कर दी है जबकि पूरे प्रदेश में कहीं पर भी तह बाजारी खत्म नहीं की है। इसके बारे एक रैजोल्यूशन भी आया है मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर तह बाजारी

को खत्म न किया जाये क्योंकि इस कारण कई लोग बेरोजगार हो गये हैं। जो लोग 30–30 साल से तह बाजारी का काम कर रहे थे वे अब बेरोजगार हो गये हैं। इस बात को लेकर वहां पर लोगों में सरकार के प्रति बहुत नाराजगी है तह बाजारी को एक जगह पर हटाकर लोगों पर बहुत जुल्म किया है, इससे एक विशेष वर्ग पर जुल्म हुआ है। अध्यक्ष महोदय, रिवाडी मे यह कहकर तह बाजारी बंद कर दी गई कि वहां पर तो कांग्रेस के लोग हैं जो कि बहुत गलत बात है।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठें। आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार मै वैट प्रणाली लाग करके तीन हजार करोड़ रुपये के एकस्ट्रा टैक्स ले लिये इससे आम जनता पर असर पड़ रहा है।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है। प्लीज आप बैठें। कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाये। क्या हुड्डा साहब आप बोलना चाहेंगे?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में अब हमारी तरफ से कोई मेंबर नहीं बोलेगा। हमने कल की

तारीख में बोलने के लिए नाम दे रखा है और कल ही हमारे मैंबर बोलेंगे। बी०ए०सी० में भी यही बात हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, सरकार के मुखिया अपनी चेयर पर हैं नहीं, और आप आज ही विपक्ष के सभी सदस्यों को बुलाना चाहते हैं 1

श्री अध्यक्षः राव साहब, मैं तो सभी को बोलने का अवसर दे रहा हूं।

श्री भूपेन्द्र सिह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः हुड्डा जी ने जो अनपार्लियामेंट्री शब्द कहे हैं वे रिकार्ड न किए जाये। हुड्डा साहब यदि आपकी पार्टी के सदस्यों को बोलने का समय न दिया जाये तो आप कहते हैं कि समय नहीं दिया जाता और अब दे रहें हैं तो आप कह रहे हैं कि कल बोलेगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमने कल बोलने के लिए आपको लिखकर दे रखा है और हम कल ही बोलेगे।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि बी०ए०सी० में बात चली थी कि कल बोलेंगे। बी०ए०सी० की मीटिंग में हुड्डा साहब थे और आज के लिए डबल सिटिंग इसीलिए रखी गई थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा हो सके। विपक्ष के लिए अधिवेशन का समय

अपनी बात कहने का होता है और सत्ता पक्ष उसका जवाब देती है लेकिन विपक्षी साथी इस कीमती समय का फायदा ही नहीं उठाना चाहते। स्पीकर सर, अनूप विपक्ष के साथियों को बोलने का अवसर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कल बोलेगे, ठीक है यदि ये नहीं बोलना चाहते तो न बोलें लेकिन आप तो इनको पूरा समय दे रहे हें। स्पीकर सर, आप विपक्ष के साथियों को जितना समय बोलने के लिए दे रहे हैं इतना समय पहले कभी नहीं दिया गया यह तो हरियाणा की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा कि पहले इतना समय विपक्ष को बोलने के लिए दिया गया हो। अभी 4.30 बजे हैं और दो घंटे का हाउस का समय अभी शेष है। यदि विपक्ष देन साथी बोलना चाहें तो दो घंटे में बहुत बोल सकते हैं। स्पीकर सर, कल का समय तो रिप्लाई के लिए रखा हुआ है। यदि समय बचा तो ये कल बोल लेंगे।

केप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई हे। मैं बोलना चाहता हूं।

राव इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर सर, यह हम पहली बार देख रहे हे कि एक ही पार्टी के सभी सदस्यों को आप एक ही दिन बुला रहे हैं। दूसरी पार्टी के सदस्यो को नहीं बुला रहे। (शोर एवं व्यवधान) ऐसा उदाहरण हमने पिछले 18 साल में नहीं देखा कि एक ही पार्टी के सदस्यों को बुलाया जाये, वो भी तब जब सरकार के मुखिया सदन में उपस्थित न हो।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, विपक्ष के साथी चाहे बाहर स्टेज पर कुछ भी भाषण दें लेकिन आज ये विधान सभा के अंदर एक्सपोज हो गये हैं और बोलना नहीं चाहते और भाजपा वाले तो वाक–आउट ही करके चले गये। यदि इनको बोलने के लिए समय न दे तो फिर कहते हैं कि हमें समय नहीं दिया जा रहा। अब इनको समय दिया जा रहा है तो ये बोल नहीं रहे ओर अब कह रहे हैं केवल हमे ही टाईम क्यों दिया जा रहा है। जब आप समय दे रहे हैं तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर साहब, ...

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाये।

प्रो० सम्पत सिंहः आप इनको आज बोलने के लिए टाईम दे रहे हैं जबकि ये बोल नहीं रहे। कल सी०एम० साहब ने रिप्लाई देना है। बी०ए०सी० की मीटिंग में फैसला हो गया था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दो बैठकों में चर्चा होगी इसीलिए डबल सिटिंग रखी गई थी और यह भी फैसला हुआ था कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। हाउस ने बी०ए०सी० की रिपोर्ट मन्जूर की हुई है। अब यह बी०ए०सी० की रिपोर्ट न होकर हाउस का फैसला हो गया है। कल सैशन साढ़े नौ बजे होगा। एक घंटा क्वैश्चन आवर का निकल जायेगा ओर उस वक्त

साढ़े दस बजे जायेंगे। फिर किसी का कोई कालिंग अटैंशन मोशन या एडजर्नमेंट मोशन आदि आ सकता है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। आप सभी साथी जो बोले हैं उनका जवाब भी मुख्यमंत्री जो ने देना है। जवाब देने के लिए भी मुख्यमंत्री जी को डेढ़ दो घण्टा चाहिए जबकि हाउस की बैठक का समय डेढ़ बजे तक है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जितना समय आपको स्पीकर साहब की तरफ से दिया जा रहा है। उसका इस्तेमाल करते हुए आप बोलें और रचनात्मक सुझाव दे। आप बोलेंगे तो आपके जो अच्छे सुझाव होंगे उनको सरकार मानेगी और अच्छे सुझावों को देखते हुए सी०एम० साहब कोई भी घोषणा कर सकते हैं। आप अपनी ग्रिवेसिज यहां पर रखें, इसमें झिझक वाली कोई बात नहीं है। इसलिए मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि जितना समय स्पीकर साहब की तरफ से आपको दिया जा रहा है उसको इस्तेमाल करते हुए कृपया अवेल करे।

श्री अध्यक्ष: अब राव धर्मपाल जी बोलेंगे।

राव धर्मपाल (सोहना): अध्यक्ष महोदय, 9–4–2004 को राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण इस सदन में पढ़ कर सुनाया। उस पर चर्चा करने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के प्रथम पृष्ठ पर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में लिखा है कि प्रदेश के कृषक समुदाय के हितों की रक्षा करके तथा उन्हे कृषि विविधीकरण की ओर ले जाते हुए मेरी सरकार ने राज्य को एक

आधुनिक छवि उपलव्य करवाने मे सफलता प्राप्त की है। स्पीकर साहब, किसान एक ऐसे व्यक्ति की पहचान है जो ईमानदारी, नेक नीयत और मेहनती होता है। यहां पर किसानों के बारे में बहुत चर्चा हुई। इस लाईन पर मैं कुछ चर्चा इस सदन में करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब से देश आजाद हुआ है और उसके बाद से अब तक जितनी भी सरकारें आई उन सभी के समय मे किसानों की अनदेखी होती रही है। हरियाणा प्रदेश में जो भी मुख्य मन्त्री बने हैं जो भी सरकारें बनी हैं और उनका नेतृत्व मुख्य मन्त्री के रूप में किया वे किसान के बेटे ही होते रहे हैं। आज की जो मौजूदा सरकार है उसके मुख्य मन्त्री आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक किसान के बेटे हैं एक कृषक के बेटे हैं। लेकिन इन सब बातो के बावजूद भी किसान के हितों की अनदेखी होती रही है और आज भी हो रही है। स्पीकर सर, किसान को मिलता क्या है, पहनने के लिए साधारण से कपड़े, खाने के लिए साधारण सा खाना और इसके अलावा फटे हुए कपड़े पहन कर भी वह अपना गुजारा करता है। उसकी जो फसल पैदा होती है अगर उसकी लागत का हिसाब लगाते हें, आकड़ों के आधार पर उसकी लागत मूल्य के मुताबिक उसको फसल की कीमत का पैसा नहीं मिलता है। चाहे वह गन्ने की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो या दूसरी चीजों की फसल हो हर सरकार इस बात की अनदेखी करती रही है। अध्यक्ष महोदय, आज भी में सदन में कहना चाहता हूं कि हमारे शहरी विकास और ग्रामीण विकास

प्राधिकरण के मन्त्री चौधरी धीरपाल सिंह जी किसान, हैं, उनके साथ ही बैठे हमारे माननीय वित्त मन्त्री भी किसान हैं, स्पीकर साहब, आप भी किसान हैं, बोलने वाला भी किसान है और लोगों को भी देख लें तो करीब 80–85% लोग किसान बैठे दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है और दुख के साथ दुर्भाग्य भी है कि हम सब गोल मोल बात कह कर अपना वक्त निकाल कर चले जाते हैं। स्पीकर साहब, आज किसान के साथ बहुत बुरी हो रही है। गन्ने के भाव पर, कपास बाजरा और गेहूं के भाव पर बहुत चर्चा हुई लेकिन व्या कुछ नहीं। (विघ्न) मैं अपने इलाके के बारे में बताना चाहूंगा और सब जगहों पर यह बात लाग है। सरकार ने कोशिश की थी और हर सरकार करती है और कोशिश करनी भी चाहिए। बड़े बड़े उद्योग सारे हरियाणा प्रदेश में लग गए हैं, उन उद्योगों के माध्यम से सरकार को रैवैन्यू भी मिलेगा। और उनमें काम करने वाले लोगों को उनकी योग्यता के मुताबिक काम के बदले में पैसा भी मिलेगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाह रहा हूं कि किसान के साथ क्या हो रहा है। जब किसान की जमीन ऐक्वायर की जाती है उस जमीन को कौड़ियों के दाम पर लिया जाता है। हुड्डा का जिक्र भाई दान सिंह ने और भाईयों ने भी किया। मेरे हल्के में मानेसर पड़ता है। एक हजार एकड़ के करीब गांव की जमीन पहले ऐक्यायर की गई थी और उसका दाम तकरीबन 125/– रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से दिया गया था और जो प्लॉट बेचे गए वे 900 और 1300 रुपये प्रति वर्गगज के बीच बेचे गए।

एग्जैक्ट कीमत का मुझे पता नहीं हे लेकिन मेरे विचार से वह एक हजार रुपये प्रति वर्गगज से ऊपर ही बेचे गए हैं। अध्यक्ष महोदय, 6 लाख 55 हजार रुपये पर एकड़ दिया और सरकार ने जब उन प्लाटों को बेचा तो 55 या 60 लाख रुपये पर एकड़ मूल्य लिया। सरकार ने एच०एस०आई०डी०सी० के माध्यम से प्लाटों की ऐलोकेशन या बिक्री की हे। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आती मेरे भाई क्यों नहीं समझते, क्यों यह सरकार नहीं सोचती, क्यो नहीं मुख्य मन्त्री जी सोचते हैं जबकि वे खुद भी किसान हैं। अढाई सौ या तीन सौ रुपये उसमे डिवैल्पमैंट चार्जिज लगाकर और उस पर रख–रखाव लगा कर बाकी का जो पैसा है वह किसान को क्यों नहीं मिलता है। ये कैसे आकड़े बने हुए हैं और कौन सी नियमावली के तहत कैलकुलेशन करके, तैयार करके दरें निकाली जाती हैं यह हमारी समझ से बाहर की बात है। स्पीकर सर, हुड्डा के 250/– रुपए चार्जिज के अनुसार प्राईवेट कालोनाईजर पैसे जमा करवा कर लाईसैंस लेते हैं और प्लस उस पर रख–रखाव के चार्जिज लगाकर 300–400 रुपए भी लगाएं तो भी 600–700 रुपए गज बनते हैं। अब और अजीब बात सामने आ रही है कि 600 एकड़ जमीन पर आई०एम०पी० सैकेन्ड फेज बनाने जा रहा है और उसमे बांसकुसला, अलिया और ढाना जैसे 4–5 गांवों की जमीन जा रही है। इस वक्त सरकार ने जो रेटों पर व्याज लगा कर घोषणा की है वह 3 लाख मैट हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से की है, जबकि 5–6 साल पहले 6 लाख 55 हजार रुपए मिले थे। 4–5 सालो में महंगाई बढ़ी है जबकि इस

सरकार ने किसानों के रेट कम करके 3.40 कर दिए हैं। अगर सर, बराबर में कोई प्राईवेट आदमी जमीन लेकर सी०एल०यू० करवाता है तो उस आदमी से 20 लाख रुपये एकड़ के लिए जाते हैं और इसके साथ वह सी०एल०पी०यू० भी जमा करवाता है, फिर भी वह फायदे मे रहता है। मैं नहीं समझता कि हम किसान को मार के सिवाए कुछ और देते हैं। मुख्यमंत्री जी यहां पर नहीं हैं, वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मेरा आपसे अनुरोध हे कि इस बारे मे सर्वे करवाया जाए, इन आकड़ो की जांच की जाए और पिछली रीति को बदल कर किसानों को सुविधाएं दी जाएं। आज किसान को 20 प्रतिशत कैपिटल गेन लगता है, उसके बारे में किसान को कुछ पता नहीं होता है। जब किसानों का बैंकों में हुड्डा के थ्रू चौक आता है तो वे बैंक वालों के थ्रू किसान को नोटिस दे देते हैं कि 20 प्रतिशत कैपिटल गेन जमा करवाओ। अब 3 लाख 40 हजार में से 62 हजार रुपए केपिटल गेन चला गया तो उसके पास 2 लाख समथिंग ही बचते हैं। इस पैसे से किसान किसी दूसरी जगह पर जमीन खरीदना चाहेगा तो उसको उतने पैसों में जमीन नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही मैं इन्कम टैक्स के कैपिटल गेन के बारे में कहना चाहूंगा कि इन्कम टैक्स की धारा 54 (बी) के तहत इन्डविजुअल पर कैपिटल गेन नहीं लगता है, एच०यू०एफ० पर लगता है और किसान एच०यू०एफ० होता है क्योंकि किसान सामूहिक परिवार में रहता है, इका रहता है। आज भी गांवों में भाई भाई अलग अलग खेत जोतते हैं लेकिन उनकी जमीन इकट्ठी होती है, एक ही नाम पर होती है, वे बंटवारा नहीं करवाते हैं। में

सदन के सभी सदस्यों से और सदन के नेता जी से कहना चाहूंगा कि इन्कम टैक्स का महकमा हमारा नहीं होता है, यह भारत सरकार का महकमा है इसलिए सरकार की तरफ से इस बारे में सिफारिश करके भेजें कि जब किसान की जमीन बिकती है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगाना चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, राव धर्मपाल जी जो कह रहे हें, इस विषय में मैंने अखबार में पढ़ा था कि पिछले दिनों जो रियायतें दी गई उसमें उन्होंने केपिटल गेन माफ कर दिया है। हमने भी इसी विषय में धरना दिया था, प्रोटैस्ट किया था। अगर वह बात मान ली गई है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मानी गई है तो मैं भी गवर्नमैंट से रिक्वैस्ट करूंगा कि सरकार इस विषय में भारत सरकार से सिफारिश करे।

राव धर्मपालः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध हे कि सदन में सब मिलकर के चाहे वह किसी भी पार्टी का सदस्य है, यह सब के हित में है, किसानों के हितों से सम्बन्धित है, इस विषय में भारत सरकार से सिफारिश करनी चाहिए। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस आदमी की जमीन बिक जाती है और जमीन सस्ते भाव में गयी और वहां पर फेक्ट्री लग गयी ओर फैक्ट्री लगने के बाद जब किसान अपने बच्चे को लेकर वहां जाकर उनसे कहता है कि मई फैक्ट्री वालो मेरे बच्चे को अपने यहां पर नोकरी पर लगा लो तो उसकी बात कोई

नहीं सुनता। वह उनसे यह नहीं कहता कि इसको आप मेनेजर लगा लो या इसको आप कार प्रोवाइड कर दो बल्कि वह तो कहता है कि इसकी जो भी योग्यता है उसके अनुसार ही इसको नौकरी पर लगा लो। अध्यक्ष महोदय, मजदूरी पर लगने के लिए तो किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती लेकिन फैक्ट्री वाले लोकल आदमी को नहीं लगाते वे कहते हैं कि अगर हम इसको नौकरी पर लगा लेगे तो बाद में यह हम पर प्रभाव डालेगा और हमारे काम में रूकावट डालेगा जबकि हमारा बच्चा ऐसा नहीं करता क्योंकि जिसको भूख लगी हो तो वह पहले अपने पेट की सोचेगा और बाद में शराब की सोचेगा। इसलिए इस बारे में प्रावधान होना चाहिए कि जिसकी जमीन जाती है उसके परिवार के एक बच्चे को नोकरी दी जाएगी ताकि वह आदमी भुखमरी की तरफ न जाकर अपना गुजारा कर सके। अध्यक्ष महोदय, अभी एक साथी ने शायद मंत्री महोदय ने बताया था कि रजिस्ट्री की जो फीस है वह आधी कर दी गयी है इसमें कोई दो राय नहीं हे कि इससे सुविधा मिलेगी लेकिन इससे किसान को उतना फायदा नही होगा क्योकि किसान तो बेचने वाला है यह लाभ तो उसको होगा जो खरीदने वाला हे और खरीद वही सकता हे जिसके पास पैसा होगा।

श्री धीरपाल सिंहः राय साहब, कई मामलो में किसान एक दूसरे से खेती की जमीन खरीदते हैं इसलिए उनको भी फायदा होगा। यह केवल आपकी या आपके जिले की ही बात नही है बल्कि इंटीरियर रोहतक या दूसरी जगहों की भी बात है।

श्री अध्यक्षः राव साहब, जिसकी जमीन ऐक्यायर होती है वह उतने ही पैसे की जमीन तीन साल में बगैर स्टैम्प के खरीद सकता है। अगर वह जमीन खरीदेगा तो वह उसी पैसे से ही खरीदेगा और इसलिए उसे फायदा होगा। जिसकी जमीन ऐक्यायर होती है उसको स्टैम्प खरीदने की जरूरत नहीं होती।

प्रो० सम्पत सिंहः अगर स्टैम्प खरीदते हैं तो रजिस्ट्री फीस तो लगेगी लेकिन ऐक्यायर्ड जमीन पर नही लगेगी।

राव धर्मपालः अध्यक्ष महोदय, किसानों की बातें तो बहुत चल रही हैं लेकिन किसान तो हमेशा ही पिसता आया हे। चौधरी सर छोटूराम जी ने किसान के बारे में कहा था कि सारा दिन पच पच कर मर गया फिर भी भूखा सोया, जमींदार तेरा हाल देखकर मेरा जीवडा रोया। किसान तो जब से पैदा होता है और जब तक वह मरता है तो उसके फाटे सिलते नहीं। यह तो हम जैसे लोग जो दूसरे बराबर के धंधे करके अपना काम चला लेते हैं या जिनके परिवार में किसी को नौकरी पर लगने का मौका मिल जाता है चाहे वह कर्मचारी हो या चाहे वह अधिकारी हो तो उसकी हालत तो सुधर सकती है वरना खाली किसान तो सिर्फ भूखा मरने के लिए है। वह दूसरों का पेट भरता है और खुद भूखा रहता है।

श्री अध्यक्षः राव साहब, अब आप बैठें। (विघ्न)

राव धर्मपालः स्पीकर साहब, आप मुझे दो मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्षः राव साहब, आप सिर्फ एक मिनट में अपनी बात पूरी करें।

राव धर्मपालः अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा था कि सरकार को ऐसी पोलिसी बनानी चाहिए कि जिस घर की जमीन जाए उसके परिवार के बच्चे को एक रोजगार जरूर दिया जाएगा ताकि वह अपनी रोजी रोटी कमाकर खा ले। स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है कि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए विश्वविद्यालय ओर महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुड़गांव मे कालेज खोला है लेकिन स्पीकर सर, जो इस अभिभाषण में आकड़े दर्शाये गये हैं कि हर 111 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल, 1.44 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल, 1.75 किलोमीटर पर हाई स्कूल और 3.08 पर सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल हैं लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है पता नहीं कैसे आकडे तैयार किए जाते हैं। मेरे हल्के में 140 गांव हैं कोई छोटा है कोई बड़ा है लेकिन उसमें सिर्फ 10 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल हैं। स्कूलो की कमी होने की वजह से लड़कियों को बहुत समस्या हो जाती है और विशेषकर सर्दियों के दिनों में जब जल्दी अंधेरा हो जाता है तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता हे। में अनुरोध करूंगा कि यदि शिक्षा प्रणाली

को सुदृढ़ बनाना है तो स्कूलों का विस्तार किया जाना चाहिए। देहातों में अध्यापकों की भी काफी कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों एक स्कूल में गया। वहां गांव के लोग खडे होकर नारे लगा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मै बच्चे मैट्रिक की परीक्षा मे बैठे थे 41 के 41 फेल हो गए हैं। ख्यारपुर गाय हे, सोहना तहसील है, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव है आप चाहें तो बेशक इसकी जांच करा लीजिए और मिडिल मे उठ बच्चे थे जिनमे से 3–4 पास हो पाए। अगर ये हालत रहनी है तो फिर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने का क्या फायदा। शहरों में तो बहुत सी सुविधाएं हैं लेकिन गांव में तो किसान रहता है। मेरा अनुरोध है कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सड़को की जब बात आती है तो सभी साथी यह कहते हैं कि क्या धर्मपाल ने सड्कों का ठेका ले रखा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास आधुनिक कंप्यूट्राइज्ड मशीन हैं हमारे पास स्टोन क्रशर हें। किसान का बच्चा यदि आधुनिक मशीनों से काम करता है तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। गवर्नमैंट ने पिछले दिनो कुछ स्टेट हाइवेज को अपग्रेड किया था उस पर दिक्कत की बात ये है कि रोड बने 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए और अब उन पर टोल टैक्स लगा दिया गया है। गुड़गांव से निकलकर चाहे जयपुर जाएं तो टोल टैक्स देना पड़ता है, रिवाड़ी जाएं तो देना पड़ता है, पटौदी जाएं तो देना पड़ता है और सोहना जाएं तो भी देना पडता हे। इन्हीं सड़को पर हम पड़े हैं, इन्हीं पर चलते रहे हैं इन्हीं पर ट्रैक्टर चलाया हे इन्हीं पर ट्रैक्टर

से जोतते रहे हैं। जो ऐग्जिस्टिंग रोड्स हैं उन पर टोल टैक्स लगाने की क्या जरूरत पड़ी। जो चली हुई सड़कें हैं उन पर ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः यह टोल टैक्स केन्द्र सरकार का है या हरियाणा सरकार का है?

राव धर्मपालः सर, पटौदी रोड और सोहना रोड पर स्टेट गवर्नमैंट का हे।

श्री अध्यक्षः अच्छा सुझाव दिया है, अब आप बैठ जाएं।

राव धर्मपालः अध्यक्ष महोदय, जो ऐप्रोच रोड्ज हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए उन पर भी गांव का किसान चलता है। वैसे तो बहुत सारी बातें कहनी हैं लेकिन समयाभाव के कारण राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री रामकिशन फौजी (अनुसूचित जाति, बवानी खेडा): अध्यक्ष महोदय,आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इस अभिभाषण का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले स्पीकर सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो बाजरे का भाव 506 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इस सरकार ने दिया है वह पिछली बार केन्द्र की सरकार ने हरियाणा सरकार को कहा था कि आप हरियाणा में बाजरा 505 रुपये के हिसाब से खरीदें जो सब्सिडी होगी वह हम देंगे लेकिन हमारी सरकार ने

वह नहीं खरीदा। लेकिन इस साल बाजरा राजस्थान के इलैक्शन के लिए वोट मांगने के लिए खरीदा गया।

श्री अध्यक्षः लेकिन हरियाणा की मण्डियों में ही खरीदा गया है।

श्री रामकिशन फोजीः अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बाजरा हरियाणा की मण्डियों में लाया गया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के किसानों का बाजरा नहीं खरीदा गया बल्कि राजस्थान के लोगों का बाजरा खरीदा गया। लेकिन गरीब आदमी इससे मारा गया जो मजदूरी करता था वह बेचारा किसान मारा गया जिन्होने अपना बाजरा 250 रुपये के हिसाब से बेच दिया और उसे 500 रुपये के हिसाब से खरीदना पड़ा। इस तरह से मजदूर और किसान को कुछ नहीं मिला। स्पीकर सर, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय जब यह सरकार बनी तो इस सरकार ने पहले कहा था कि हम बिजली और पानी फ्री देंगे। मेरे पास इसकी सी०डी० है अगर आपको जरूरत हुई तो मैं यह सुना दूंगा। सी०एम० साहब ने कहा था कि अगर हमारी हरियाणा सरकार बनी तो बिजली पानी फ्री करूंगा। लेकिन सरकार के बनने के बाद उन्होंने कहा था कि बिजली पानी फ्री करने के लिए मैंने नहीं कहा था। अध्यक्ष महोदय, आज जो बिजली के इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाये गये हैं उनका मैंने पहले भी विधान सभा मे विरोध किया था कि ये गलत रीडिंग निकालते हैं। (विघ्न) इस सरकार के बनने के बाद बिजली के रेट कई बार बढाये गये हैं। यह सरकार

कहती है कि हम किसानों को टयूबवैल्ज के कनैक्शज देंगे लेकिन किसानों को टयूबवैल्ज के कनैक्शज नहीं मिल रहे हैं। किसानों ने डेढ़–डेढ़ लाख रुपये तक जमा करा रखे हें लेकिन उनको कनैक्शज नहीं मिल रहे हैं। आपको पता है कि गरीब किसान इतना पैसा कहां से लायेगा या तो अपनी जमीन को गिरवी रखेगा या फिर अपना मकान बेचेगा। (विघन) अध्यक्ष महोदय, बिजली की बहुत बुरी हालत है लोगों को चार घंटे भी बिजली नही मिलती। अब बच्चों की पढ़ाई का समय है। इस समय रात ओं बजे से लेकर 1 बजे तक बिजली मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी अखबारों मे रोज बयान देते हैं कि इस साल इतनी अधिक बिजली दी गई और पानीपत के सातवें और आठवें यूनिट बन रहे हैं। लेकिन हमें तो पता नहीं यह अधिक बिजली कहां दी गई है। मेरे हल्के के खानक, कंवारी, बालावास, भोजराज, दहंमा, गुजार, धमाना आदि गांवों में जिस दिन से यह सरकार आई है उस दिन से टेल पर पानी नहीं पहुंचा हे। सिंचाई की तो बात छोड़िये वहां पर लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर हमने कंवारी के अंदर धरना भी दिया था। अध्यक्ष महोदय, खानक के अंदर पीने के लिए 20 हजार रुपये का पानी हर रोज आता है यह नोट करने वाली बात हे और सरकार कह रही है कि पानी पूरा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी चाहे सुन्दर नहर हो या शिवानी माईनर हो उनमे पानी नहीं आ रहा। शिवानी के अंदर –एक बूस्टिंग स्टेशन है जिसके बारे में सरकार ने अपने कर्मचारियों को हुकम दिया कि वहां पर घरों में नल्के लगा दो और 600 रुपये ले

लो। वहां पर लोगो के घरों में नल्के लगा दिए गये और लोगों से 600 रुपये भी ले लिये लेकिन उन नल्कों में पानी नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गांव बडुसी के बाहर कुछ गुण्डो ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। हम डी०आई०जी० से मिले, एस०पी० से मिले लेकिन उसके असली कातिलो का अभी तक पता नहीं चला है। इस मामले को दबाने के लिए ऐसे ही किसी को पकड़ लिया असली कातिलों को नहीं पकड़ा गया है। यदि असली कातिलों को पकड़ लिया होता तो जो मोटरसाईकिल इस वारदात में यूज हुई थी, वह कहां हे? अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन से यह सरकार बनी है उस दिन से जो सड़कें बनाई गई हैं उनके अंदर तारकोल नाम की कोई चीज नहीं डाली गई और केवल रोड़ी से सड़क बना दी गई। यही कारण है कि एक महीने बाद सभी सड़कें टूट गई और उनकी हालत पहले से भी बुरी हो गई। यह इसलिए हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री जी सड़क बनाने का ठेका अपने वर्करों को देते रहे हैं। मेरे हल्के के अंदर भी तीन चार सड़के बनाई गई और एक महीने में वे टूट गई। जैसे बवानी खेड़ासे भिवानी तोशाम से भिवानी, हांसी से तोशाम आदि सड़कें टूट चुकी हैं इनकी पहले से भी बुरी हालत है। जब लोग मुख्यमंत्री जी को कहते हैं तो मुख्यमंत्री जी कह देते हैं आपके यहां तो 50 लाख रुपये खर्च हो गया जब लोग कहते हैं कि इतना पैसा खर्च नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी उसको कह देते

हैं कि तू बैठ जा तू हमारी पार्टी का नहीं हे। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के साथ भेदभाव हो रहा है।

17.00 बजे

सरदार जसविन्द्र सिंह संधुः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि बवानी खेड़ा में चौधरी भजन लाल जी के समय में 2. 58 लाख रुपये, चौधरी बंसी लाल जी के समय में 33.62 लाख रुपये सड़कों पर खर्च किए गए थे और हमारी सरकार के चार साल के कार्यकाल मे 2 करोड़, 29 लाख 30 हजार रुपये सड़को पर बवानी खेड़ा मे खर्च किए गए हैं जिसमें 50 लाख रुपये की नई सड़के बनाई गई हैं। यदि कोई गलत बात करे तो उसका कोई इलाज नहीं है।

श्री रामकिशन फौजीः मंत्री महोदय बताएं कि इन्होंने सिवानी शहर में एक नया पैसा लगवा कर कोई काम करवाया हो। अगर ये इस बात को साबित कर दें तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता हूं। ये बताएं कि सिवानी शहर में इन्होने पिछले चार सालों में कोई पैसा लगाया हो।

श्री अध्यक्षः प्लीज वाईड अप।

श्री रामकिशन फौजीः स्पीकर साहब, मैंने पिछले सैशन में भी सरकार से अनुरोध किया था कि पीले कार्ड जो गरीब लोगों को दिए गए हैं उनका सर्वे दुबारा करवाया जाये क्योकि

बहुत से लोग पीला कार्ड बनवाने से रह गए हैं। इसलिए मेरा अब फिर आपके माध्यम से निवेदन है कि पीले कार्ड बनाये जाने का पुनः सर्व करवाया जाये और जो सही मायनों में हकदार हैं उनको पीला कार्ड उपलब्ध करवाया जाये।

स्पीकर साहब, सरकार द्वारा 5100 रुपये कन्यादान के रूप में गरीब हरिजनों की बेटियों के लिए दिया जाता है लेकिन असल में इसका सही फायदा गांव के लोग उठा नहीं पाते। काफी सारे लोग तो अधिकारियों के चक्कर लगा कर रह जाते हैं लेकिन उनको पैसे नहीं मिल पाते। मैं कानून की बात को और संविधान की बात को मानता हूं कि 8 साल की आयु में लड़की की शादी होनी चाहिए। आप भी जमींदार हैं और हम भी गांव में रहते हैं। आप देखते हैं कि देहात के लोग अपनी लड़की की शादी 17 साल या साढ़े 17 साल में कर देते हें। इस उमर में शादी करने से उनको यह 5100 रुपये की राशि नहीं मिल पाती। मेरा निवेदन है कि इस स्कीम के बारे में सरकार को कुछ ढील देनी चाहिए।

श्री राम बीर सिंहः आन ए प्यायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि लड़की की शादी की आयु हमारे संविधान में 18 साल निश्चित की हुई है। क्या हम संविधान से हट कर कोई परम्परा डालेंगे। इनको अपनी बात कहते समय संविधान की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बात कह कर इन्हें लोगो को बरगलाना नहीं चाहिए।

श्री रामकिशन फौजीः स्पीकर साहब, संविधान के अन्दर तो यह भी हे कि किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ लूट खसोट नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये सारी बाते हमारे समाज में हो रही हें। स्पीकर साहब, ...

श्री अध्यक्षः जो ये कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। अब आप बैठ जाएं।

श्री रामकिशन फौजीः आप न बोलने दें तो यह अलग बात है।

श्री अध्यक्षः लड़की की शादी की आयु हमारे संविधान में 18 साल की है। जब चौधरी भजन लाल जी ने 18 साल से कम लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह किया था, उस वक्त भी यह मामला सदन मे आया था। उस वक्त भजन लाल जी ने क्या जवाब दिया था वह मैं कह नहीं सकता। इसलिए 18 साल की आयु का जो उल्लेख हमारे संविधान में है उसको हम कम नहीं कर सकते।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, प्रत्येक समाज के सामाजिक रीति–रिवाज हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। हर चीज को संवैधानिक रूप नहीं दे सकते। संविधान के अनुसार हम 18 साल से पहले लड़की की शादी हम कानूनी रूप से नहीं कर सकते और न ही सरकार इसको रिकोगनाईज कर सकती है। समाज में तो बहुत कुछ होता है। लोग जो ऐसी शादी करते हैं वे अपनी मजबूरी में करते हैं। हम लोगो में चेतना तो जागृत कर सकते हैं

कि हमें 16 साल या 17 साल या पीने 18 साल में लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। हम उनको कह सकते हैं कि आप छोटी आयु में शादी न करो बल्कि अपनी बच्ची को पढाये ताकि वह अपना कोई काम कर सके। यदि कोई एम०एल०ए० होकर ऐसी मांग करे कि 13 साल की आयु से पहले लड़की की शादी की जाये और वह रिकोगनाईज की जाये, तो यह ठीक नहीं होगा और न ही सरकार ऐसी शादियों को रिकोगनाईज करेगी।

श्री रामकिशन फौजी: स्पीकर साहब, ...

श्री अध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया है, इसलिए अब आप बैठ जाएं। रामकिशन जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: फौजी साहब, आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो गया है। (विघ्न) आपके बहुत सुझाव आ गए हैं, अब आप बैठें (विघन) इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न)

चौधरी जगजीत सिंह (दादरी): स्पीकर साहब, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है वह सरकार द्वारा तैयार किया गया था और वास्तविकता से बहुत परे था। इस अभिभाषण पर बोलने के लिए और प्रदेश की जो सही तस्वीर है

उसको उजागर करने के लिऐ मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं श्रम एवं रोजगार के विषय का जिक्र करना चाहूंगा। अभिभाषण में यह बताया गया है कि सरकार ने 39 हजार पद सृजित किए हैं और नौकरियां दी हैं लेकिन हमें लगता है कि ऐसा है नहीं क्योंकि पच्चीस हजार से ज्यादा आदमी नौकरी से निकाल भी दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों मदों पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। सरकार आपके द्वार के तहत 43 हजार विकास कार्य इस अभिभाषण के अन्दर दिए हुए हैं लेकिन वे विकास कार्य कौन से हैं इसका कोई जिक्र नहीं है। में समझता हूं कि अगर सड़क पर कोई पैच लगाया है तो उसको विकास का कार्य मान लिया और इस 43 हजार विकास कार्यों में शामिल कर लिया। इस प्रकार के कार्य अगर पिछली सरकार के कार्यों में शामिल कर लिए जाएं तो उन सरकारों के लाखों की संख्या में विकास कार्य हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर भी सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि वह 43 हजार विकास के कार्य कौन से हैं और किस किस जिले में हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के ऊपर भी सरकार ने काफी चर्चा की है और अभिभाषण में लिखा हुआ था। मैं दूसरी जगहों की बात तो नहीं कहूंगा क्योंकि एस०वाई०एल० और दूसरे सभी मुद्दों पर हमारे साथियों ने काफी कुछ कहा है मैं केवल भिवानी जिले के कुछ रजवाहे जो मेरे हल्के दादरी मे पड़ते हैं और जिनमें पिछले चार साल से पानी नहीं गया है, का जिक्र करना चाहूंगा।

स्पीकर साहब, मैं इन रजवाहों के नाम आपके सामने बताना चाहूंगा।

एक रामपुरा रजबाहा है इसमें पिछले चार साल से पानी नहीं गया है, दादरी का रजबाहा है, चरखी रजबाहा है और दूसरे अनेक रजबाहे हैं जिनकी टेल पर पिछले चार पांच साल से पानी नहीं गया है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि इन रजबाहों में पानी पहुंचाने की कृपा करे। स्पीकर सर, इस अभिभाषण में शिक्षा का भी बड़ा जिक्र था लेकिन पिछले दिनों हमारे जिले में एक बहुत बड़ा ऐजिटेशन चला। छात्रों की मर्जी के खिलाफ उनके अभिभावकों की मर्जी के खिलाफ भिवानी और जीन्द के कॉलेजों के छात्रों को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, सिरसा के साथ जोड़ दिया गया जब कि रोहतक में 50 किलोमीटर के अन्दर यूनिवर्सिटी पड़ती है और 50 किलोमीटर ही जीन्द के कॉलेज और भिवानी के कॉलेज पड़ते थे छात्र वहां पर आराम से जा सकते थे और अपने काम करवा सकते थे। इससे उनका टाईम और पैसा भी बचता था। स्पीकर सर, इसके बारे में वहां पर एक बहुत बड़ा ऐजिटेशन हुआ जिससे छात्रो की पढ़ाई खराब हुई लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई जबकि इसके कारण छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है। शिक्षा के अन्दर इस तरह की गलत परम्परा नहीं डालनी चाहिए और छात्रों को उनकी मर्जी के मुताबिक की यूनिवर्सिटी में रखना चाहिए। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्य श्री पूर्ण सिंह

डाबरा पदासीन हुए) सभापति महोदय, बिजली के बारे में मेरे साथियों ने काफी कुछ कहा है। इस प्रदेश के अन्दर शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जिसके अन्दर तारे न लटकती हों, खम्मों की शॉर्टेज है। आप किसी भी बिजली के सब डिवीजन में या एक्सीयन के ऑफिस में जाए तो एक ही जवाब मिलता है कि सरकार खम्भे नही खरीद रही है सरकार नई तारे नहीं दे रही हे इसलिए हम बिजली की नई डिवैल्पमैंट की बात नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर गांवों के अन्दर कई कई साल पुरानी बिजली की तारे लगी हुई हैं जोकि टूट गई हैं, नीचे लटक रही हैं। लोगों ने घरों के ऊपर छोटे छोटे डण्डे लगाकर उन तारों को बांध रखा है। रोजाना वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं और उन दुर्घटनाओं में घायल या मरने वालो को सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। इस बारे में भी सरकार को अभिभाषण में प्रावधान रखना चाहिए। इन्होंने सत्ता में आने से पहले लोगों को कहा था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम बिजली–पानी मुफ्त में देंगे। लेकिन आज इन्होने हर साल बिजली के रेट बढाए हैं और तो और पीने के पानी के रेट भी बढ़ाए हैं। चेयरमैन महोदय, पीने के पानी के बिल 3–4 महीनों से नहीं आ रहे थे, पहले बिल मे 630 रुपए बिल के आते थे लेकिन पिछले दिनो पानी के जो नए बिल आए हैं उसमें इन्होंने इस अमाउन्ट को बढ़ाकर 1036 रुपए कर दिया है। यह सब इन्होंने बिना बताए किया है। यहां पर सदन चल रहा है और वहां पर इन्होंने पीने के पानी के रेट बढ़ा दिए हैं।

चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को उन बढ़े हुऐ बिलों के रेटों को वापिस लेना चाहिए।

चेयरमैन महोदय, जहां तक उद्योग धन्धों का सवाल है तो इस बारे में भी सदन में प्लाटों का जिक्र किया गया था। पाई के अन्दर सब्जी और फल मण्डी बननी थी, उस मण्डी के प्लाट एच०एस०आई०डी०सी० द्वारा बेच दिए गए थे। अब फिर यह कहा गया है कि उसके बराबर में किसानों की जमीन एक्वायर करके नई सब्जी और फल मण्डी बनाई जाएगी। जबकि यह मण्डी पहले जो जमीन बेची गई है वही पर मण्डी बन सकती थी। पता नहीं क्या उस वक्त यह रिपोर्ट आई कि वहां पर फल और सब्जी मण्डी कामयाब नहीं होगी। अब ये दोबारा से वहां पर किसानों की जमीन एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। चेयरमैन महोदय, मेरे ख्याल से जो वे प्लाट बेचे गए थे वहां पर अभी कोई उद्योग नहीं लगे हैं। उन प्लाटों को प्रापर्टी डीलर्ज ने रेट बढ़ाने के लिए अपने पास रखा हुआ है। सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। चेयरमैन महोदय, हमारे देश में हरियाणा प्रदेश उद्योगों के मामले में नम्बर एक पर था और आज हालात यह है कि यहां पर टैक्सों के चलते हुए कई—कई सौ फैक्टरियां बंद हो रही हैं। जो फैक्टरियां थोड़ी बहुत चलती हैं, वह पता नहीं किस तरह से चल रही हैं। चेयरमैन महोदय, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं हे। सरकार को इस बारे में भी अभिभाषण में कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए।

चेयरमैन महोदय, इसके साथ ही अभिभाषण में भवन तथा सड़कों के बारे में काफी जिक्र किया गया है कि इससे प्रदेश में काफी नई सड़कें बनाई गई हैं। चेयरमैन महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि नई सड़कें बनी हैं। ज्यादातर सड़कों के लिए नाबार्ड से, एशियन डिवैल्पमैंट बैंक से और वर्ल्ड बैंक लोन पर पैसा लेकर सड़कों की मरम्मत हुई है, उनको चौड़ा किया गया है और उनकी फोर लेनिंग की गई हे।

श्री सभापतिः जगजीत सिंह जी, आप यह मानते हैं कि नई सड़के बनी हैं।

चौधरी जगजीत सिंहः चेयरमैन महोदय, यह बात तो मैं कह रहा हूं। चेयरमैन महोदय, ये जो नई सड़कें बनी थीं तो आधी सड़क बनने के बाद ही शुरू में टूटनी शूरू हो गई। मैं आपके माध्यम से सदन में उन सड़कों के नाम बताना चाहूंगा। ये सड़कें भिवानी से दादरी, लोहारू से बहादुरगढ़, दादरी से नारनौल हैं। चेयरमैन महोदय, तोशाम से हांसी सड़क जाती है यह कम्पलीट हो गई थी और कम्पलीट होने के बाद 2—3 महीने मे टूट गई थी। यह इसलिए टूटी थी क्योंकि वहां पर सब— स्टैण्डर्ड मैटिरियल प्रयोग हुआ था। वहां पर सब—स्टेण्डर्ड मैटिरियल क्यों प्रयोग द्या था, इसके क्या कारण हैं यह तो मुझे पता नहीं है। चेयरमैन महोदय, यह जांच का विषय है क्योंकि इन सड़कों को बनवाने के लिए पैसा लोन पर लिया गया था और वे सड़कें टूट गई हैं और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। चेयरमैन महोदय, इसी तरह से

छोटी छोटी एप्रोच रोडज हैं, जो पिछले 5–7 सालों से बहुत ही बुरी हालत में हैं। यहां तक कि हरियाणा रोडवेज की बसें भी उन सड़कों की बजाए दूसरी तरफ से जाने लग गई हैं। गांवों के लोग बसों के लिए तरस गए हैं। उनके पास दूसरी जगहों पर आने–जाने के लिए दूसरे कोई साधन नहीं हैं। चेयरमैन महोदय, कागजों में तो बसें उन्हीं रूटस पर चल रही हैं लेकिन एक्चुअल मे वे बसें दूसरे रूटो पर चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भागी सरूपड़ होकर के बस दिल्ली जाती है तो उस रूट पर सड़क टूट गई है इसलिए वह बस दूसरे रूट से होकर जाती है। उस टूटी हुई सड़क से तो लोग पैदल भी नहीं जाते हैं। इसी तरह से मोराला गांव है, वहां की सड़कें पानी खडा होने की वजह से बिलकुल टूट चुकी हैं। वहां पर भी आने जाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। इसी तरह से नामली गांव में भी आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहां पर लोग कई कई किलोमीटर दूर चलकर अपने कामों को करने के लिए जाते है।

चेयरमैन महोदय, इसी तरह से जन–स्वास्थ्य के बारे में भी जिक्र किया गया है कि 40 लीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रति दिन दिया जाएगा। पिछले दिनों 35 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से देने की बात थी। वर्ल्ड बैंक से इसके लिए काफी लोन लिया गया था कि 17 से 35 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से दिया जाएगा। अब इन्होंने नया आकड़ा दिया है कि 40 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन के

हिसाब से देंगे। जिसके लिए एशियन डिवैल्पमैन्ट बैंक और नाबार्ड से भी सहायता ली गयी है लेकिन मैं समझता हूं कि जिन गांवों में पानी नीचे खारा है उन गांवों की हालत बहुत बुरी है। मेरे हल्के के काफी गांव ऐसे हें जिनकी हालत ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वह। पर चालीस लीटर पानी देना तो दूर की बात है अगर आप उनको दस लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ही पानी दे दें तो इससे उनका काम चल सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि उन क्षेत्रो की तरफ भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। इसी तरह से नगर विकास की बात है। ज्यादातार शहरों में सिवरेज सिस्टम फेल हो गये हैं। हमारे दादरी हल्के में जहां से मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र सांसद हैं और जो मेरे ख्याल में महीने दो महीने में उस रोड से जाते हैं, वह रोहतक रोड पर जिसको वहां पर फव्वारा चौक भी बोला जाता है वहां पिछले आठ साल से सिवरेज का पानी नहीं हटा है। अब तो वहां पर बहुत ही बुरी हालत हो गयी है। इसलिए इसका भी जिक्र होना चाहिए था। अभी हमारे एक साथी ने बताया था कि पिछले दिनों मुख्यमत्री जी तोशाम गए थे उन्होने वहां पर एक जनसभा भी की थी। लोग उसमें आए और हल्के के काम लेकर उनके पास गए। हमे आश्चर्य इस बात का हुआ कि ....

श्री सभापतिः इनकी यह बात दर्ज न की जाए क्योंकि यह रिलेटेड नहीं है।

Shri Karan Singh Dalal : Sir, but this is not

unparliamentary.

Mr. Chairprson : It is not related to Governor's Address. Anybody can do whatever he wants to do out side the House. This matter is not related to the House. अगर कोई देना चाहता है तो दे सकता है it is not his concern लेकिन इनकी यह बात अभिभाषण से रिलेटेड नहीं है इसलिए यह कार्यवाही में रिकार्ड नहीं की गई है। I request the members, keep quite please. (विघन) कैप्टन साहब, बैठ जाए। Sangwan ji, please wind up.

चौधरी जगजीत सिंहः चेयरमैन सर, आपने न कर दी बात खत्म हो गयी। (विघन)

कैप्टन अजय सिंह यादवः सभापति महोदय, अभय सिंह जी बैठे बैठे जो चुभने वाली बात कह रहे हैं क्या यह ठीक है। अगर यह मुख्यमंत्री जी के लड़के हैं तो इसका मतलब यह है कि ये किसी को कुछ भी कहे?

Mr. Chairperson : Capt. Sahib, let him complete.
आप बैठ जाएं'।

श्री अभय सिंह चौटालाः सभापति जी, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। कैप्टन साहब ने जो बात कही है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि इन्होने पहले भी जब बोलना शुरू किया था तो इन्होंने कहा था कि यहां एक मुख्यमंत्री

और दो मंत्री हैं लेकिन इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि यहां पर 11 मंत्री हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः सभापति जी, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है।

श्री सभापतिः पहले उनको बात पूरी करने दें। अभी आप बैठ जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः मुझे इनको बताने की जरूरत नहीं है। यह शान की बात कर रहे हैं। (विघन)

श्री अभय सिंह चौटालाः सर, मैं इनको इसलिए बता रहा हूं कि इनको शायद तकलीफ यह होती होगी कि जिन कुर्सियों पर ये बैठा करते थे आज उन पर दूसरे लोग बैठे हैं। इन्होंने यह भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री का लड़का हूं। मैं केवल मुख्यमंत्री का लड़का ही नहीं हूं हालांकि मुख्यमंत्री का लड़का होने पर भी मुझे फख्र है लेकिन मुझे मेरे हल्के के लोगों ने सबसे ज्यादा मतों से जिताकर यहां भेजा है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः सभापति जी, आप इनकी लैंग्वेज देखें ये किस प्रकार बोल रहे हे।

श्री सभापतिः कैप्टन साहब, आप प्लीज बैठ जाइए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः सभापति महोदय, ये जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या यह अच्छी बात हे।

श्री अभय सिंह चौटालाः चेयरमैन सर, इनको बोलना गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर चाहिए इसके बजाय ये बात कहीं और ले जाकर किसी मैंबर पर खड़ी कर देते हैं। आपको सुझाव देने चाहिएं। सुझाव और इश्यू तो आपके पास हैं नहीं।

चौधरी जगजीत सिंहः स्वास्थ्य के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। में आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि चरखी दादरी में अस्पताल 3 किलोमीटर दूर बना दिया गया है वहां रिक्शा जाता है तो वह एक तरफ के 30–35 रुपये ले लेता है। वहां अस्पताल शिफ्ट करने का कोई औचित्य नहीं था। अगर सरकार नये अस्पताल को चलाना चाहती है तो उसको भी चलाए लेकिन पुराना सिविल अस्पताल भी चलता रहे तो अच्छा है। अगर कोई एक तरफ से 35 रुपये किराया लगाकर अस्पताल जाएगा तो इससे अच्छा तो वह 100 रुपये देकर प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखा लेगा। यह वहां के प्राइवेट डॉक्टरों की चाल है जिन्होंने यह कार्यवाही करवाई है। मेरे हल्के में एक खेल स्टेडियम की आधारशिला रखी गई थी। मैंने पिछली से पिछली बार कहा था तो मुझे आश्वासन मिला था कि खेल स्टेडियम बन जाएगा लेकिन वहां पर अब तक एक पत्थर भी नहीं लगा। उस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसके अलावा दादरी तहसील के अंदर जितने पहाड़ हैं उन सब पहाड़ों से निकलते ही नाके लगाए हैं वे सब असामाजिक तत्व हैं ओर 20–20 लोग वहां बैठे रहते हैं और वे पैसे लेते हैं व 140 रुपये की एक रसीद देते हैं व एक ट्रक माल

जाता है वह सारा येस। दो नंबर में जाता है और इससे सरकार को चूना लगता है। वे पैसे भी छीन लेते हैं जो वहां की लोकल पुलिस है वह भी मिली रहती है।

श्री सभापतिः आप इस विषय में लिखकर दे दीजिए। कैप्टन साहब, आपकी सीरियसनैस देखिए। How many members of your party are sitting in the House? You are not serious about the House. This is the seriousness of your party about the House.

Shri Karan Singh Dalal : Now, let me speak Sir.

श्री सभापतिः अब बिसला जी बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लबगढ़): चेयरमैन सर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। काश हमारे सभी सम्मानित सदस्य और विशेषकर जो सीनियर नेता हैं सभी पार्टियों के, जिन्होंने महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है जैसे जो मुख्यमंत्री हे या केन्द्र में भी महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। अगर वे इस समय हाऊस में होते तो बहुत अच्छी बात होती। मुझे हैरानगी है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की अगर हम सभी साथी चार लाईन भी पूरी पढ़ लें तो हम पूर्ण रूप से अवगत हो जायेंगे कि हमें इस अधिवेशन में किन मुद्दों को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ बोलना है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष

के पहले सत्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं तथा अपनी शुभकामनायें देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि आशा भी है कि यह सत्र हरियाणावासियों के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर रचनात्मक विचार–विमर्श को समर्पित होगा। बहुत दु ः ख के साथ कहना पड़ता है कि ठीक है आज विपक्ष के जो साथी हैं वे विपक्ष के विचारों को सम्बोधित कर रहे हें। इनकी भूमिका को भी आज कम नहीं औक सकते हैं। इस सदन की सार्थकता से पता चल जाता है कि अगर हरियाणा की जो गम्भीर चुनौतियां हैं और ऐसी समस्याएं हैं जिनको यहां सीनियर साथी बोलते हुए अपने विचार रखें और अपने सुझाव दें तो मैं समझता हूं कि हमारे ज्यादातर साथी गम्भीर नहो हैं इनमे मैं भी अपने आपको जोड़ता हूं। जो एयर कंडीशन कोठियों में, एयर कंडीशन कारों में रहने वाला वर्ग है आज प्रदेश के अन्दर उन वर्गो से उन समस्याओं से अनभिज्ञ हैं उस पर चर्चा करना और उनको गम्भीरता से नहीं अपना पा रहे हैं यह हमारी बहुत बड़ी फेलियोर है। चेयरपर्सन महोदय, आज दो करोड़ 22 लाख की आबादी हमारे प्रदेश की है और 80 लाख नौजवान हैं जो 18 साल की ऐज के बीच में हैं। हम सभी जानते हैं आज जो भयंकर बेरोजगारी है और जनसंख्या का जो विस्फोट हो चुका है अब तक किसी भी सम्मानित साथी ने जिनका मैं सम्मान करता हूं चौधरी भजन लाल जी, चौधरी हुड्डा, राव इन्द्रजीत सिंह जी जो पुराने साथी हैं? 1977 से इस सदन के सदस्य रहे हैं। हमारे अपने जिले के श्री कृष्ण

पाल गुर्जर किसी भी सदस्य ने इन समस्याओं के बारे अपने सुझाव नहीं रखे हैं। इसलिए हम सबको जो गम्भीर समस्याएं हैं उनकी तरफ भी अपने विचार रखने चाहिएं कि क्या पोलिसी होनी चाहिए अपने सुझाव देने चाहिएं ताकि जो रूलिंग पार्टी हे, सदन के नेता हैं उनके सामने रखें और उन्हें इस बारे में मजबूर करें, उनके साथ बैठें और उन्हें बतायें कि हरियाणा के अस्तित्व के लिए यह पोलिसी बननी चाहिये। चेयरपर्सन महोदय, इस सदन में आने से पहले मैं अपने हल्के बल्लबगढ़ के सभी गांवों और शहरी कालोनियों में गया हूं। जो 16 साल से 25 साल का युवा वर्ग है दुर्भाग्य वश उसका हम लोगों से, नेतृत्व से और प्रशासन से धीरे–धीरे विश्वास उठ रहा है। वे समझते हैं कि आज उनकी रोजी रोटी के प्रति देश का जो नेतृत्व है उसमें हम सभी अपने आपको जोड़ते हैं गम्भीर नहीं है। मैं कई गांवों में गया। 500 के लगभग लोग चौपाल में आये इतनी भयंकर सर्दी में भी किसी के पास ओढ़ने के लिऐ कम्बल नहीं था इतनी भयंकर बेरोजगारी है। जो अब तक सदन का जो समय है हम सभी सम्मानित सदस्यो ने विचार रखे हैं लेकिन इन गम्भीर समस्याओं की तरफ विचार नहीं रखे हैं मैं समझता हूं यह हमारी एक बहुत बड़ी कमी है। सभापति महोदय, भारतीय संविधान में फैंडामंटल राईट्स और डायरेक्टिव प्रिन्सीपल्ज भी हैं उनमें सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मैंशन किया गया हे। हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है कि उसने अनेकों महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी नीतियां शुरू की हैं। जिनकी देश भर में सराहना ही नहीं की जा रही बल्कि अनेक

राज्यो द्वारा उनका अनुसरण किया जा रहा है। सभापति महोदय, हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की पहचान ऋषि–मुनियों, किसानों, वीरों की वजह से होती है। आज के दिन बेरोजगारी का मेन कारण जनसंख्या विस्फोट है और उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बड़ी ही गम्भीरता से लिया है और महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हें। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बार–बार हर जगह जाकर कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री मैं हूं आगे कोई और आयेगा उसके बाद कोई और आयेगा लेकिन कोई भी सभी को नौकरी नहीं दे सकता और हम भी पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। सुबह पांच बजे से लेकर रात आठ बजे तक हमारे पास सबसे ज्यादा नौकरी मांगने वाले ही आते हैं। एक सिपाही की भर्ती के लिए 10 हजार एप्लीकेशंज आती हैं यही कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय कृषि का डाईवर्सिफिकेशन कर रहे हें ताकि फलों, सब्जियो, हरबल और औषधि आदि की खेती की तरफ किसानों का ध्यान आकर्षित हो और गांव के जिन नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं मिले, कारखानों में नौकरी न मिले वे खेती करके अपना पेट पाल सकें। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी नीतियां बनाई हैं उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और सरकार की इन अच्छी नीतियों की वजह से गांव के नौजवान अपनी रोजी –रोटी कमा रहे हैं। सभापति महोदय, 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के बारे में सभी साथियों ने अपने–अपने विचार रखे

हैं। मैं समझता हूं कि इससे सारगर्भित और लाभकारी ओर कोई कदम नहीं हो सकता। सभापति महोदय, हमने कई जगह देखा है कि मुख्यमंत्री जी 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में जाते हैं और हमने अनुभव किया है कि इस बात के ऊपर कि यह गांव कहां है, किधर है, कौन लोग रहते हें यानि बिना किसी भेदभाव के सबको विकास कार्यों के लिए पैसे दिए हैं। ऐसी नीतियों का हमें विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी नीतियों से प्रदेश को न केवल विकास की नई दिशा मिली है बल्कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है। जिससे ग्रामीण विकास को प्राथमिकता, खिलाड़ियों को सम्मान, सैनिकों का सम्मान, बुजर्गों का सम्मान यानि हर वर्ग को सम्मान मिल रहा है और विकास हो रहा है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने वन, पर्यावरण, बिजली, पानी आदि के बारे में जो योजनाएं बनाई हैं वे किसी से छिपी हुई नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारा जिला फरीदाबाद स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी की देन है। जब मैं पहली बार विधायक बनकर आया था उस समय श्री गजराज बहादुर नागर ने, जो इस समय संसार में नहीं रहे और हमारे साथी दीपचन्द भाटिया जी ने यानि हम सब ने स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी से फरीदाबाद जिले की मांग की थी और स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने हमारी बात मानकर गुड़गांव को फाईबरकेट करके फरीदाबाद जिला बनाया था। उसके बाद 22–23 साल हो गये किसी ने इस जिले की तरफ ध्यान नहीं दिया। फरीदाबाद में डी०सी० आफिस, ए०डी०सी० आफिस और एस०पी०

आफिस कहां है किसी को नहीं पता। आज भी फरीदाबाद जिले का डी०सी० ए०डी०सी० या एस०पी० का अभी तक अपना आफिस नहीं है। जब हमने इस बारे में मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलवाया तो उन्होंने हमारी बात को बडे ध्यान से सुना। अब हमारे फरीदाबाद जिले में जिला स्तरीय सचिवालय सैक्टर– 12 में बनने जा रहा हे। जिस तेजी से वहां पर काम चल रहा है मैं समझ सकता हूं कि उस हिसाब से इस सचिवालय का काम दो महीने में खत्म हो जाना चाहिए। उस सचिवालय की बिल्डिंग ऐसी है जैसे हमारे इस चण्डीगढ़ स्थित सचिवालय की है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल्डिंग में और उस बिल्डिंग मे कोई अन्तर नजर नहीं आता। अधिकारियों के कार्यालय एक स्थान पर हों तो यह एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिऐ बहुत ही अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि हमारे साथियों को जो सरकार की कमजोरियां हैं उसके बारे में बताना चाहिए ताकि सरकार की तरफ से उनको दूर किया जा सके। अगर हमारा कोई साथी अच्छे काम के लिए सरकार का आभार व्यक्त नहीं करता तो में समझता हूं कि यह उसकी एक कमजोरी है। मैं सभी साथियों को फरीदाबाद जिले में आने का निमंत्रण देता हूं कि सरकार की तरफ से वहां पर क्या–क्या कार्य किए जा रहे हैं। फरीदाबाद में सैक्टर 12 के अन्दर हुडा द्वारा एक टाउन पार्क में शॉपिंग कम्पलैक्स बनाया जा रहा है। यह बनने के बाद मैं समझता हूं कि देश की राजधानी जो साथ ही है उससे भी बढ़िया सैंटर यहां पर बनेगा। इसी प्रकार से वही पर ट्रासपोर्ट नगर बनाया जा रहा है। वहां पर इस समय सारा ट्रांसपोर्ट सड़कों

में या पार्को में खडा रहता है। इस ट्रांसपोर्ट नगर के बनने से सारे वाहन वहां पर खड़े हो सकेंगे। मैं समझता हूं कि ट्रांसपोर्ट नगर भी एक महीने में शिफ्ट हो जायेगा। इसी प्रकार से हमारे वहां पर इलैक्ट्रो प्लेटिंग यूनिट्स की भी समस्या थी। ये यूनिट्स बहुत मात्रा में फरीदाबाद में हैं। इनमें जो मैटीरियल यूज होता है वह एक प्रकार का जहर होता है। गरीब मजदूर जो वहां पर रहते हैं। उनके लिए वह प्यायजन का काम करता है। यह क्लो प्यायजन का काम करता है। जिससे बाद मे स्लो डैथ हो जाती है। अब इस इलैक्ट्रो प्लेटिंग यूनिट को शहर के एक कोने में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके शिफ्ट होने से वहां की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे 4–5 जिले दिल्ली के नजदीक लगते हैं। वहां पर फलोटिग पापुलेशन की एक गम्भीर समस्या है। इसको अगर हम समय रहते रोक नहीं पाएंगे तो हरियाणा की पहचान ही खत्म हो जायेगी क्योंकि लाखों आदमी फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़ और सोनीपत में बहुत मात्रा मे जॉब के लिए आ रहे हैं। खासकर ये लोग यहां पर हरियाणा की तरक्की कै। देखकर आ रहे हैं। इस बारे मे मेरा निवेदन है कि इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाना चाहिए। हमने यह समस्या ग्रिवेंसिज कमेटी में मुख्यमंत्री जी के सामने उठायी थी कि इस फलोटिग पापुलेशन को रोकने के लिऐ कोई पालिसी बनायी जानी चाहिए। ताकि आने वाले समय मे हरियाणा के लिऐ कोई गम्भीर समस्या पैदा न हो।

चेयरमैन साहब, अब मैं आपके माध्यम से शिक्षा नीति के बारे में कहना चाहूंगा। मेरा इस बारे में सरकार को निवेदन है कि हमारी जो शिक्षा नीति है इसको चेंज किया जाना चाहिए। अगर किसी शिक्षा नीति के तहत हम अपने युवाओं में इमानदारी और राष्ट्रीय भावना पैदा न कर सके तो वह शिक्षा नीति किसी काम की नहीं है। यहां पर नैतिक वैल्यूज रैस्टोर होनी चाहिए। यह नैतिक वैल्युज की रैस्टोरेशन हमारी मौजूदा शिक्षा नीति मे न के बराबर हे। इसलिए इस बारे में मेरा निवेदन है कि हमारा जो पुराना वैदिक सिस्टम 5 हजार साल पुराना है, जिसमें वेद, उपनिषद, गीता आदि ग्रन्थ आते हैं और जो हमारे देश की एक सबसे बड़ी धरोहर सम्पत्ति हे उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनायी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में दुनिया की समस्त मानव जाति की सही मायनों में अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वह हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वही रक्षा कर सकती है। हमे अपने देश पर गर्व होना चाहिए और हम में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार हमारे सम्मानित सदस्य जो वरिष्ठ पदों पर रहे हैं डिस्कशन में ऐसे निम्न स्तर की बात कह जाते हैं जिससे समाज का ताना– बाना टूटता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं कि आदरणीय मुख्यमन्त्री जी की कार्यशैली बहुत ही प्रभावशाली है और वे आर्यसमाजी विचारधारा के हैं इसलिए जातिवाद अथवा नोकरियों में पक्षपात के आक्षेप लगना उन पर बिलकुल गलत बात है। यह बात ठीक है कि

सरकार के कामों में कुछ कमियां नजर आ सकती हैं और उन कमियों को उजागर करना चाहिए। और ज्यादातर केसों में वे अपनी कमियों को मान भी लेते हैं इसलिए इस प्रकार की कोई बोत नहीं होनी चाहिए। जिससे उन पर कोई आक्षेप लगे। चेयरमेन महोदय, रात के समय टी०वी० पर एक डिस्कशन आ रही थी। जिसमें उत्तर प्रदेश के चीफ सैक्रेटरी और गवर्नर रहे व्यक्ति भाग ले रहे थे। इस डिस्कशन में उन दोनों ने कहा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी और गम्भीर समस्या प्रशासन और राजनीति में कास्टिटस्ट सोच है। मैं तो यह कहता हूं कि यह आतंकवादियों से भी ज्यादा बुरी है। इस प्रकार की स्थिति हो गई कि एक ईमानदार आदमी राजनीति तथा नौकरी नहीं कर सकता है। वहां पर जा कर आप देख में कि वहां पर कितना बुरा हाल हो रहा है। जितना भी पैसा जाता है वह विकास कार्यों पर लगता नहीं है। अगर हम इसकी तुलना अपने प्रदेश से करते हैं तो हमारी स्थिति वहां से कहीं बेहतर नजर आती है। प्रदेश में अच्छी नीति हो, अच्छे कार्यक्रम हों और जिस पद पर हम हैं और जिस भी पार्टी में हम हैं, हमें अपना रचनात्मक रोल प्ले करना चाहिए। चेयरमैन साहब, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा वरना आप कहेंगे कि आप समय की पालना नहीं कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है मैं उसका समर्थन करते हुए यह बात कहना चाहूंगा तथा सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब भी समय मिलता है तो जो गम्भीर चुनौतियां हैं चाहे वह इन्फ्रास्ट्रक्चर की हैं चाहे वह

बेरोजगारी की हैं या पोपुलेशन ग्रोथ अथवा दूसरी चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करना चाहिए। आज युवाओं में ईमानदारी घट गई है। चेयरमैन साहब, यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 50 साल में ईमानदारी और राष्ट्रीय भावना का लोप हो गया है ओर यह समस्या आने वाली हे कि इस देश को कौन चलाएगा इसलिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भगवान साहय रावत (हथीन): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ करूं मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। (विघन) उन्होंने एक आवाहन किया है सरकार की नीतियों के प्रति हमें प्ररेणा देते हुए वस्तुस्थिति से हमें अवगत करवाया है। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में जैसे कि उनकी इस भूमिका में वर्णित है हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों और राजनीतिक निर्देशक सिद्धान्तों का जिक्र किया गया है। हमारी लोकप्रिय सरकार ने संवैधानिक नीति निर्देशक सिद्धान्तो में वर्णित सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए और मैं समझता हूं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सरकार की भूरी–भूरी प्रशंसा की है। (विघ्न)

वाक आऊट

श्री कर्ण सिंह दलालः चेयरमैन साहब, मैंने अभिभाषण पर बोलने के लिऐ अपना नाम भिजवाया था लेकिन मुझे अभी तक बोलने के लिए समय नहीं दिया गया है।

श्री सभापतिः दलाल साहब, आप अभी अपनी सीट पर बैठे। (विघ्न) आपको बोलने के लिए समय दिया जाएगा। (विघ्न) अगर आप भागेगे नहीं तो आपको बोलने का समय जरूर दिया जाएगा। (विघ्न) अगर आप बोलना चाहते हैं तो अपनी सीट पर बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अब समय तो बहुत ही थोड़ा रह गया है और मुझे बोलने का समय नहीं मिला हे और आप अपनी मनमानी कर रहे हैं ओर मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं वाकआउट करता हूं।

श्री सभापतिः मेरी मनमानी नहीं है। कल अभिभाषण पर रिप्लाई होगा और अभी काफी समय है और मैं आपको समय देने के लिए तैयार हूं। (विघ्न) यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप अपनी सीट पर बैठें। (विघन) अगर आप जाना चाहते हें तो जा सकते हैं। (विघन)

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इन्डिया के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से बहिर्गमन कर गए)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनारारम्भ)

18.00 बजे

श्री भगवान सहाय रावतः दलाल साहब, आप बैठिये। सभापति महोदय, ये मेरे पड़ौसी हैं मैं इनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं ये शायद इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं कम्पैरेटिव अध्ययन के पलवल क्षेत्र और पूर्ववर्ती सरकार का कुछ जिक्र करना चाहता था। आदरणीय चेयरमैन साहब, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जितने भी मूल बिन्दु हैं हरियाणा राज्य के विकास के लिए हैं उन सबका उल्लेख इसमें है। एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते किसान की फसल का उचित मूल्य देने का माननीय साथी विरोध कर रहे थे। मैं समझता हूं कि उन्हें विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए था। हरियाणा पहला प्रान्त हे जिस ने दूसरे प्रान्त के किसानों का खाद्यान खरीद करके रिकार्ड कायम किया है। ये किसानों के लिए आसू बहाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गर्व से और सामाजिक रूप से लोगों में जाकर कहा कि किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। केन्द्र सरकार की नीति के मुताबिक जो मिनीमम प्राईस होती है वह सभी राज्यों में एक समान होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशालकाय राज्य, राजस्थान जस विशालकाय राज्य हरियाणा के सामने कहीं पर नहीं टिक पाए। हरियाणा ने दूसरे पड़ौसी राज्यों के गेहूं और बाजरे की उचित कीमतें देकर उनकी आर्थिक स्थिति को कायम किया है। मैं राज्य सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा कि जब जब पडौसी राज्यों में कोई आर्थिक विपदा

आई, उड़ीसा में भूकम्प आया या गुजरात में कोई दूसरी त्रासदी हुई हो या राजस्थान में अकाल पड़ा हो, मैं समझता हूं कि इस सरकार ने वहां पर मदद देकर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जो दायित्व निभाया है वह इस सरकार के अलावा पहले की सरकारों में कभी भी किसी ने नहीं निभाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने पूरे हिन्दुस्तान में अपना नाम रोशन किया है। देश को आजाद हुए 56 साल हो गए हैं, इस सरकार ने उन बिन्दुओं पर ध्यान दिया, जिन पर ध्यान देना इस सरकार से पहले वाली सरकारों से अपेक्षा थी। हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अधिकांश समय राज किया है और उनकी जिम्मेवारी से वे बच नहीं सकते हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस सरकार ने थोड़े से समय मे उन मूल बिन्दुओं को टच किया है जिसका इस प्रदेश की जनता को बहुत टाईम से इन्तजार था। मैं विधायक बनने से पहले शिक्षक रहा हूं। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे और शिक्षा काह में मूल चूक प्रावधान करने थे जो कि उन्होंने नहीं किए। हरियाणा में, चाहे केन्द्र में और अन्य राज्यों में जिनमें ज्यादा समय राज कांग्रेस का रहा है, ने राष्ट्र की नीति के तहत भी शिक्षा नीति पर मैकाले पद्धति से हटकर के कोई भी उचित ध्यान नही दिया है। मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की सरकार ने यह काम किया है। हरियाणा आज पहला राज्य है जिसने प्रगति के लिए

पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करवाया हे और 6वीं कक्षा से कम्प्यूटर की एजुकेशन देनी शुरू की है तथा दूसरी आधुनिक टैकनीकल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया है। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा बजट का प्रतिशत हरियाणा राज्य शिक्षा पर खर्च कर रहा है। इसके अतिरिक्त चेयरमैन महोदय, मैं खेलों की नीति के बारे में कहना चाहूंगा। आदरणीय साथी विधायक भाई अभय सिंह चौटाला जी यहां पर उपस्थित हैं। अगर मैं उनकी प्रशंसा यहां पर ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में करूं तो मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में जहां युवाओं को मार्गदर्शन के स्थान पर शराब की तस्करी के लिए धकेला गया था वर्तमान में सरकार ने उन युवाओं को उनकी इच्छाओं के मुताविक उनका सर्वागीण विकास हो सके, उनको खेलों की तरफ डायवर्ट किया है। मैं समझता हूं कि आज से पहले इतने बड़े देश के नौजवान जब ओलम्पिक टूर्नामैंट में जाया करते थे तो उनकी झोली में कोई पदक नहीं होता था। आज हरियाणा के खिलाड़ियों को जब किसी भी स्तर पर खेलों का आयोजन होना होता है, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहन देने में हरियाणा की आज की सरकार अग्रणी रहती है। इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला और हमारे युवा साथी अभय सिंह चौटाला जी को जाता है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सरकारों से पहले हरियाणा की लड़कियों को नगद पारितोषिक देकर के उसमें अग्रणी स्थान लेकर के एक सराहनीय काम किया हे। मुझे इस बारे में याद दिलाते हुए कोई संकोच नहीं

हो रहा है कि पिछली सरकारों ने जो इस देश की युवा पीढ़ी, जो इस देश के उज्ज्वल भविष्य माने जाते हैं, को शराब की तस्करी और जमीनो पर कब्जे करने जैसे घृणत कार्यों की ओर धकेला था। हमारी सरकार ने उन युवाओं को सही मार्गदर्शन देकर के उनको सही राह पर डाला है। मैं कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकारों के वक्त में जो हरियाणा की रोडवेज की बसे जाती थी तो वै लोग उनमें से उतर कर दूसरी बसों में बैठ जाते थे ओर तो और हरियाणा की बसे ही सड़कों पर नहीं दिखती थीं। चेयरमैन महोदय, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री महोदय, ट्रांसपोर्ट विभाग को तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज हरियाणा की बसें देश में सबसे अच्छी बसें हैं और अच्छी क्वालिटी की बसें हैं। इन बसो में सवारियों को अच्छी सुविधाएं देकर हरियाणा रोडवेज सरकार को लाभ पहुंचा रही है। इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्रो की बात है मुझे अच्छी तरह से दस बारह साल पहले की बात याद है हरियाणा की सडकें इतनी जर्जर अवस्था में थीं कि जिसकी शब्दों में विवेचना या व्याख्या नहीं की जा सकती। लकिन आज की सरकार ने उन टूटी हुई सड़कों को ठीक करने की प्राथमिकता देकर एक आधारभूत ढांचा तैयार करने का काम किया है। आज हरियाणा की सड़कें दूसरे राज्यो से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। यही नहीं गांवों के विकास के लिए पहली बार एक समग्र नीति का निर्धारण किया गया। मेरे विपक्ष के साथी बताएं कि क्या 55 सालों मे उन्होंने सैद्धांतिक फैसला लिया कि गांवों की फिरनी को पक्का किया जाएगा, क्या उन्होने कभी यह फैसला

किया कि शमशान घाट जैसी जगहों पर जिन लोगों ने कब्जे कर लिए थे उनको उनसे मुक्त करवाया जाएगा? चेयरमैन सर, भारतवर्ष मे किसी भी सरकार का जो लोकप्रिय कदम उठाने के लिऐ दायित्व बनता है, किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी राजनैतिक पर्सनेलिटी का उस समुचित व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो दायित्व बनता है वैसे सारे कदम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की तरह किसी ने नहीं उठाए। मुझे यह कहते हुए फख्र हो रहा है कि जो घुन लगने वाली व्यवस्था थी जिसमें सारी चीजें ध्वस्त हो गयी थीं उस अवस्था में हमारे मुख्यमंत्री जी ने नाजायज कब्जे को हटवाने, बिजली की चोरी रोकने, नहर के पानी की चोरी रोकने और परीक्षाओं में नकल रोकने जैसे साहसिक कदम उठाकर उस व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया हे। जिस विदेशी पाश्चात्य जगत को हम जानते हैं और जिस पाश्चात्य जगह की व्यवस्था की, वहां के जैसे अवसर उपलब्ध करवाने की हम प्रशंसा करते हैं। उन्होंने बाहर के भ्रमण से लाभ उठाकर और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे उपायों को ध्यान में रखकर सड़कों पर होने वाले ऐक्सीडैंटस पर तुरंत सहायता उपलब्ध करवाकर और सड़कों के ट्रैफिक में मदद देकर जिस तरह से वहां पर सहायता उपलव्य करवायी है उससे हम उन्हें तुरंत उपचार उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया है। उन सामाजिक और राजनैतिक कुरीतियों और राजनैतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर काम किया है जिसकी इस देश को और सारे प्रदेशों को आवश्यकता

थी। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान जैसे पड़ौसी राज्य में जहां नकल नहीं है लेकिन हरियाणा में यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मैडीकल एजुकेशन और स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए किसी सरकार ने क्या कभी नोर्म्ज तय किए थे? इसके अलावा भी और कई चीजें ऐसी हैं कि उनके बारे में हमारे विपक्षी माननीय साथी बताएं। चेयरमैन महोदय, मंत्रिमंडल को छोटा करने के बारे में देश की संसद तो अब कानून पास कर रही है लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक छोटा मंत्रिमंडल रखकर जोकि दस फीसदी से भी कम है जबकि उसमें एक दो संख्या और हो सकती थी, एक रिकार्ड कायम किया, एक मिसाल कायम की। भारत की संसद ने तो बाद मे कानून पास किया। इसी तरह से महिलाओं के आरक्षण का बिल वर्षो से भारतीय संसद में कानून बनने के लिए लटकता रहा है लेकिन क्या किसी राजनैतिक दल ने ईमानदारी से इस पर काम किया है क्या विपक्षी साथियो की पार्टी ने इस पर काम किया है? लेकिन हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री ने कानून बनने से पहले ही विधानसभा के चुनावो में और पार्लियामैंट के चुनावों में महिलाओं को एक तिहाई सीट्स देने की घोषणा हरियाणा में लागू की है। क्या विपक्ष के साथी मुझे बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शुगर प्रोडक्शन का गढ़ माना जाता है, चीनी उत्पादन का गढ़ माना जाता है या किसी और राज्य सरकार ने अपनी सारी शूगर मिलों की तरफ जो किसानों का पैसा उधार बकाया है, उसकी पूर्ण रूप से पैमेंट की है? लेकिन हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य दिया गया है और किसान

का कोई भी पैसा किसी शुगर मिल की तरफ बकाया नहीं है। क्या हमारे विपक्षी साथी बता पाएंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिऐ जितने आयुर्वेदिक पद्धति के होस्पीटल्ज को बढ़ावा देने का काम, नयी पी०एच०सी० खोलने का काम या स्वास्थ्य की दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं ऐसे काम किसी ओर राज्य सरकार ने किए हैं ? मैं समझता हूं कि हमारे जो विकसित देश हैं उनमें मैडीकल एजुकेशन फ्री है, वहां पर चिकित्सा सुविधाएं फ्री हैं और वहां की सड़कें ठीक हैं इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमारे यहां पर भी सरकार द्वारा विकास की गति को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पाश्चात्य विकसित जगत की जो अच्छाईया थीं उनको ग्रहण करने के बाद हरियाणा में लाग करने का काम किया। हम विधायको को भी जिनको हमारे विरोधी लोग सैर सपाटे का नाम देते थे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विदेशों मे जाने का अवसर उपलब्ध करवाया। हमने या हमारे परिवार ने सारे जीवन में कभी पैरिस का नाम तो सुना होगा लेकिन पैरिस को नहीं देखा होगा। हमने अमरीका के बारे में यह तो सुना होगा कि वह पाताल में बसता है लेकिन देखा नही होगा। जब अमरीका, पैरिस और हालैंड जाकर हमने वहां की सडकों को देखा, वहां के विकास को देखा तो मैं समझता हूं कि हमारे ज्ञान में बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि हुई है वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है उनमें जो आधारभूत तथ्य हमें नजर आए उनका क्रियान्वयन हरियाणा सरकार

यहां कर रही है। वहां पर हर आदमी को आजादी, हर आदमी को अवसर उपलब्ध करवाना ओर एक सिस्टम को मजबूत करना, इन तीनों गुणो का समावेश हरियाणा सरकार की नीतियों में भी हो रहा है। जहां पर आर्थिक सम्पन्नता की बात आती है मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर हमें वहां जाकर के मिला, वहां पता लगा कि वहां के लोग अमीर क्यों हैं। एक सभ्य नागरिक के दिमाग में ऐसे दो प्रश्न बार–बार कौंधते हैं उसका जवाब हमें वहां जाकर मिला कि वहां किसी सभ्य नागरिक के पास एक मिनट का वक्त भी बर्बाद करने के लिए नहीं है। वहां पर लोग अपना काम स्वयं करते हैं। वहां के लोगों को सर्विस लेने के लिए पेमेन्ट करने की आदत है और मुख्यमंत्री जी ने वहां से प्रेरणा लेकर के स्वयं अपने ऊपर ढाला है आज भी मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों का उद्‌घाटन करने के लिए गए हुए हैं। क्या हरियाणा के अलावा कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो 24 घंटे मे से रात को तारीख बदलकर सोते हें और आज की नौजवान पीढ़ी से भी पहले जाग जाते हैं आज भी मुख्यमंत्री जी सैशन के मध्य में जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए आपके बीच मे दोबारा से उपलब्ध हैं विपक्ष को इन चीजो कैं लिए प्रशंसा करनी चाहिए थी लेकिन दुर्भाग्यवश, द्वेषवश उन्हांने सरकार की नीतियों की सराहना की बजाय उसे व्यक्तिगत आलोचना और व्यक्तिगत ईर्ष्या का विषय बना लिया। चेयरमैन महोदय इसके अतिरिक्त लडकियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रेजुएशन लैवल पर फ्री एजुकेशन देने की व्यवस्था सरकार ने की है। उसके लिए सरकार की जितनी सराहना की जाए, कम है। मेरे मेवात जैसे

पिछड़े क्षेत्र में चौधरी देवी लाल जी के समय में 15 करोड़ रुपये की लागत से पोलिटैक्निक कालेज स्थापित किया गया था जहां कि लडकियों को पढ़ाना स्वप्न की बात हो सकती थी। 12 वर्ष बाद जब दोबारा सरकार आई तो तब तक वहां कम्प्यूटर जैसी मॉडर्न कोर्सिज को बंद कर दिया था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक जरा से अनुरोध करने से उन्होंने 40 सैट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एजुकेशन के और मैट सैट डिप्लोमा इन इलैक्ट्रोनिक्स और 20 सैट फार्मेसी के डिप्लोमा के स्वीकृत करके मेवात क्षेत्र को बढ़ावा दिया। मुझे आज भी वह तारीख याद है मुख्यमंत्री जी 26 तारीख को रैनीवैल योजना का शुभारंभ करने के लिए फरीदाबाद में उपस्थित थे मैं संयोगवश और सौभाग्यवश उनके साथ गाडी मे बैठा था और हम आगरा कैनाल से गुजर रहे थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया कि रैनीवैल योजना से हमारे मेवात जैसे प्यासे इलाके की प्यास बुझाई जा सकती है क्या आप इस पर अनुकम्पा करके पेयजल व्यवस्था के सुधार के लिए कोई उपाय बनाएंगे। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो घंटे के बाद खाना खाने से पहले ही उन्होंने कमिश्नर को बुलाया, डी०सी० को बुलाया और उन्होंने एस०ई० व अन्य विभागीय अधिकारियो को निर्देश दिए कि आप जाइए और यमुना के पास जाकर हमें फिजिबल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आपको जानकर खुशी होगी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मात्र दो दिन के बाद 28 तारीख को 425 करोड़ रुपये की योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात एरिया के लिए स्वीकृत कर दी

थी। एक दो दिन के अंदर 425 करोड़ का इन्वैस्टमैंट करने के लिए जो सरकार तत्पर है, सक्षम है इससे ज्यादा विकास की मिसाल ओर क्या मिलेगी। आज जहां लोग स्वार्थवश ईद जैसे मौके पर पार्टियां करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने लोगों के घरों में जाकर दरवाजे पर जाकर इफ्तार की पार्टी आयोजित की, इसको भी लोगों ने रंग देने की कोशिश की। आज भी वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के वहां गांव की गलियों, नालियों, वहां की फिरनी, स्कूल के कमरे लोगों की यह सब मांगें आज बढ़ रही हैं आज लोग ईट के गलियारों से संतुष्ट नहीं हैं। हरियाणा के लोगों में आज यह मैसेज गया है कि वर्तमान सरकार में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे जो मांगोगे वही देंगे। आज वे कंकरीट की गलियां मांगकर अपने आपको सौभाग्यशाली समझते हैं कोई काम ऐसा नहीं है जहां पर 50 लाख या एक करोड़ रुपये की व्यवस्था न की गई हो। हमारे विपक्षी साथी कह सकते हैं कि वह केन्द्र का पैसा है। मैं पूछना चाहूंगा कि केन्द्र तो सदा से है इनके टाइम में भी केन्द्र था क्या तब केवल राज्य था। आज आदरणीय कृषि मंत्री जी ने आपको हर समस्या पर व्यक्तिगत रूप से बताया है कि आपके हल्के में इतने किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ है। इतनी सड़कों की आपकी रिपेयर की गई हैं इन सबका ज्ञान सभी माननीय सदस्यों को है लेकिन वे स्वीकारते नहीं हैं। इन सब बातों को दृष्टिगत रख करके मैं तीन–चार बातो पर अपने विचार रखते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा था मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जो एक रचनात्मक भूमिका

एक विधायक की और एक जन प्रतिनिधि की होती हे उसमें जो मेरा एक विश्लेषण है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन नीतियों में और उनका समावेश किया तो भारतवर्ष में हरियाणा एक अग्रिम राजा विकसित राज्य होगा और मैं समह हूं कि भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन सकेगा। आज मुझे इस बात की खुशी हुई है कि हरियाणा विधानसभा के मध्य में सन् 1987 में जब चौधरी देवीलाल जी के आशीर्वाद से और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से मुझे विधान सभा में आने का मौका मिला उस दिन की पहली शपथ के संस्मरण में मुझे याद बै और आज मैं उसकी पुनरावृत्ति करना चाहूंगा। मैंने कहा था जैसे विधायक बनने से पहले हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है। मैं भी विधायक बनने से पहले अध्यापक था। उस समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट अपने हल्के में कराई थी। मैं समझता हूं कि देश के राजनेता ने भीष्म पितामह ने राजनीति को जो नई दिशा दी थी वहां ग्रामीण अंचल मे जन्मे व्यक्ति ने एक आजादी की लहर उन लोगों में बहाई थी। उन लोगों ने फाईव स्टार होटल में उस धोती वाले आदमी को बैठा दिया था। उन्होंने लोगों से पुलिस के भय को निकाल दिया था। उन्होंने 24 घण्टे बिजली देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था और उन्होंने देश के लोकतन्त्र को लोक लाज से चल रहा है इस तरह की डैमोक्रेसी की परिभाषा की थी। हमने चौधरी साहब से अनुरोध किया। लेकिन विरोधी लोगों ने शायद इस पर भी एतराज किया था। आज मुझे धन्यवाद वर्तमान सरकार को देते हुए खुशी हो रही है

कि उन्होंने सिरसा मे चौधरी देवीलाल जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। आज उसमें महिला कालेज और दूसरे कालेजिज को सम्बद्ध किया है। मैंने चार संस्थाओ को मजबूत करने का अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है। मैं वह बात कह रहा हूं जो 56वें साल पर देश के राष्ट्रपति महोदय ने देश का आह्वान करते हुए कही है। मैं उस बात की पुनरावृत्ति करना चाहूंगा। 1987 और 2000 के प्रथम अभिभाषण के समय अपनी स्पीच पर बोलने का मौका चौधरी साहब ने मुझे दिया था उस वक्त भी मैंने अपनी बात रिपीट की थी कि इस सोसायटी की प्रथम इकाई मनुष्य है। Person is the first unit of this society. चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चाईना का हो, चाहे अमेरिका से हो, पाकिस्तानी हो या इग्लैंड का रहने वाला हो। इस सारी सामाजिक व्यवस्था की प्रथम इकाई मनुष्य हे और जब तक मनुष्य का सर्वागीण विकास नहीं किया जायेगा तब तक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता और वह केवल मात्र शिक्षा से ही हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के कुशासन ने देश के कर्णधारों ने 55–56 साल में इस प्रथम इकाई को कभी विकास की तरफ से देखा ही नहीं। जिस तरह से सारी समस्याओं की बात करते हैं, कानून–व्यवस्था की बात करते हैं, कानून को तोड़ने की बात करते हैं, अपराधी की मनोवृत्ति की बात करते हैं। कोई भी गवर्नमैंट कैसे संभव है उसके लिए अपराध प्रवृत्ति को एक दिन में या 24 घण्टे में रोक दे। क्योंकि प्रवृत्ति तो आज 56 साल के बाद में

उनके कुसंस्कारों के कारण वह युवा पीढ़ी का मार्ग दर्शन सही नहीं कर पाये उसी का परिणाम है कि आज अछुतोद्वार के महान प्रेणेता श्री महात्मा गांधी और महर्षि दयानन्द जैसे महापुरुषों के प्रयास के बावजूद भी आज वह बीमारी हमारी समाज में है। क्रप्शन हमारे समाज में आज भी है इन सबके सुधार के लिए आदमी को सुधरना होगा। जैसा कि प्रथम गुरू मां है। आज चौधरी साहब ने उस स्त्री को समझा है। उस कन्या की शिक्षा को बढ़ावा दिया है। उस गरीब कन्या के कन्यादान में 5100 रुपये की राशि दी है और बी०ए० तक की उसकी शिक्षा फ्री की है और उस घर को आर्थिक स्वरूप प्रदान करने के लिए कमेरा वर्ग के परिवार का कोई आदमी मर जाता है तो उस परिवार को एक लाख रुपये की राशि प्रदान करने की व्यवस्था की है। इसलिए आज 55 साल में वह मां, वह मातृशक्ति असहाय पुरुष प्रधान समाज में उपेक्षित इस तरह की है मैं समझता हूं कि प्रेरणा देने में सक्षम नहीं है। उसके बाद दूसरा गुरु जो है जो हमारे वेद शास्त्रों में पिता है क्या पिता की भूमिका निभाने के लिए हम और आप सक्षम हैं। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी का दोष नहीं है हम लोग उनको वह संस्कार नहीं दे पाये इसलिए लोगों में चोरी, डकैती, शराब और शार्टकट लाईफ जीने के आयाम पैदा हो गये हैं। आज ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में भाई अभय सिंह चौटाला ने खेल जैसी नीति को बढ़ावा देकर युवाओं को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया है। शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस बारे में मैं चौटाला साहब से मिला और कहा कि चौटाला साहब

आज आप हरियाणा के शक्तिशाली व्यक्ति हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नकल और नाजायज कब्जे जैसी बुराई पर आज आप प्रहार कर सकते हैं। आदरणीय चौटाला साहब ने तुरन्त हमारे डी०सी० को कहा कि सबसे पहले इस विधायक के गांव से नाजायज कब्जे हटाये जायें। मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और आदरणीय चौटाला साहब से कहा कि यदि इस बुराई को आप दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं तो उसको बीच में बन्द करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात का श्रेय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा कि पाश्चात्य जगत की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बिजली की चोरी, पानी की चोरी, नाजायज कब्जे और नकल जैसी बीमारी से लडने के लिए चौटाला साहब ने विशेष कदम उठाये। नकल रोकने से शिक्षा और शिक्षक पर अच्छा असर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए क्योकि शिक्षा तीसरा गुरु होती है। चौथा गुरु हम और आप जैसे लोगों से बनी सोसायटी होती है। इन सभी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए चौटाला साहब ने उचित कदम उठाये हैं। इसलिए मैं चौटाला साहब को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सभी माननीय साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन मे पढ़ा है उसको पास किया जाये और आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 11th February, 2004.

***18.12 hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 11th February, 2004.)